● वर्ष-4
● अंक-155
रायपुर, शुक्रवार
07 फरवरी 2025
● पृष्ठ-8
● मूल्य-3 रु.

।। संगच्छध्वम् संवदध्वम् ।।

समाचार पचीसा

राजनीति का जनपक्षकार

पेज-6» प्राकृतिक सौंदर्य के लिए....

कांग्रेस ने संविधान की धज्जियां उड़ाईः मोदी

आजादी के बाद संविधान निर्माताओं की भावनाओं को नष्ट कर देने का आरोप

नईदिल्ली। संविधान को लेकर जारी सियासत के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कांग्रेस पर जमकर वार किया। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर अपना संबोधन देते हुए मोदी ने कहा कि हम आगे बढ़ते हुए अपने संविधान निर्माताओं से प्रेरणा ले रहे हैं। जो लोग समान नागरिक संहिता पर सवाल उठा रहे हैं उन्हें यह समझने की जरूरत है कि हम केवल अपने संविधान निर्माताओं की राह पर चल रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने आजादी के तुरंत बाद हमारे संविधान निर्माताओं के कार्यों और भावनाओं को नष्ट कर दिया था। स्वतंत्रता के बाद एक स्टॉप-गैप व्यवस्था के दौरान हमारे संविधान के लोकाचार का अपमान करते हुए, एक ऐसी सरकार द्वारा संशोधन किए गए थे जिसे देश के लोगों द्वारा नहीं चुना गया था।

मोदी ने कहा कि संविधान निर्माताओं का आदर करना चाहिए था, उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए थी। लेकिन, कांग्रेस ने आजादी के तुरंत बाद ही संविधान निर्माताओं की भावनाओं की धज्जियां उड़ा दी थी।,

उन्होंने कहा कि इस देश ने इमरजेंसी का दौर भी देखा है। संविधान को किस प्रकार कुचला गया, संविधान की स्पिरिट को सत्ता सुख के लिए किस प्रकार रौंदा गया था, ये देश जानता है। इमरजेंसी में प्रसिद्ध सिनेमा कलाकार देव आनंद जी से कहा गया कि वे सार्वजनिक रूप से इमरजेंसी का समर्थन करें। लेकिन देव आनंद जी ने इसके लिए इंकार कर दिया। इसलिए दूरदर्शन पर देव आनंद जी की सभी फिल्मों को प्रतिबंधित कर दिया गया। किशोर कुमार जी ने कांग्रेस के लिए गाना गाने से मना किया। इस एक गुनाह के लिए आकाशवाणी पर किशोर कुमार के सभी गानों को प्रतिबंधित कर दिया गया।

मोदी ने कहा कि आपातकाल में जॉर्ज फर्नांडिस समेत देश के अनेक महानुभावों को हथकड़ियां पहनाई गई थी, जंजीरों से बांधा गया था। संसद के सदस्य, देश के गणमान्य नेताओं को हथकड़ियों और जंजीरों से बांधा गया था। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के मुंह से संविधान शब्द शोभा नहीं देता। सत्ता सुख के लिए, शाही परिवार के अहंकार के लिए देश के लाखों परिवारों को तबाह कर दिया गया था, देश को जेलखाना बना दिया गया था। बहुत लंबा संघर्ष चला। आखिर में अपने आप को बहुत बड़ा %तीस मार खां% मानने वालों को जनता जनार्दन की ताकत स्वीकारनी पड़ी, घुटने टेकने पड़े और जनता जनार्दन के सामर्थ्य से देश से इमरजेंसी हटी।

मोदी ने कहा कि गरीबों को शक्ति देने के लिए, उनके सशक्तिकरण के लिए जितना काम हमारे कार्यकाल में हुआ है, हमारी सरकार के द्वारा हुआ है, इतना पहले कभी नहीं हुआ। गरीबों का सशक्तिकरण और गरीब ही गरीबी को परास्त करे, इस दिशा में हमने योजनाओं को आकार दिया है। मुझे मेरे देश के गरीबों पर और उनके सामर्थ्य पर पूरा भरोसा है। अगर अवसर मिले तो वो हर चुनौती को पार कर सकता है। गरीब ने करके दिखाया है और योजनाओं का लाभ लेते हुए, अवसरों का फायदा उठाते हुए 25 करोड़ लोग गरीबी को परास्त करने में सफल हुए हैं।

पीएम मोदी के भाषण पर कांग्रेस का पलटवार

कांग्रेस ने गुरुवार को राज्यसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिए गए भाषण की कड़ी आलोचना की है। पार्टी ने आरोप लगाया कि पीएम मोदी ने अपने भाषण में झूठ की नदी बहाई और इतिहास को तोड़-मरोड़कर पेश किया। कांग्रेस ने कहा कि पीएम ने देश के असल मुद्दे पर बात नहीं की। उनका भाषण झूठ और आधा सच से भरा हुआ था। राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब दिया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कांग्रेस पर तुष्टिकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया और दावा किया कि भाजपा की सरकार सबका साथ, सबका विकास के सिद्धांत पर काम कर रही है। पीएम ने यह भी कहा कि कांग्रेस की प्राथमिकता परिवार पहले रही है, और उसकी नीतियां इसी आधार पर केंद्रित रही हैं। पीएम मोदी के बयान पर पलटवार करते हुए कांग्रेस महासचिव और संचार प्रभारी जयराम रमेश ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि प्रधानमंत्री की बातों को भटकाने, तोड़-मरोड़कर पेश करने और बदनाम करने की क्षमता वाकई चौंका देने वाली है। आज राज्यसभा में उनका 90 मिनट का भाषण झूठ और आधा सच से भरा हुआ था।

आचार्य विद्यासागर का क्षण-क्षण राष्ट्र को समर्पितः अमित शाह

रायपुर। केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने आज छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज के प्रथम समाधि स्मृति महोत्सव को मुख्य अतिथि के तौर पर संबोधित किया और श्री 1008 सिद्धचक्र विधान विश्व शांति महायज्ञ में शामिल हुए। इस दौरान केन्द्रीय गृह मंत्रीअमित शाह ने आचार्य श्री विद्यासागर जी की स्मृति में 100 का स्मारक सिक्का, डाक विभाग का ?5 का विशेष लिफाफा, 108 चरण चिन्हों व चित्र का लोकार्पण और प्रस्तावित समाधि स्मारक 'विद्यायतन' का शिलान्यास किया। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, उप-मुख्यमंत्री विजय शर्मा और पूज्य मुनि समता सागर जी महाराज सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।

आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज केवल एक संत या जैनाचार्य नहीं थे, बल्कि एक युग पुरुष थे जिन्होंने एक नए विचार और नए युग का प्रवर्तन किया। उन्होंने कहा कि कर्नाटक में जन्मे आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज अपने कर्मों से भारत, भारतीय संस्कृति, भारतीय भाषाएँ और भारत की पहचान के ज्योतिर्धर बने। श्री शाह ने कहा कि शायद ही यह सम्मान किसी ऐसे धार्मिक संत को मिला होगा, जिन्होंने धर्म के साथ-साथ देश की पहचान की व्याख्या विश्व भर में की हो।

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने कहा कि उन्हें कई बार आचार्य श्री विद्यासागर जी का सान्निध्य मिला और हर बार आचार्य जी ने भारतीय भाषाओं के संवर्धन एवं संरक्षण, भारतीय संस्कृति की अक्षुण्णता, भारत एवं भारतीयता के गौरव के विश्व भर में प्रसार और भारत की पहचान 'इंडिया' की बजाय 'भारत' से होने पर जोर दिया। श्री अमित शाह ने कहा कि जब भारत को जी-20 की मेजबानी मिली और सम्मलेन में शामिल होने के लिए सभी राष्ट्राध्यक्षों को निमंत्रण पत्र भेजे गए, तो उन पर 'प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया' की बजाय 'प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत' लिखा देख पूरा विश्व आश्चर्य में पड़ गया।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से नवनियुक्त पुलिस महानिदेशक अरुण देव गौतम ने की सौजन्य भेंट

रायपुर। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय से आज उनके निवास कार्यालय में नवनियुक्त पुलिस महानिदेशक श्री अरुण देव गौतम ने सौजन्य भेंट की। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने श्री गौतम को नई जिम्मेदारी के लिए शुभकामनाएं देते हुए प्रदेश में कानून-व्यवस्था, अपराध नियंत्रण, नागरिक सुरक्षा और पुलिस प्रशासन को और अधिक प्रभावी बनाने हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान किए। उन्होंने आधुनिक तकनीकों के समुचित उपयोग, जनसहभागिता और अनुशासित पुलिसिंग के माध्यम से प्रदेश में कानून-व्यवस्था को सुदृढ़ किए जाने पर बल दिया।

एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल में भाजपा को बढ़त

नईदिल्ली। एक्सिस माई इंडिया एग्जिट पोल ने दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की वापसी की भविष्यवाणी की है। प्रदीप गुप्ता के नेतृत्व वाली उपभोक्ता डेटा इंटेलिजेंस कंपनी के सर्वेक्षण के अनुसार, पार्टी को विधानसभा चुनाव 2025 में 70 में से 45-55 सीटें जीतने का अनुमान है। एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल में मौजूदा आम आदमी पार्टी (क्क) के सत्ता से बाहर होने का अनुमान लगाया गया है, साथ ही पार्टी को 15-25 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया है। इस बीच, कांग्रेस को अधिकतम एक सीट जीतने का अनुमान है।

एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल सर्वे से पता चलता है कि मुख्यमंत्री पद के लिए, क्क के अरविंद केजरीवाल दिल्ली के लोगों की पहली पसंद हैं, उनके बाद बीजेपी के परवेश वर्मा और मनोज तिवारी हैं। एक्सिस माई इंडिया एग्जिट पोल के मुताबिक, नई दिल्ली लोकसभा सीट की 10 सीटों में से बीजेपी को सात सीटें मिल सकती हैं, जबकि आम आदमी पार्टी (आप) को तीन सीटें मिलने का अनुमान है। आप सुप्रीमो और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री जिले की नई दिल्ली सीट से चुनाव लड़ रहे हैं।

एक्सिस माई इंडिया एग्जिट पोल के मुताबिक, उत्तर पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट पर बीजेपी को 10 में से छह सीटें जीतने का अनुमान है, जबकि आप को चार सीटें मिलने का अनुमान है। एक्सिस माई इंडिया एग्जिट पोल के मुताबिक, दक्षिण दिल्ली लोकसभा सीट पर बीजेपी और आप को पांच-पांच सीटें मिलने का अनुमान है। चांदनी चौक लोक सभा सीट की 10 सीटों में से भाजपा को साथ और आम आदमी पार्टी के खाते में तीन सीटें जा सकती हैं।

पश्चिमी दिल्ली की 10 सीटों में से भाजपा को 8 जबकि आम आदमी पार्टी को दो सीटें मिल सकती हैं। पूर्वी दिल्ली में भाजपा जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रही है। बीजेपी को 8 जबकि आम आदमी पार्टी को दो सीटे मिल सकती हैं। उत्तर पश्चिमी दिल्ली के 10 सीटों में भाजपा को 9 और आम आदमी पार्टी को एक सीटे मिल सकती हैं। वोट प्रतिशत की बात करें तो 48 फ़ीसदी भाजपा के पक्ष में जबकि आम आदमी पार्टी को 42 फ़ीसदी मिल सकती है। कांग्रेस को तीन प्रतिशत वोट मिल रही है।

प्रमुख समाचार

नए फॉर्मेट में होगी परीक्षा पे चर्चा, मोदी छात्रों को देंगे टिप्स

नईदिल्ली. परीक्षा पर चर्चा के 8वें एडिशन की तारीख सामने आ गई है। %इस वर्ष एक नए प्रारूप और शैली में आयोजित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परीक्षाओं पर संवाद कार्यक्रम में कई अन्य विशेषज्ञ भी शामिल होंगे। %परीक्षा पे चर्चा% कार्यक्रम में समाज के सभी क्षेत्रों की मशहूर हस्तियां और प्रतिष्ठित हस्तियां मौजूद रहेंगी। सद्गुरु, मैरी कॉम, दीपिका पादुकोण और विक्रांत मेस्सी सहित गणमान्य लोग परीक्षा पे चर्चा% कार्यक्रम में छात्रों को परीक्षा संबंधी टिप्स देते नजर आएंगे। पीएम मोदी के परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम का यह 8वां संस्करण है. इस वर्ष इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए तीन करोड़ से अधिक छात्रों ने पंजीकरण कराया है। परीक्षा पे चर्चा का नया प्रारूप 10 फरवरी को प्रसारित किया जाएगा। पीएम मोदी के साथ-साथ अलग-अलग क्षेत्रों के अन्य लोग परीक्षा के दौरान तनाव से उबरने के टिप्स देते नजर आएंगे। आमतौर पर बोर्ड परीक्षाओं से पहले होने वाली इस चर्चा में अब तक सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही छात्रों को परीक्षा से जुड़े तनाव को दूर करने के टिप्स देते नजर आए थे. लेकिन इस बार ये लोग छात्रों को परीक्षा के लिए तनाव मुक्त रहने के टिप्स भी देते नजर आएंगे।

घरेलू हिंसा मामले में मंत्री धनंजय मुंडे पाए गए दोषी

नईदिल्ली. महाराष्ट्र के खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री धनंजय मुंडे को घरेलू हिंसा मामले में दोषी पाया गया है। बांद्रा फैमिली कोर्ट ने शिकायतकर्ता करुणा शर्मा के पक्ष में फैसला सुनाया है। मजिस्ट्रेट एबी जाधव ने एक आदेश जारी कर मंत्री को अंतिम फैसला आने तक शिकायतकर्ता को प्रति माह 1.25 लाख रुपये और उनकी एक बेटी को 75,000 रुपये प्रति माह का भुगतान करने का निर्देश दिया। इसके अतिरिक्त, अदालत ने आवेदन की लागत को कवर करने के लिए मुआवजे के रूप में 25,000 रुपये दिए। महिला ने घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम, 2005 की धारा 23 के तहत मामला दायर किया, जिसमें दावा किया गया कि 1998 में मंत्री से उसका अंतरजातीय प्रेम विवाह शुरू में स्थिर था लेकिन 2018 में बिगड़ना शुरू हो गया। उसने आरोप लगाया कि उसने परिवार के दबाव में दूसरी शादी की, लेकिन उसे आश्वासन दिया कि वह उसकी पहली पत्नी के रूप में अपना दर्जा बरकरार रखेगी। उसने मंत्री पर उसे अपने मूल स्थान पर जाने से रोकने और अपने अनुयायियों से शारीरिक धमकियां देने का आरोप लगाया।

कबड्डी महासंघ के प्रशासक को कार्यभार सौंपने का निर्देश

नईदिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को देश के शौकिया कबड्डी महासंघ का संचालन एक निर्वाचित शासी निकाय को सौंप दिया, अदालत ने स्पष्ट किया कि उसका आदेश निर्वाचित निकाय का समर्थन नहीं था, बल्कि यह सुनिश्चित करने के लिए एक तदथ व्यवस्था थी कि महासंघ की संबद्धता बहाल हो जाए और महिला खिलाड़ी इस महीने के अंत में एक अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम में भाग ले सकें। अगस्त 2018 से फेडरेशन को दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश (सेवानिवृत्त) एसपी गर्ग, अदालत द्वारा नियुक्त प्रशासक द्वारा चलाया जा रहा है। केंद्र की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पीठ को अंतरराष्ट्रीय कबड्डी महासंघ (आईकेएफ) से प्राप्त एक पत्र के बारे में सूचित करने के बाद गुरुवार का आदेश पारित किया, जिसमें एमेच्योर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया (एकेएफआई) की संबद्धता को बहाल करने के लिए कदम उठाने और ईरान चैंपियनशिप में भारतीय खिलाड़ियों की भागीदारी की अनुमति देने का वादा किया गया था, अगर एक निर्वाचित निकाय प्रशासक से महासंघ का अधिग्रहण करता है। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और एन कोटिस्वर सिंह की पीठ ने सहमति व्यक्त की।

10 दिनों के लिए पश्चिम बंगाल पहुंचे मोहन भागवत

नईदिल्ली. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) प्रमुख मोहन भागवत के संगठनात्मक कार्य के लिए 10 दिवसीय दौरे पर पश्चिम बंगाल पहुंचे हैं। यह 5 फरवरी को आरएसएस पश्चिम बंगाल इकाई द्वारा सूचित किया गया था। आरएसएस बंगाल के महासचिव जिष्णु बसु द्वारा आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में कहा गया कि मोहन भागवत संघ कार्यकर्ताओं और प्रचारकों के साथ कई दौर की चर्चा करने वाले हैं। यात्रा कार्यक्रम के अनुसार, भागवत 6 फरवरी को कोलकाता पहुंचें। इसके बाद 7 फरवरी से 10 फरवरी तक वह कोलकाता में केशव भवन में रहेंगे और संघ कार्यकर्ताओं और वरिष्ठ संघ सदस्यों से मुलाकात करेंगे।11 और 12 फरवरी को वह कोलकाता के अखिल भारतीय टोली बैठक में संघ के केंद्रीय नेतृत्व के साथ अहम बैठक करेंगे। फिर 13 फरवरी को वह मध्य बंगाल, बर्दवान के लिए रवाना होंगे। 14 फरवरी को भागवत एक नए संघ कार्यालय का उद्घाटन करेंगे और 1 फरवरी को बर्दवान के तलित में साई कॉम्प्लेक्स में सभी संघ कार्यकर्ताओं के लिए एक बैठक करेंगे।

शेख हसीना के बयान पर बौखलाया बांग्लादेश

ढाका। बांग्लादेश में अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रही है। इसी बीच विदेश मंत्रालय ने गुरुवार को बताया कि बांग्लादेश ने भारत में अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना द्वारा दिए गए झूठे और मनगढ़ंत बयानों पर भारत से विरोध दर्ज कराया है। बता दें कि यह घटनाक्रम हसीना द्वारा बुधवार रात सोशल मीडिया के माध्यम से दिए गए भाषण के एक दिन बाद सामने आया है, जिसमें उन्होंने देशवासियों से मौजूदा शासन के खिलाफ संगठित तौर पर प्रतिरोध करने की अपील की थी। मामले में विदेश मंत्रालय ने बताया कि भारत के कार्यवाहक उच्चायुक्त को सौंपे गए विरोध पत्र में बांग्लादेश ने 'गहरी चिंता, निराशा और गंभीर आपत्ति' जताई है। साथ ही बांग्लादेश ने कहा है कि इस तरह के बयान देश के लोगों की 'भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे हैं। इसको लेकर बांग्लदश ने भारत सरकार के समक्ष पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना द्वारा सोशल मीडिया समेत विभिन्न मंचों पर लगातार की जा रही झूठी मनगढ़ंत टिप्पणियों और बयानों' को लेकर कड़ा विरोध दर्ज कराया है, जिससे बांग्लादेश में अस्थिरता का माहौल पैदा हो रहा है।

राज्यसभा में कांग्रेस पर जमकर बरसे मोदी, डिपोर्ट मामले में हंगामा

नईदिल्ली। संसद का बजट सत्र चल रहा है। राज्यसभा में आज हंगामा के बीच ही राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा हुई। वहीं, प्रधानमंत्री ने अभिभाषण पर जवाब भी दिया। लोकसभा में आज का दिन काफी हंगामेदार रहा। अमेरिका से निर्वासित अवैध भारतीय प्रवासियों के साथ हुए व्यवहार को लेकर विपक्ष सरकार पर जबरदस्त तरीके से हमलावर था। राज्यसभा में भी इस मुद्दे को उठाया गया। दोनों ही सदनों में खूब हंगामा हुआ। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इसको लेकर अपना बयान भी दिया।

राज्यसभा की कार्यवाही

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने राज्यसभा में कहा कि राष्ट्रपति का अभिभाषण प्रेरक और प्रभावी था और हम सब के लिए आगे के काम करने का मार्गदर्शन भी था। उन्होंने तंज सकते हुए कहा कि कांग्रेस के मॉडल में सर्वोपरि है 'फैमिली फर्स्ट'। उन्होंने कहा कि वर्ष 2014 के बाद देश को एक वैकल्पिक मॉडल, एक वैकल्पिक कार्यशैली देखने को मिली जिसमें तुष्टीकरण नहीं संतुष्टीकरण पर जोर दिया जाता है। हमने सामान्य वर्ग के गरीबों को दस प्रतिशत का आरक्षण दिया जिसका एससी, एसटी और ओबीसी समाज ने स्वागत किया।

प्रधानमंत्री ने कहा कि जिसे कोई नहीं पूछता, उसे मोदी पूजता है। गरीब और वंचित का कल्याण हमारी प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि बाबा साहेब अंबेडकर से कांग्रेस को कितनी नफरत थी, उनके प्रति कांग्रेस में इतना गुस्सा था कि उनकी (बाबा साहेब) की हर बात से कांग्रेस चिढ़ जाती थी। आज कांग्रेस को मजबूरन %जय भीम% बोलना पड़ रहा है। कांग्रेस की राजनीति का मंत्र हमेशा दूसरे की लकीर छोटी करना रहा...इसके कारण उन्होंने सरकारों को अस्थिर किया। उन्होंने कहा कि इस देश ने इमरजेंसी का दौर भी देखा है।

संविधान को किस प्रकार कुचला गया, संविधान की स्पिरिट को सत्ता सुख के लिए किस प्रकार रौंदा गया था, ये देश जानता है। पीएम मोदी ने सदन में पढ़ा शेर...

तमाशा करने वालों को क्या खबर,
हमने कितने तुफानों को पार कर, दीया जलाया है...

– विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बृहस्पतिवार को राज्यसभा में कहा कि अमेरिका में बिना दस्तावेज़ों के रह रहे भारतीयों को निर्वासित किए जाने की प्रक्रिया नयी नहीं है और यह सभी देशों का दायित्व है कि यदि उनके नागरिक विदेशों में अवैध रूप से रह रहे हैं तो उन्हें वापस ले। राज्यसभा में इस संबंध में एक बयान देते हुए जयशंकर ने यह भी कहा, ''हम यह सुनिश्चित करने के लिए अमेरिका की सरकार के साथ बातचीत कर रहे हैं कि निर्वासित लोगों के साथ दुर्व्यवहार न हो।'' उन्होंने कहा, ''यह सभी देशों का दायित्व है कि यदि उनके नागरिक विदेश में अवैध रूप से रह रहे पाए जाते हैं तो वे अपने नागरिकों को वापस लें। यह नीति केवल एक देश पर लागू नहीं है। निर्वासन की प्रक्रिया कोई नयी नहीं है, यह कई वर्षों से है।''

– राज्यसभा में बृहस्पतिवार को कांग्रेस के एक सदस्य ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के कारण आचार संहिता लागू होने के बावजूद राष्ट्रपति अभिभाषण एवं आम बजट में सरकार द्वारा की गयी घोषणाओं को आचार संहिता का उल्लंघन करार देते हुए कहा कि अगली बार निर्वाचन आयोग को इस पर ध्यान देना चाहिए। उच्च सदन में राष्ट्रपति अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा को आगे बढ़ाते हुए कांग्रेस के राजीव शुक्ला ने प्रश्न किया कि क्या राजनीति चुनाव के लिए ही होती है अथवा कुछ काम करने के लिए भी होती है? उन्होंने कहा कि जब चुनाव होने वाले होते हैं तो उस राज्य विशेष, वहां की संस्कृति, खानपान, पहनावे आदि की चर्चा होती है और चुनाव हो जाने के बाद उस राज्य को भुला दिया जाता है।

लोकसभा की कार्यवाही

अमेरिका से निर्वासित''अवैध'' भारतीय प्रवासियों के साथ हुए व्यवहार को लेकर विपक्षी दलों के सदस्यों ने बृहस्पतिवार को लोकसभा में हंगामा किया जिसके कारण सदन में केंद्रीय बजट पर चर्चा शुरू नहीं हो सकी तथा कार्यवाही तीन बार के स्थगन के बाद चौथी बार शुक्रवार पूर्वाह्न 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने विपक्ष के हंगामे के बीच सदन में कहा कि अमेरिका में बिना दस्तावेज़ों के रह रहे भारतीय प्रवासियों को निर्वासित किए जाने की प्रक्रिया नयी नहीं है और यह सभी देशों का दायित्व है कि यदि उनके नागरिक विदेशों में अवैध रूप से रह रहे हैं तो उन्हें वापस ले। उन्होंने यह भी कहा, ''हम यह सुनिश्चित करने के लिए अमेरिका की सरकार के साथ बातचीत कर रहे हैं कि निर्वासित लोगों के साथ दुर्व्यवहार न हो।'' वहीं, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बृहस्पतिवार को सदन में विपक्षी सदस्यों के हंगामे के बाद कहा कि रोजाना प्रश्नकाल में गतिरोध पैदा करना भारत के मतदाताओं का अपमान हैं।

नक्सल दहशत कम हुई तो उम्मीदवारों की लगी होड़

■ नेशनल पार्क इलाके में सिमटने लगा नक्सलियों का खौफ

बीजापुर। बीजापुर में नक्सलियों कि दहशत अब नक्सलगढ़ में सिमटने लगी हैं। इसका परिणाम बखूबी निकलकर सामने आ रहा हैं। इस साल के पंचायत चुनाव में इसका सार्थक परिणाम देखने को मिला हैं। नेशनल पार्क सेड्रा इलाके में नक्सलियों के इशारे के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता था। लेकिन अब माहौल बदलता हुआ नजर आ रहा हैं। मौजूदा समय में हालत बदल गए हैं। मतदान के इस महा पर्व में कई वर्षो बाद उन इलाके के प्रत्याशी खुलकर सामने आ रहे हैं। एक समय ऐसा भी था कि जब इन इलाक़ों से पंच सरपंच और जनपद सदस्य के प्रत्याशी निर्विरोध होते थे। लेकिन अब चुनाव लड़ने वालों में कम्पटीशन हो गया है।

नक्सलियों के भय को दरकिनार कर निडर होकर सभी पदों के लिए कई वर्षो बाद नामांकन आए हैं। यह प्रत्याशी अपने पक्ष में वोट मांगने उन दहशतगर्द इलाकों में निकलेंगे। यह राष्ट्रीय पर्व कि गूंज सुनाई देगी। आपको बता दे कि 2005 के सलवा जुडूम के बिगड़ाते हालातो कि वजह से यह

चुनाव कराना संभव नहीं था।कोई भी प्रत्यासी यहां से खड़े होने कि हिम्मत नहीं करता था। उस समय के बिगड़ते हालत से ग्रामीणों के आशियाने छीन गए। कई ग्रामीण अपने घर से बेघर हो गए। यहां के ग्रामीण ब्लाक और जिला मुख्यालय में आकर बसने लगे। नक्सली दहशत इस कदर था कि उनका नाम लेने से लोग कतराते थे। अब समय ने करवट ले ली हैं। सरकार के सहयोग से नक्सल दहशत सिमटता जा रहा हैं । उन नक्सल इलाकों में राष्ट्रीय पर्व का उत्साह देखने को मिल रहा हैं।

दो दशको से इन इलाके में निर्विरोध चुनकर जाते थे सरपंच

वर्ष 2005 सलवा जुडूम के बाद नेशनल पार्क इलाके के चार पंचायतो के जन प्रतिनिधि निर्विरोध चुनकर आए हैं। सेंड्रा इलाके में सेंड्रा, बड़ेकाकलेड, एडापल्ली,और केरपे पंचयात हैं। इन पंचायतो के कई गांव सलवा जुडूम के वक्त खाली हो गए थे। बीजापुर जिले के भोपालपटनम सहित आसपास के इलाकों में जाकर बसने लगे। उसके बाद से उन जगहों पर चुनाव नही होता है। इनके पोलिंग बूथ ब्लॉक मुख्यालय में शिफ्ट कर दिए गए हैं।

चार पंचायतों में सरपंच के 13 उम्मीदवार मैदान में है

केरपे पंचायत के सरपंच पद के लिए तीन आवेदन आए हैं। वहां 13 वार्ड हैं सभी निर्विरोध हुए हैं। यहां 785 मतदाता हैं। 356 महिला व 429 पुरुष है। वही बड़े काकलेट में सरपंच के लिए चार आवेदन आए हैं। वह 16 वार्ड हैं। सभी निर्विरोध हुए हैं। वहां कुल 958 मतदाता हैं। जिनमें 478 महिला व 480 पुरुष हैं। वही एडापल्ली में सरपंच के तीन आवेदन आए हैं। वह कुल 13 वार्ड हैं। जिनमे छः निर्विरोध हुए हैं। साथ ही 14 पंचो ने आवेदन किया हैं। जहाँ कुल 739 मतदाता हैं। इनमें 373 महिला व 366 पुरुष हैं। इसी तरह सेड्रा पंचायत के लिए तीन आवेदन आए हैं। वह 15 वार्ड हैं 11 निर्विरोध हुए हैं। आठ आवेदन आए हैं। जिनमे कुल 845 मतदाता हैं। 419 महिला व 426 पुरुष शामिल हैं।

रिटर्निंग अधिकारी दिलीप उईके ने बताया की दस जनपद सदस्यो के लिए 39 आवेदन आए हैं। स्कूटनी में 1 रिजेक्ट किया गया है। वही 35 ग्राम पंचायतो के लिए 134 आवेदन आए हैं और 420 पंचो के लिए 633 आवेदन आए। जिनमे से 5 निरस्त हुए है। 628 आवेदन हैं। स्कूटिंग कि प्रक्रिया हो चुकी हैं। अब कल नाम वापसी का अंतिम दिन है।

अवैध शराब बिक्री से त्रस्त पिपरहट्टा के ग्रामीणो ने सौंपा ज्ञापन

रायपुर। शासन - प्रशासन से लगातार गुहार लगाने के बाद भी अवैध शराब बिक्री पर लगाम न लगने से त्रस्त व आक्रोशित ग्रामीणों ने पंचायत चुनाव के दौरान ही इस पर स्थायी रोक लगाने व लिप्त तत्वों के खिलाफ ठोस एवं प्रभावी कार्यवाही की मांग को लेकर पुलिस प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों सहित मंदिर हसौद थाना प्रभारी को ज्ञापन सौंपा है व इसकी प्रतिलिपि जनप्रतिनिधियों को सौंप जनभावना की सम्मान कराने का आग्रह किया है।

पुलिस महानिरीक्षक अमरेश मिश्रा, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डा लाल उमेद सिंह, थाना प्रभारी अविनाश सिंह को बीते बुधवार 5 फरवरी को सौंपे गये इस ज्ञापन की प्रति क्षेत्रीय सांसद बृजमोहन अग्रवाल, क्षेत्रीय विधायक गुरु खुशवंत सिंह साहेब व शराब विरोधी मुहिम में सक्रिय किसान संघर्ष समिति के संयोजक भूपेंद्र शर्मा को प्रदत्त की गयी है। ज्ञापन में पूर्व राज्यपाल रमेश बैस जी के गृह ग्राम होने की जानकारी देते हुये बताया गया है कि लगातार शिकायत व पुलिसिया कार्यवाही के बाद भी इसमें लिप्त तत्व अपने गतिविधियों से बाज नहीं आ रहे हैं जिसके चलते ग्राम में अशांति का वातावरण बना रहता है और कभी भी कोई अनहोनी घटना घटित हो सकता है। ग्राम में जुआ होने की जानकारी देते हुये इनमें लिप्त तत्वों के खिलाफ ठोस एवं प्रभावी कार्यवाही करने व इन असामाजिक गतिविधियों पर स्थायी रोक लगाने कठोर कार्यवाही का आग्रह किया है। शर्मा ने शासन - प्रशासन की विफलता पर ग्रामीणों को एकजुट हो आंदोलनात्मक कदम उठाने का आग्रह किया है व उनके अभियान को पूर्ण समर्थन देने का आश्वासन देते हुये संपन्न होने जा रहे पंचायत चुनाव में इसे एक मुद्दा बनाने व शराब - जुआ व इनमे लिप्त तत्वों के प्रति नरम रुख अपनाने वाले प्रत्याशियों को सबक सिखाने का आग्रह किया है।

ग्रामीण सूत्रों के अनुसार खासकर एक आपराधिक रिकार्डधारी असामाजिक तत्व ने आतंक मचा रखा है और ग्रामीणों को चुनौती देते हुये खुले आम शराब बेच रहा है तथा उसके आतंक के चलते ग्रामीण सामने आने से कतराते हैं। ज्ञापन में सरपंच वीर सिंह वर्मा, उपसरपंच प्रहलाद साहू, पूर्व सरपंच लक्ष्मीनारायण ठाकुर, परमानंद सिंह ठाकुर, नूतन साहू, टेकराम साहू, रामनारायण सिंह ठाकुर आदि सहित सरपंच संघ के अध्यक्ष गोपाल धीवर के हस्ताक्षर है। इधर पंचायत चुनाव के चलते कई ग्रामों में पियक्कड़ों की बन आने व कई प्रत्याशियों के घर इनके जमावड़ा लगने की जानकारी कई ग्रामों के ग्रामीणों से मिल रही है।

दंतैल हाथी का आतंक, 2 मकानों में की तोड़फोड़

रातभर जागने को मजबूर लोग, इलाके में दहशत

कोरबा। कोरबा वन मंडल कटघोरा में 48 हाथी घूम रहे हैं। जो लंबे समय से विचरण कर रहे हैं। कई हाथी झुंड से बिछड़ कर जंगल से लगे गांव में पहुंच रहे हैं। जिससे ग्रामीण दहशत में हैं ग्रामीण रात को जगाने को मजबूर हैं। अब हाथियों पर सायरन कभी असर नहीं हो रहा है। केंदई रेंज में दंतैल हाथी ने रात ढ़ोढ़ाबहार में दो मकानों को तोड़ दिया।

केंदई रेंज में दंतैल हाथी के कहर से बचने के लिए ग्रामीण शंकर ने अपने परिवार के साथ भागकर जान बचाई। हाथी के मकान तोड़ने और हाथी मित्र दल के वाहन में सायरन बजाने का वीडियो सामने आया है। जहां वन विभाग की टीम सायरन बजा रही है। लेकिन हाथी को कोई असर नहीं हो रहा है, वह घर के बाहर खड़ा हुआ था। हाथी मित्र दल के कर्मचारी टॉर्च मारने के साथ सायरन बजाते रहे। लेकिन दंतैल पर कोई असर नहीं हुआ। हाथी मकान को तोड़ने के साथ ही अंदर से राशन सामान निकाल कर खाता रहा। काफी देर बाद दो मकानों को तोड़ने के बाद जंगल की ओर चला गया। इस क्षेत्र में अभी 28 हाथी घूम रहे हैं। जिसमें से दंतैल हाथी अलग से घूम रहा है। आसपास के ग्रामीणों को सतर्क कर दिया गया है।

ग्रामीणों की मानें तो हाथी गांव के आसपास में विचरण कर रहा है, जो अक्सर गांव के करीब आ जाता है। कई बार तो गांव के अंदर हाथी घुस जाता है और फसल को भी नुकसान पहुंचाता है जिससे लोग परेशान हैं और उन्हें आर्थिक क्षति भी हो रही है। हाथी से बचने के लिए उन्हें कई बार रात-रातभर जगना पड़ जाता है। वहीं, शाम होते ही लोगों को घर के अंदर रहना पड़ता है। डर हमेशा बना हुआ रहता है।

अंबिकापुर ननि में कांग्रेस हैट्रिक लगाने के लिए जुटी

■ भाजपा के आरोपों को बताया बेबुनियाद

सरगुजा। अंबिकापुर शहर के कांग्रेस मेयर कैंडिडेट डॉ अजय तिर्की नगर सरकार में हैट्रिक लगाने के लिये तीसरी बार मैदान में हैं। लगातार 10 साल तक मेयर रहने के बाद वो एक बार फिर जनता के सामने तीसरी पारी के लिए वोट मांग रहे हैं। दस साल तक सत्ता में रहने के कारण उन पर कई आरोप हैं। ज्यादातर आरोप विकास ना होने के हैं। अब चुनाव प्रचार जोरों पर हैं।

मेयर प्रत्याशी अजय तिर्की ने कहा कि शहर में भाजपा अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए सामने वाले को हमेशा ही डोमिनेट करना चाहती है। माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा ही तो लगातार 7 बार हमको इनाम दिया गया। हमारे पूर्व विभागीय मंत्री अमर अग्रवाल कहते हैं की काम करना सीखना है तो अम्बिकापुर महापौर से सीखिये और स्थानीय स्तर पर इनके ही कार्यकर्ता बोलते हैं की विकास नही हुआ। हमने जो स्वच्छता पर काम शुरू किया, शहर के चारो कोने में हमार क्लीनिक निगम ने बनवाये। कई ऐसे काम हैं जिनका उद्घाटन तो मुख्यमंत्री व मंत्रियों ने ही किया था, स्टेडियम में इनडोर स्टेडियम, बास्केटबॉल ग्राउंड, फ्लड लाइट लग गई।

अजय तिर्की के मुताबिक काम हुआ है बीजेपी कहती है काम नहीं हुआ तो ऐसा क्या कर देते कि जिसे काम माना जाता। इस सवाल पर उन्होंने कहा कि अभी पिछले 4-5 दिनों में मैंने बहुत सोचा इस बारे में कि हमें और क्या करना चाहिए था, क्योंकि निगम अपने स्तर पर घोषणा नहीं कर सकती है। घोषणा तो राज्य सरकार या केंद्र सरकार से ही होंगी। हम शहर के लिए क्या मांग कर सकते हैं। उसमें हम लोग ट्रांसपोर्ट नगर में माध्यम से रिंग रोड को

व्यवस्थित नहीं कर पाए हैं। पुराना बस स्टैंड में नए मार्केट के लिए प्रपोजल जो भेजे हैं वो हो जायेगा तो निगम की आय भी बढ़ेगी और युवाओं को रोजगार भी मिलेगा।

कांग्रेस मेयर कैंडिडेट डॉ अजय तिर्की ने कहा 10 साल सत्ता में रहने के बाद आप कई आरोपों से घिर जाते हैं, लेकिन हमने भ्रष्टाचार मुक्त और कंफर्टेबल सरकार निगम को दी है, जिसमें कोई भी व्यक्ति सहजता से मेयर से मिल सकता है। हमारे काउंसलर के माध्यम से वो अपनी बात आसानी से रख सकता है।कई काम नियमानुसार नहीं भी होते हैं। लेकिन लोगों को सुलभता से मेयर उपलब्ध हैं। आधी रात को भी फोन के माध्यम से मेयर संपर्क में रहते हैं। और लोग इस बात से संतुष्ट हैं।

अजय तिर्की के मुताबिक गार्बेज कैफे हो या जीपीएस के माध्यम से स्वच्छता गाड़ियों को ट्रैक करना इस तरह के नवाचार किए गए हैं। अब तीसरी बार मौका मिला तो मध्य क्षेत्र की तरह अब उन क्षेत्रों के डेवलपमेंट पर फोकस होगा, जो शहर बढ़ने के कारण शहर के अंतिम छोर पर हैं वहां भी विकास कार्यों के साथ गार्डन, तालाबों का सौंदर्यीकरण किया जाएगा।

एमपी की शराब पहुंच रही छत्तीसगढ़ 11 को होना है नगरीय निकाय चुनाव

बेमेतरा। अवैध शराब का जखीरा बेमेतरा पुलिस ने पकड़ा है। दो अलग अलग घटनाओं में लाखों की अवैध शराब जब्त की गई है। पकड़ी गई शराब मध्य प्रदेश के देवास से आई थी। शराब किसने भेजा था और किसको पहुंचाना था इसकी जांच जारी है। पूरे छत्तीसगढ़ में आदर्श आचार संहिता लगी है। 11 फरवरी को नगरीय चुनाव के लिए मतदान होना है। ऐसे में शराब की इतनी बड़ी खेप पकड़े जाने से कई सवाल भी खड़े होने लगे हैं। पकड़े गए आरोपी को रिमांड पर लेकर पूछताछ की जा रही है।

बुधवार को भी पुलिस ने मध्य प्रदेश से लाई गई 24 पेटी शराब पकड़ी थी। पकड़ी गई शराब की कीमत लाखों में है। कल हुई कार्रवाई में बेमेतरा सिटी कोतवाली और बेमेतरा आबकारी विभाग संयुक्त रुप से शामिल रही। पुलिस ने बताया कि कल करही गांव से 24 पेटी शराब की बरामदगी की गई थी। शराब के साथ पुलिस ने सनत खरे नाम के एक शख्स को भी गिरफ्तार किया था। संभावना जताई जा रही है कि पकड़ी गई शराब का इस्तेमाल चुनाव में किया जा सकता था।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रामकृष्ण साहू ने कहा मध्य प्रदेश के देवास से ये शराब लाई जा रही थी। पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ जारी है। पूछताछ के बाद ये पता चल पाएगा कि शराब कहां से किसने मंगाई थी और कहां पहुंचानी थी। शराब मंगाने वाले और भेजने वाले दोनों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

बेरला पुलिस ने आज बांसा गांव से कुल 445 पेटी शराब पकड़ी है। शराब के साथ दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पकड़े गए लोगों के नाम अनिल वर्मा उर्फ बन्नू निवासी बेमेतरा और योगेश मिना निवासी देवास मध्य प्रदेश शामिल हैं। पकड़ी गई शराब की कीमत तीन लाख से भी ज्यादा है।

छत्तीसगढ़ प्रमुख समाचार

भाजपा ने 18 बागी नेताओं को छह साल के लिए किया सस्पेंड

कबीरधाम। कबीरधाम जिले में इसी माह फरवरी में हो रहे निकाय चुनाव में भाजपा ने अपने पार्टी के नेताओं के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया है। पार्टी ने निकाय चुनाव लड़ने वाले बागी प्रत्याशी को 6 साल के लिए सस्पेंड कर दिया है। दरअसल, कबीरधाम के सभी निकाय में भाजपा ने अपने अधिकृत प्रत्याशी को चुनावी मैदान में उतरा है। वहीं, कुछ नेताओं ने टिकट के लिए दावेदारी की थी, लेकिन पार्टी ने उन्हें टिकट नहीं दिया है। इस कारण ऐसे नेता बागी हो गए है। भाजपा प्रदेश कार्यालय ने ऐसे 18 बागी नेताओं की सूची जारी की है, जिससे नगर पालिका परिषद कवर्धा से 8, नगर पंचायत सहसपुर लोहारा से 7 व नगर पंचायत इंदौरी से 3 लोग शामिल है। इनमें कुछेक तो ऐसे है जो पार्टी से हटकर निर्दलीय चुनाव में खड़े हुए है। इस कारण भाजपा के अधिकृत प्रत्याशी को नुकसान हो सकता हैं। गौरतलब है कि कवर्धा नगर पालिका अध्यक्ष पद के लिए भाजपा ने चंद्रप्रकाश चंद्रवंशी को टिकट दिया है। इसके अलावा पालिका के सभी 27 वार्ड में पार्षद पद के लिए प्रत्याशी उतारे हैं।

मां कर्मा के नाम से डाक टिकट हुआ जारी

बिलासपुर। भारत सरकार ने तैलिक समाज की मांग पूरी करते हुए भक्त माता कर्मा के नाम पर डाक टिकट जारी कर दिया है। टिकट जारी होने के साथ ही वर्षों पुरानी मांग पूरी करवाने की पहल करने वाले केंद्रीय शहरी और आवासन राज्यमंत्री तोखन साहू 1 लाख डाक टिकट वितरित करेंगे जिससे लिए आर्डर दें चुके हैं। साथ ही भारत सरकार द्वारा भी 2 लाख डाक टिकट वितरण किया जायेगा। गौरतलब हो कि केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य राज्य मंत्री श्री तोखन साहू 22 दिसंबर को भोपाल में अखिल भारतीय तैलिक साहू संघ के कार्यक्रम में शामिल हुए थे। जहां देशभर के साहू समाज के पदाधिकारियों ने केंद्रीय राज्यमंत्री श्री तोखन साहू से भक्त माता कर्मा के नाम पर डाक टिकट जारी करने की मांग की थी। जिस पर तुंरत एक्शन लेते हुए केंद्रीय राज्यमंत्री श्री तोखन साहू ने 15 दिन के भीतर समाज की यह मांग पूरी करने का आश्वासन दिया था और साहू समाज की वर्षों से लंबित मांग को महज 12 दिन में पूर्ण करवा दिया। भक्त माता कर्मा करोड़ों लोगों की आराध्य देवी हैं।

महिला वकील डिजिटल अरेस्ट की हुई शिकार

दुर्ग। छत्तीसगढ़ के दुर्ग कोर्ट में प्रैक्टिस करने वाली वकील फरीहा अमीन कुरैशी को ठगों ने आईपीएस अधिकारी बनकर धमकाया कि दिल्ली में एक आरोपी पकड़ा गया है। उसके पास आपके नाम का खाता मिला है, जिसमें 8.7 करोड़ का लेनदेन हुआ है। इसके बाद उन्होंने महिला को धमकाकर 41 लाख रुपए मंगवा लिए और ठगी की। महिला वकील ने दुर्ग कोतवाली थाने में मामले की शिकायत दर्ज कराई है। वकील ने बताया कि 21 जनवरी 2025 को सुबह 10.35 मिनट पर दिल्ली पुलिस डिपार्टमेंट का एक विडियो कॉल आया था। उसे यह बताया गया था कि सीबीआई, दिल्ली पुलिस संदीप कुमार के खिलाफ मनीलॉन्ड्रिंग, ड्रगट्रैफिकिंग और आईडेन्टिटी थेफ्ट केस की जांच कर रही है। जिस आरोपी को उन्होंने पकड़ा है, वह बड़ा अपराधी है। उसने कई लड़कियों का रेप कर उन्हें मौत के घाट उतार दिया है। इसलिए यह प्रकरण बहुत कॉनफिडेनशियल है। इसकी गोपनीयता भंग हुई तो तत्काल सीबीआई गिरफ्तार करेगी और काफी प्रताड़ित करेगी।

तेज रफ्तार ट्रक ने सरपंच प्रत्याशी को कुचला

गरियाबंद। जिले में एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। जहां दर्दनाक सड़क हादसे में सरपंच प्रत्याशी कुसुमा की मौके पर ही मौत हो गई है। तेज रफ्तार ट्रक प्रत्याशी कुसुमा को रौंदते हुए निकल गया। हादसे के बाद ट्रक चालक वाहन छोड़कर मौके से फरार हो गया है। पूरा मामला देवभोग थाना क्षेत्र का है। जानकारी के अनुसार, साहस खोल निवासी कुसुमा चंद्राकर अपने पति देवानंद चंद्राकर के साथ बाइक में सवार होकर ओडिशा की दिशा में जा रही थी। इस दौरान मोड़ पर एक ट्रक तेज रफ्तार को विपरीत दिशा से अचनाक आते देख बाइक अनियंत्रित होकर गिर गई। सड़क पर गिरने के बाद ट्रक ने सरपंच प्रत्याशी कुसुमा को कुचलते हुए गुजर गया। हादसे में कुसुमा की मौके पर ही मौत हो गई। मृतिका कोड़की पारा पंचायत में सरपंच पद की प्रत्याशी थी। पुलिस ने मामले में अज्ञात आरोपी के विरुद्ध बीएएनएस की धारा 281,106(1) के तहत मामला पंजीबद्ध किया है। वहीं मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है।

नक्सली प्रेस टीम के कमांडर ने पत्नी के साथ किया सरेंडर

मोहला मानपुर। छत्तीसगढ़ में लगातार नक्सल संगठन कमजोर होता जा रहा है। मोहला मानपुर जिला पुलिस को भी बड़ी कामयाबी मिली है। यहां माड़ डिविजन के प्रेस टीम के कमांडर ने पत्नी के साथ सरेंडर किया है। दोनों पर 5-5 लाख रुपए का इनाम घोषित था। कमांडर का नाम पवन तुलावी और पत्नी का नाम पायके ओयाम है। कमांडर की पत्नी केंद्रीय कमेटी सदस्य सोनू उर्फ भूपति की सुरक्षा गार्ड थी। सरेंडर करने वाला कमांडर पवन मानपुर ब्लॉक के बस्तर सीमावर्ती ग्राम दोरदे का का रहने वाला है। वह अबूझमाड़ के नक्सलियों की प्रेस टीम का कमांडर था। वहीं उसकी पत्नी पायके बीजापुर के भैरमगढ़ की रहने वाली थी और वह केंद्रीय कमेटी सदस्य सोनू उर्फ भूपति की सुरक्षा गार्ड थी।

जहां गूंजते थे लाल सलाम के नारे, अब सुनाई दे रही एबीसीडी

■ नक्सली लीडर हिडमा के गांव में खुला है स्कूल

सुकमा। बस्तर की तस्वीर अब बदलने लगी है। सीआरपीएफ 150वीं बटालियन ने नक्सलियों के टॉप कमांडर हिडमा के गांव में सीआरपीएफ गुरुकुल की शुरुआत की है, जहां आदिवासी बच्चे अपना भविष्य गढ़ रहे हैं। वहीं सरकार ने मार्च 2026 तक छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद खत्म करने का लक्ष्य रखा है, जिसे पूरा करने सुरक्षा बलों के जवान लगातार नक्सलियों के खिलाफ अभियान चला रहे।

सालभर पहले सीआरपीएफ की 150वीं बटालियन ने सुकमा के अति नक्सल प्रभावित पूवर्ती और टेकलगुडियम में बच्चों को शिक्षित करने के उद्देश्य से गुरुकुल शुरू किया था। यहां 50 से ज्यादा बच्चे पहुंच रहे हैं। सीआरपीएफ की पहल से अब नक्सल

प्रभावित गांव पूवर्ती व टेकलगुडियम के बच्चों को शिक्षा दी जा रही है। इस गांव में सुरक्षा बलों का कैंप भी खोला गया है, जिसका नक्सलियों ने विरोध किया था।

अति संवेदनशील नक्सल प्रभावित क्षेत्र पूवर्ती एवं टेकलगुड़ियम में दिसंबर 2024 से गुरुकुल का संचालन किया जा रहा है। यहां शुरुआत में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल 150 बटालियन के जवानों ने बच्चों को पढ़ाने का काम किया। बाद में अपने स्तर पर लोकल शिक्षक को हायर कर शिक्षा देने का कार्य किया जा रहा है। वर्तमान में गुरूकुल में प्राथमिक शिक्षा दी जा रही है। बच्चों को शिक्षा के अतिरिक्त स्कूल यूनिफार्म, किताबें, स्कूल बैग, शूज, शारीरिक एवं मानसिक विकास के लिए विभिन्न प्रकार के खेल-कूद जैसे बॉलीबाल, फुटबाल, वास्केटबाल एवं विभिन्न प्रकार के झूलों की खास व्यवस्था की गई है।

सीआरपीएफ गुरुकुल में विभिन्न प्रकार के चार्ट एवं बोर्ड दीवारों पर स्थापित किए गए हैं। समग्र विकास के लिए स्कूल में प्रोजेक्टर लगाना भी प्रस्तावित है। अब यहां बच्चे गांव में ही रहकर शिक्षा की अलख जला पाएंगे। अक्सर नक्सलवाद और नक्सली घटनाओं के लिए ही चर्चे में रहने वाला सुकमा जिला अब शिक्षा के क्षेत्र में नया बदलाव कर रहा है। जहां लाल सलाम के नारे गंजू करते थे वहां अब स्कूल की घंटी और बच्चों की एबीसीडी सुनने को मिल रही है। स्कूल गांव तक पहुंचा तो बच्चे गांव में ही रहकर शिक्षा से जुड़ पाए। अब वह बच्चा जो घर की देखभाल के लिए रोका जाता है वह भी शिक्षा से अछूता नहीं रहेगा।

गुरुकुल में टाइलेट, बाथरूम एवं हैंडपंप जिला प्रशासन से स्थापित किए जाने की संभावना है। साथ ही भविष्य में इसे बारहवीं कक्षा तक ले जाने का भी प्रयास किया जाना है। 150वीं वाहिनी सीआरपीएफ के एसएस हॉकीप द्वितीय कमान अधिकारी, विकास कुमार राय द्वितीय कमान अधिकारी, अमरेश्ज्ञ कुमार घोष उप कमांडेंट, भैरव प्रसाद उप कमांडेंट, अजय त्यागी सहायक कमांडेंट, मुकेश कुमार सिंह सहायक कमांडेंट, चंद्रप्रकाश तिवारी सहायक कमांडेंट, रवि चंदर सहायक कमांडेंट, राकेश कुमार शर्मा सहायक कमांडेंट की देखरेख में अति-संवेदनशील नक्सल प्रभावित क्षेत्र में सीआरपीएफ गुरुकुल का संचालन किया जा रहा है।

बालोद नगरीय निकाय चुनाव, 4 बार पार्षद का रिकॉर्ड, अब पांचवीं बार मैदान में

बालोद। नगरीय निकाय चुनाव का रण जारी है। बालोद जिले में एक ऐसे पार्षद प्रत्याशी है जो लगातार चार बात जीत चुके हैं। इस बार के निकाय चुनाव में अगर ये जीत जाते हैं तो इनके नाम लगातार पांचवीं बार जीतने का रिकॉर्ड बन जाएगा।

कमलेश सोनी बालोद नगर पालिका के वार्ड 2 से लगातार चार बार पार्षद रह चुके हैं। अब पांचवी बार चुनाव मैदान में खड़े हैं। कमलेश सोनी का दावा है कि इस बार भी वह पार्षद चुनाव जीतकर जनता की सेवा करेंगे।

कमलेश सोनी ने मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि लगातार उन्हें जनता का समर्थन मिल रहा है। सोनी ने बीजेपी का आभार जताते हुए कहा कि पार्टी हमेशा काम करने वाले कार्यकर्ताओं को चुनाव लड़ने का मौका देती है और जनता उस पर मोहर लगाती है। वार्ड 2 से

पार्षद प्रत्याशी और चार बार के पार्षद कमलेश सोनी ने कहा कि इस बार भी वे चुनाव जीतेंगे। उन्होंने कहा कि इस बार बालोद नगर पालिका का 10 साल का सूखा खत्म होने वाला है। नगर पालिका के 20 वार्डों में भाजपा के ही पार्षद चुने जाएंगे। विपक्ष को लेकर उन्होंने कहा कि 10 साल नगर पालिका में कोई काम नहीं हुआ। 11 फरवरी को भारी मतों से कमल फूल पर मोहर लगेगी।

संक्षिप्त समाचार

स्ट्रांग रूम पहुंचे राज्य निर्वाचन आयुक्त, चुनाव की तैयारियों का लिया जायजा

रायपुर। छत्तीसगढ़ में 11 फरवरी को नगरीय निकाय चुनाव के लिए मतदान होना है। निकाय चुनाव को लेकर प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। राज्य निर्वाचन आयोग के आयुक्त अजय सिंह गुरुवार को सेजबहार में बनाए गए स्ट्रांग रूम का निरीक्षण करने पहुंचे। निरीक्षण के दौरान स्ट्रांग रूम के सुरक्षा व्यवस्थाओं और अन्य अहम पहलुओं की जानकारी ली गई। इस निरीक्षण के दौरान राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव, जिला कलेक्टर गौरव कुमार सिंह, एसपी लाल उमेद सिंह और राज्य निर्वाचन आयोग सचिव भी मौजूद रहे। सुरक्षा उपायों और स्ट्रांग रूम की तैयारियों को लेकर अधिकारियों ने विस्तृत जानकारी ली। नगरीय निकाय चुनाव के लिए सेजबहार में बनाए गए स्ट्रांग रूम में अधिकारी-कर्मचारी के साथ राज्य निर्वाचन आयुक्त ने समीक्षा बैठक ली। जिसमें व्यवस्थाओं को लेकर गंभीर चर्चा की।

नवनियुक्त डीजीपी गौतम ने मुख्यमंत्री-उप मुख्यमंत्री शर्मा से की सौजन्य मुलाकात

रायपुर। नवनियुक्त पुलिस महानिदेशक अरुण देव गौतम ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के साथ उप मुख्यमंत्री अरुण साव से उनके निवास कार्यालय में सौजन्य मुलाकात की। इस दौरान मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ने नवनियुक्त डीजीपी को नई जिम्मेदारी के लिए शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अरुण देव गौतम से मुलाकात के दौरान प्रदेश में कानून-व्यवस्था, अपराध नियंत्रण, नागरिक सुरक्षा और पुलिस प्रशासन को और अधिक प्रभावी बनाने जरूरी दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने आधुनिक तकनीकों के समुचित उपयोग, जनसहभागिता और अनुशासित पुलिसिंग के माध्यम से प्रदेश में कानून-व्यवस्था को सुदृढ़ किए जाने पर बल दिया। वहीं उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने मुलाकात के दौरान मौजूद पूर्व डीजीपी अशोक जुनेजा से कहा कि आपने बहुत मेहनत करके काम किया है। नए डीजीपी से हमको उम्मीद है। हम अपेक्षा रखते हैं कि 2026 मार्च तक नक्सलवाद समाप्त होगा। इसमें कोई संदेह नहीं है।

10 साल आप ने किया धोखा, इस बार दिल्ली में बनेगी भाजपा की सरकार : साय

रायपुर। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है। मतदान के बाद एक्जिट पोल के रुझान सामने आने लगे। जिसमें सत्ता परिवर्तन के संकेत देखने को मिल रहे हैं। इस बीच छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने दिल्ली चुनाव में भाजपा की जीत का दावा किया है। उन्होंने निश्चित ही दिल्ली में भाजपा की सरकार बनने की बात कही है। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर मुख्यमंत्री साय ने कहा कि दिल्ली के चुनाव के एग्जिट पोल को देखते हुए देश की जनता का विश्वास भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ है। उन्होंने कहा कि इस बार निश्चित रूप से दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, क्योंकि 10 वर्षों तक आम आदमी पार्टी की सरकार ने जनता के साथ धोखा किया है।

अमेरिका में अवैध तरीके से रह रहे भारतीयों को वापस भेजने पर बिफरे बैज

रायपुर। अमेरिका ने अवैध तरीके से रह रहे 104 भारतीयों को वापस भारत भेज दिया है। अमेरिका को इस कदम को छत्तीसगढ़ कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने देश के लिए शर्मनाक बताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से माफी मांगने को कहा है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने मीडिया से चर्चा में कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति प्रवासी भारतीयों को अमेरिका से बाहर भेज रहे हैं। विश्वगुरु कहने वाले पीएम कहां गए हैं। इतनी शर्मनाक घटना, इतना अपमान भारत क्यों सह रहा है। इस घटना के लिए देश से उन्हें माफी मांगनी चाहिए। बता दें कि डोनाल्ड ट्रम्प ने अमेरिकी राष्ट्रपति का पद संभालने के बाद अवैध तरीके से रह रहे बाहरी लोगों को डिपोर्ट करने के आदेश दिए थे। इस कड़ी में 104 अवैध भारतीय प्रवासियों को लेकर अमेरिकी सैन्य विमान बुधवार (5 फरवरी) को अमृतसर के श्री गुरु रामदास जी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरा। भारत लाए गए 104 अप्रवासियों में सबसे ज्यादा हरियाणा और गुजरात के 33-33 लोग शामिल है। इसके अलावा पंजाब के 30, महाराष्ट्र के 3, उत्तर प्रदेश-चंडीगढ़ के 2 लोग शामिल हैं।

कांग्रेस के कुशासन के कारण 78 नगरीय निकाय अनुदान के लिए अपात्र हुए: सव्वनी

रायपुर। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष और नगरीय निकाय चुनाव प्रदेश प्रभारी भूपेंद्र सवन्नी ने 78 नगरीय निकायों के अपात्र होने को कांग्रेस की अक्षमता का एक और बड़ा नमूना बताया है। श्री सवन्नी ने कहा कि कांग्रेस की कारगुजारियों के कारण प्रदेश के रायपुर, दुर्ग सहित 78 नगरीय निकाय अनुदान के लिए अपात्र घोषित हो गए हैं। ऐसा निकम्मापन और भ्रष्टाचार कांग्रेस की पहचान बन गयी है।श्री सवन्नी ने कहा कि सवा साल पहले तक प्रदेश और महीने भर पहले तक निकायों में सत्ता सम्हालने वाली कांग्रेस के जनप्रतिनिधियों को निकायों के विकास से कोई लेना देना नहीं था। पिछले निकाय चुनाव में संविधान की हत्या करते हुए कानूनों को तोड़ मरोड़ कर सभी निगमों में बेजा कब्जा कर लिया और फिर उसे दिवालिया जैसी स्थिति में पहुंचा दिया। कांग्रेस कभी भी विकास को लेकर जरा भी संजीदा नहीं होती, उसे बस लूट मचाना होता है। भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष श्री सवन्नी ने कहा कि 15वें वित्त आयोग के तहत अनुदान प्राप्त करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन निकायों को करना अनिवार्य है। इसमें यह भी स्पष्ट किया गया है कि जो निकाय शर्तों का पालन करेंगे, वही अनुदान के लिए पात्र होंगे और बाकी निकाय अपात्र माने जाएंगे। अनुदान के लिए तय शर्तों की पूरी तरह अनदेखी करते हुए निकायों पर काबिज कांग्रेस के जनप्रतिनिधियों ने निगमों को रसातल में पहुंचा दिया। उन्होंने कहा कि ऐसी कांग्रेस को पूरे प्रदेश के निकायों से जनता को दूर रखना चाहिए। भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष श्री सवन्नी ने कहा कि नगरीय निकायों को भ्रष्टाचार और लूट-खसोट का अड्डा बनाकर रख देने वाले कांग्रेस के जनप्रतिनिधियों की इस गंभीर लापरवाही से यह साबित होता है कि कांग्रेसियों को जन-धन की लूट और उस लूट में अपनी-अपनी हिस्सेदारी की ही फिक्र रही और जनता की मूलभूत सुविधाओं व नगरीय क्षेत्र के विकास से उनका रत्तीभर सरोकार पूरे कार्यकाल में नहीं रहा।

कांग्रेस को फिर एक बार न्यायालय ने आइना दिखाया : विजय शंकर मिश्रा

रायपुर। भारतीय जनता पार्टी के चुनाव आयोग सम्पर्क समिति के प्रदेश प्रभारी डॉ. विजयशंकर मिश्रा ने धमतरी नगर निगम के कांग्रेस के महापौर प्रत्याशी विजय गोलछा द्वारा अपना नामांकन रद्द किए जाने के निर्णय के खिलाफ दायर की गई याचिका को उच्च न्यायालय द्वारा खारिज किए जाने पर कहा है कि अब पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समेत कांग्रेस के नेता प्रदेश की भाजपा सरकार पर सत्ता के दुरुपयोग व लोकतंत्र की हत्या जैसे प्रलाप करने से बाज आ जाएँ, क्योंकि यह वही कांग्रेस है जिसने अतीत में न जाने कितनी बार लोकतंत्र की हत्या की है। डॉ. मिश्रा ने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा मिथ्या प्रलाप करके प्रदेश को बरगलाने की कोशिश की है, लेकिन हर बार उसे न्यायालय में जाकर मुँह की खानी पड़ी है।

भाजपा चुनाव आयोग सम्पर्क समिति के प्रदेश प्रभारी डॉ. मिश्रा ने कहा कि धमतरी महापौर निर्वाचन-2025 हेतु भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उम्मीदवार विजय गोलछा का नॉमिनेशन फॉर्म अधिनियम की धारा 17 के अंतर्गत रिटर्निंग अधिकारी (धमतरी) द्वारा निगम में ठेकेदारी कार्य में उम्मीदवार के संलग्न होने के कारण निगम का प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष लाभार्थी होने के कारण निरस्त किया गया था। इसे लेकर बघेल समेत तमाम कांग्रेस नेता एक सुर में प्रदेश की भाजपा सरकार पर सत्ता के दुरुपयोग, लोकतंत्र की हत्या का आरोप लगाकर भाजपा नेताओं के खिलाफ ओछे दर्जे की टिप्पणियाँ करते प्रदेशभर में घूम रहे हैं। उत्तरवादी छत्तीसगढ़ शासन के अतिरिक्त आपत्तिकर्ता भाजपा उम्मीदवार जगदीश रोहरा का पक्ष अधिवक्ता अखिलेश कुमार द्वारा प्रस्तुत किया गया। न्यायमूर्ति विभु दत्त गुरु ने सुनवाई उपरांत विजय गोलछा द्वारा प्रस्तुत याचिका को प्रचलन योग्य न मानते हुए उसे इस आधार पर निरस्त किया कि निर्वाचन प्रक्रिया प्रारंभ होने के उपरांत नॉमिनेशन पेपर रद्द किए जाने के विषय को केवल चुनाव याचिका में ही चुनौती दी जा सकती है।

पीसीसी चीफ दीपक बैज ने बीजेपी पर साधा निशाना

कांग्रेस के घोषणा पत्र को बताया गेम चेंजर

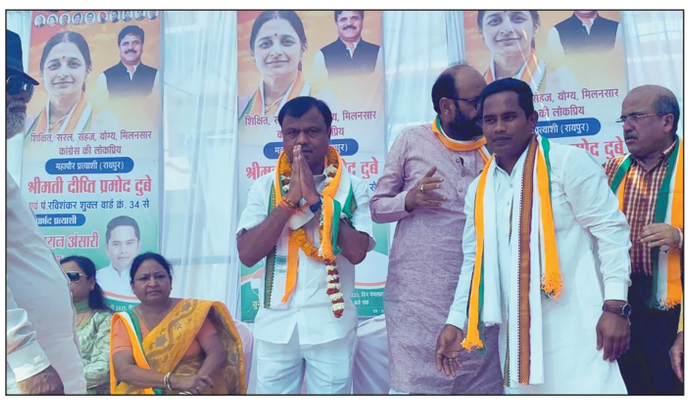

रायपुर। नगरीय निकाय चुनाव के वोटिंग में अब कुछ ही दिन बाकी हैं और राजनीतिक पार्टियां जोर-शोर से प्रचार में जुटी हुई हैं। इसी बीच कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने गुरुवार को रायपुर में महापौर और पार्षदों के पक्ष में प्रचार करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस के घोषणा पत्र को चुनावी 'गेम चेंजर' बताया। इसके साथ ही उन्होंने बीजेपी पर हमला भी बोला। बैज ने कहा कि बीजेपी के नेता हताश होकर घर बैठ चुके हैं और चुनाव में रुचि नहीं दिखा रहे हैं। उन्हें पता है कि एक साल में कुछ नहीं हुआ है। जनता उन्हें खदेड़ देगी इसलिए वे घर पर बैठे हैं।

पीसीसी चीफ दीपक बैज की आज रायपुर के विभिन्न वार्डों में कई जनसभाओं का आयोजन होगा। वहीं एक जनसभा में जब बैज पहुंचे तो उन्होंने पहले मीडिया से बातचीत की, जिसमें उन्होंने कांग्रेस के घोषणा पत्र को चुनावी गेम चेंजर बताया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की घोषणा पत्र जन-जन तक पहुंच रही है। प्रत्याशी भी दमदारी के साथ चुनाव में जुटे हुए है।

दीपक बैज ने बताया वे आज 12-13 सभाएं कांग्रेस के प्रत्याशियों के पक्ष में करने जा रहे हैं। जनता में कांग्रेस के लिए जबरदस्त उत्साह है और घोषणा पत्र सभी निकायों में गेम चेंजर साबित होगा।

कांग्रेस के घोषणा पत्र को कॉपी पेस्ट बताने वाले वाले बयान पर उन्होंने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस की 36 बिंदुओं की घोषणा पत्र है, जबकि बीजेपी की 20 बिंदुओं की गोल-गोल जलेबी है। एक साल में बीजेपी ने कुछ काम नहीं किया है इसलिए इस पत्र को जनता नकारेगी।

वहीं रायगढ़ के महापौर प्रत्याशी के लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय द्वारा चाय बनाने को लेकर उन्होंने कहा कि सीएम साय चाय बनाकर मोदी की कॉपी कर रहे हैं।

बीजेपी पर निशाना साधते हुए दीपक बैज ने कहा कि बीजेपी के नेता हताश होकर घर बैठ चुके हैं और चुनाव में रुचि नहीं दिखा रहे हैं। उन्हें पता है कि एक साल में कुछ नहीं हुआ है। जनता उन्हें खदेड़ेगी इसलिए घर पर बैठे हैं। सीएम सिर्फ अपनी क्षेत्र में जा रहे हैं, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सिर्फ़ जगदलपुर के ही नेता है। बीजेपी के नेता अपने क्षेत्र से बाहर नहीं निकल रही है। उन्होंने ये भी कहा कि निकाय चुनाव में कही अमित शाह स्टार प्रचारक बनकर तो नहीं आ रहे।

कृष्णा पब्लिक स्कूल में पालकों का हंगामा

सीजी बोर्ड मान्यता प्राप्त स्कूल में सीबीएसई के नाम से कराया एडमिशन

पालकों ने धोखाधड़ी का लगाया आरोप

रायपुर। राजधानी रायपुर से लगे आरंग स्थित कृष्णा पब्लिक स्कूल में बच्चों के भविष्य के साथ गंभीर लापरवाही का मामला सामने आया है। कृष्णा पब्लिक स्कूल को ष्टत्र बोर्ड से मान्यता प्राप्त होने के बाद भी प्रबंधन ने बच्चों को सीबीएसई बोर्ड पढ़ाई के नाम पर एड्मिशन करा लिया। पालकों से सीबीएसई बोर्ड की महंगी फीस ले ली गई, सालभर बच्चों को सीबीएसई कोर्स की पढ़ाई कराई गई, लेकिन बच्चों का रजिस्ट्रेशन सीजी बोर्ड में कर दिया। अब 5वीं और 8वीं के बच्चों को सीजी बोर्ड में एग्जाम देना होगा। केंद्रीकृत परीक्षा की तारीखों के ऐलान के बाद इस मामले का पूरा खुलासा हुआ, जिसके बाद आज पालकों ने स्कूल पहुंचकर हंगामा खड़ा कर दिया है।

इस मामले में जिला शिक्षा अधिकारी विजय खंडेलवाल ने बताया कि संभागीय संचालक ने जांच के दिए निर्देश दिए हैं। स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारी इस गंभीर लापरवाही के जांच के लिए स्कूल रवाना हो गए हैं। वहीं इस मामले की सूचना मिलने के बाद पालकों ने स्कूल में हंगामा खड़ा कर दिया है। बता दें इस स्कूल में सीआरपीएफ जवानों के बच्चों समेत सैकड़ों बच्चे अध्ययनरत हैं।

पालकों ने स्कूल प्रबंधन पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। पालकों ने बताया कि बच्चों के एडमिशन के समय उन्हें सीबीएसई से मान्यता प्राप्त होने की जानकारी दी गई थी। जबकि स्कूल को सीजी बोर्ड से मान्यता प्राप्त है। अब बच्चों का रजिस्ट्रेशन सीजी बोर्ड में कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि साल भर सीबीएसई की पढ़ाई के बाद 1 महीने में सीजी बोर्ड को लेकर बच्चों की तैयारी कैसे हो पाएगी ?

नवा रायपुर में दिखेगी ब्रिटिश कालीन जनजाति विद्रोह की झांकी

■ हल्बी या गोंडी बोली में होगा संग्रहालय का नाम

रायपुर। छत्तीसगढ़ के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी शहीद वीर नारायण की स्मृति में नवा रायपुर में पुरखौती मुक्तांगन के समीप निर्माणाधीन जनजातीय संग्रहालय का 70 प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका है। इस संग्रहालय में अंग्रेजी हुकुमत के दौरान हुए जनजातीय विद्रोहों की झांकी का निर्माण किया जा रहा है।

आदिम जाति, अनुसूचित जाति तथा पिछड़ा वर्ग विभाग के प्रमुख सचिव सोनमणि बोरा ने निर्माणाधीन संग्रहालय का आज निरीक्षण किया और संग्रहालय निर्माण की धीमी गति पर अप्रसन्नता व्यक्त की। उन्होंने संग्रहालय के शेष कार्य गुणवत्ता के साथ जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों, ठेकेदारों और क्यूरेटर का एक दल बनाकर एक-एक गैलेरी का कार्य उत्कृष्ट गुणवत्ता के साथ शीघ्र पूर्ण कराने के निर्देश दिए।

प्रमुख सचिव बोरा ने कहा कि संग्रहालय के आस-पास जल जमाव की स्थिति निर्मित न हो, इस पर विशेष रूप से ध्यान रखा जाए। उन्होंने मुख्यद्वार के पास वाटर फॉउटेन भी लगाने के निर्देश दिए। उन्होंने संग्रहालय का नाम हल्बी एवं गोंडी बोली में भी अंकित करने के निर्देश दिए। उन्होंने संग्रहालय के भीतर लगने वाली दुकानों को ट्राइफेड को दिए जाने के संबंध में कार्यवाही पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि संग्रहालय परिसर सौर ऊर्जा से उत्पन्न विद्युत से जगमगा सके, इसे ध्यान में रखते हुए सोलर प्लांट स्थापना की जाए। इस अवसर पर आदिम जाति विकास विभाग के आयुक्त पदुम सिंह ऐल्मा सहित विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित थे।

संभागायुक्त ने ली राजिम कुंभ तैयारियों की समीक्षा बैठक

रायपुर। 12 फरवरी से शुरू हो रहे राजिम कुंभ (कल्प) मेला 2025 की तैयारियों की समीक्षा के लिए संभागायुक्त श्री महादेव कावरे ने बैठक ली। इसमें मोबाइल नेटवर्किंग सुविधाओं की उपलब्धता और अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं की प्रगति पर चर्चा हुई। श्री कावरे ने मेला स्थल, कंट्रोल रूम नवापार, और लोमस ऋषि आश्रम क्षेत्र में भी नेटवर्किंग की बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने कहा।

उल्लेखनीय है कि राजिम कुंभ मेले का आयोजन 12 फरवरी 2025 (माघ पूर्णिमा) से 26 फरवरी 2025 (महाशिवरात्रि) तक किया जाएगा। श्री कावरे द्वारा ली गई बैठक में अधिकारियों ने बताया कि मेला स्थल पर मोबाइल नेटवर्किंग से संबंधित तैयारियां 20 दिन पहले ही पूरी कर ली जाएंगी। साथ ही आवश्यकता पडऩे पर कंट्रोल रूम में एयर फाइबर की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी और मेला स्थल पर 24 घंटे तकनीशियन और मैकेनिक की उपस्थिति सुनिश्चित की जाएगी।

बैठक में लोक निर्माण विभाग, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, और नगरपालिका गोबरा-नवापारा द्वारा किए जा रहे कार्यों की धीमी गति पर भी चर्चा हुई। इस पर अपर जिला दंडाधिकारी, रायपुर को निर्देशित किया गया कि कार्यों में तेजी लाकर तय समय-सीमा के भीतर गुणवत्ता के साथ पूर्ण किया जाए। बैठक में अपर कलेक्टर एवं दंडाधिकारी श्री देवेंद्र पटेल, बीएसएनएल रायपुर के एजीएम श्री एस.के. झा, रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड रायपुर के मैनेजर मोहम्मद अली चिश्ती, एयरटेल रायपुर के महाप्रबंधक श्री देवेंद्र त्रिपाठी और श्री महेन्द्र राजपूत सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

नशे में धुत युवती ने एक्टिवा सवार युवकों को मारी टक्कर

रायपुर। राजधानी रायपुर के रोड पर आधी रात को एक बड़ा सड़क हादसा हो गया, जिसमें एक तेज रफ्तार टाटा इंडिगो कार ने एक्टिवा सवार तीन युवकों को सामने से टक्कर मार दी। इस हादसे में तीनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, इंडिगो कार में एक युवक और एक युवती सवार थे जो शराब पीए हुए थे।

प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि, हादसे के समय युवती कार चला रही थी और युवक युवती की गोद में बैठा था। हादसे के बाद मौके पर पहुंची पुलिस के सामने हीयुवती ने सड़क पर ही जमकर हंगामा मचाया और मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों से भी झुमाझटकी की। इतना ही नहीं नशे में धुत युवती ने थाने पहुंचकर भी जमकर हंगामा मचाया। कार के सामने लोक अभियोजक और सरकारी वकील लिखा हुआ है। वहीं, कार में मिले विजिटिंग कार्ड के आधार पर भावेश आचार्य आरोपी युवक का नाम सामने आया है। हादसे में एक्टिवा सवार तीनों युवक नीलकमल साहू, ललित चंदेल और अरुण विश्वकर्मा घायल हुए है, जिन्हें मेकाहारा में भर्ती कराया गया है।

घायलों के स्वजनों के मुताबिक, तीनों युवक एक शादी हॉल से फोटोग्राफी का काम खत्म करके घर जा रहे थे, तभी सामने से आई तेज रफ्तार इंडिगो कार ने जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतना भयानक था कि, एक्टिवा के परखच्चे उड़ गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है।

आयकर सर्वे में रायपुर और धमतरी के सर्राफा कारोबारियों की कर चोरी उजागर

■ कारोबारियों ने कबूली कर चोरी, अग्रिम कर के रूप में 4.5 करोड़ जमा करने का निर्देश

रायपुर। आयकर विभाग के असेसमेंट विंग ने रायपुर और धमतरी में स्थित दो प्रमुख सर्राफा व्यापारियों द्वारा 15 करोड़ की कर चोरी का पर्दाफाश किया है। यह खुलासा विभाग द्वारा किए गए 30 घंटे से अधिक चले विस्तृत सर्वेक्षण में हुआ, जिसमें ए. एम. ज्वेलर्स (रायपुर) और श्री सेठिया ज्वेलर्स (धमतरी) के व्यावसायिक दस्तावेजों की गहन जांच की गई। सर्वेक्षण के दौरान इन प्रतिष्ठानों में बेहिसाब सोने की बड़ी मात्रा, अवैध धन लेन-देन और अकाउंट बुक्स से बाहर किए गए निवेश का खुलासा हुआ।

आयकर अधिकारियों द्वारा गहन पूछताछ के बाद ए. एम. ज्वेलर्स के संचालक सुनील पारख और उनके पुत्र अंकित पारख ने 10 करोड़ की कर चोरी स्वीकार की, जबकि श्री सेठिया ज्वेलर्स के संचालक राहुल सेठिया ने 5 करोड़ की कर चोरी की बात कबूल की। ए. एम. ज्वेलर्स की कर चोरी 12 किलोग्राम अतिरिक्त स्वर्ण आभूषणों के रूप में सामने आई, जबकि श्री सेठिया ज्वेलर्स ने 6 किलोग्राम अतिरिक्त सोने के भंडार पर कर देनदारी छिपाई। परिणामस्वरूप, दोनों प्रतिष्ठानों को क्रमशः 3 करोड़ और 1.5 करोड़ का अग्रिम कर 15 मार्च तक जमा करने का निर्देश दिया गया है, साथ ही कर चोरी पर अतिरिक्त दंड भी लगाया जाएगा, असेसमेंट विंग के सूत्रों ने पुष्टि की।

जांच में यह भी खुलासा हुआ कि दोनों सर्राफा व्यापारियों ने एक संगठित तंत्र विकसित कर नकद बिक्री को आधिकारिक रिकॉर्ड से छुपाया। ये व्यापारी अपने स्वर्ण आभूषणों को छत्तीसगढ़ और ओडिशा के दूर-दराज क्षेत्रों के छोटे व्यापारियों को आपूर्ति कर रहे थे, जिनका भुगतान नकद में किया जाता था, जिससे यह पूरी आय कर व्यवस्था के बाहर रह जाती थी। सर्वेक्षण के दौरान श्री सेठिया ज्वेलर्स के परिसर से बड़ी संख्या में प्रॉमिसरी नोट्स भी जब्त किए गए, जिससे यह स्पष्ट हुआ कि यह प्रतिष्ठान अवैध रूप से गिरवी रखे गए गहनों के बदले नकद उधार देने के व्यवसाय में भी शामिल था। इस लेन-देन की पूरी रकम, जिसमें नकद आगमन और निर्गमन शामिल था, को अकाउंट बुक्स से पूरी तरह बाहर रखा गया था, असेसमेंट विंग के सूत्रों ने जानकारी दी।

इसी बीच ए. एम. ज्वेलर्स के स्वामियों द्वारा बेहिसाब नकदी से अचल संपत्ति में निवेश किए जाने के प्रमाण भी सामने आए, जिससे यह संकेत मिलता है कि इस वित्तीय वर्ष 2024-25 में उजागर की गई 15 करोड़ की कर चोरी केवल शुरुआती आंकड़ा हो सकता है। पिछले वित्तीय वर्षों की जांच जारी है, और यह राशि और बढ़ सकती है। सर्वेक्षण के बाद की प्रक्रिया के तहत कर अधिकारियों ने दोनों सर्राफा व्यापारियों के बयान आयकर अधिनियम की धारा 133 (ए) (1) के तहत दर्ज कर लिए हैं। आगे की जांच और दस्तावेजी प्रमाणों की समीक्षा के लिए उन्हें शीघ्र ही फिर से पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा।

मंगलवार दोपहर 12:30 बजे शुरू हुए इस सर्वेक्षण का संचालन मुख्य आयकर आयुक्त अपर्णा करन और प्रधान आयकर आयुक्त प्रदीप हेडाउ की देखरेख में किया गया, जबकि फील्ड ऑपरेशन संयुक्त आयुक्त बीरेंद्र कुमार और उप आयुक्त राहुल मिश्रा के नेतृत्व में हुआ। रायपुर में 22 कर अधिकारियों, फोरेंसिक विशेषज्ञों, सरकारी स्वीकृत मूल्यांकनकर्ताओं और सशस्त्र पुलिसकर्मियों सहित कुल 32 सदस्यों की टीम तैनात की गई थी, जबकि धमतरी में 16 कर अन्वेषकों, फोरेंसिक विशेषज्ञों, स्वर्ण मूल्यांकनकर्ताओं और पुलिसकर्मियों सहित कुल 22 सदस्यों की टीम ने ऑपरेशन को अंजाम दिया। सशस्त्र पुलिसकर्मियों की तैनाती किसी भी संभावित प्रतिरोध को रोकने के लिए की गई थी।

इस सर्वेक्षण में नकद उत्पन्न करने के लिए फर्जी बिलिंग तंत्र, कर चोरी के लिए बनाई गई फर्जी व्यय प्रविष्टियां और डिजिटल लेन-देन के अनेक अनियमितताओं का भी खुलासा हुआ। जांचकर्ताओं ने लैपटॉप, मोबाइल फोन और अन्य डिजिटल डेटा भंडारण उपकरणों से डिजिटल साक्ष्य का क्लोनिंग कर कई गंभीर वित्तीय विसंगतियों को चिह्नित किया।

इस कार्यवाही में नागपुर से आए स्वर्ण मूल्यांकनकर्ताओं और मुंबई के साइबर फोरेंसिक विशेषज्ञों की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही, जिन्होंने सोने की सही कीमतों की पुष्टि के साथ-साथ डिजिटल डेटा से साक्ष्य एकत्र किए। आयकर विभाग इस कार्रवाई को उच्च-मूल्य वाले सर्राफा व्यापारियों पर सख्ती बढ़ाने की दिशा में एक बड़ा कदम मान रहा है। कर अधिकारियों ने संकेत दिए हैं कि इसी तरह की सख्त कार्यवाहियां जल्द ही अन्य बड़े व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर भी की जाएंगी, ताकि नकद-आधारित उद्योगों में कर चोरी को पूरी तरह रोका जा सके।

टैरिफ को हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहे ट्रंप

अभिनय आकाश

तारीख पे तारीख तारीख पे तारीख साल 1993 में सनी देओल की दामिनी फिल्म का आइकॉनिक डॉयलाग तो आप सभी ने सुना ही होगा। लेकिन इन दिनों ट्रंप टैरिफ पे टैरिफ वाले डॉयलाग को चरितार्थ करते नजर आ रहे हैं। ट्रंप ने टैरिफ वॉर छेड़ दी है। अमेरिका ने पहले तो कनाडा, मैक्सिको और चीन पर जबरदस्त टैरिफ लगाने की घोषणा कर दी। शपथ लेने के तुरंत बाद ट्रंप ने उन एक्सीक्यूटिव ऑर्डर को साइन किया, जिसमें कनाडा और मैक्सिको पर 25 प्रतिशत और चीन पर 10 प्रतिशत टैरिफ लगाने की बात कही गई थी। एक फरवरी से इसे शुरू होना था। लेकिन किसी तरह कनाडा और मैक्सिको ने इसके लिए ट्रंप को मना लिया। फिलहाल 30 दिनों के लिए दोनों देशों को मोहलत दे दी है। लेकिन यहां पर चीन का नंबर अभी तक नहीं लगा। चीन पर लगा 10 प्रतिशत टैरिफ एक फरवरी से शुरू हो चुका है। जिसके बाद अमेरिका और चीन के बीच ट्रेड वॉर शुरू हो गया है। दोनों देशों ने अपने हितों का हवाला देते हुए एक दूसरे पर टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया है। अमेरिकी की तरफ से 10 प्रतिशत टैरिफ का जवाब चीन ने 10 से 15 प्रतिशत टैरिफ लगाकर दिया है। चीन के अखबार ग्लोबल टाइम्स में बताया गया कि 10 फरवरी से अमेरिका से आयातित कुछ वस्तुओं पर अतिरिक्त टैरिफ लगाएगा। अमेरिका के प्रेसिडेंट के तौर पर कम बैक करने के बाद दुनिया में ट्रेड वॉर की शुरुआत होती नजर आ रही है। लेकिन इस टैरिफ वॉर में ट्रंप ने भारत को रियायत दी है। तो आज हम इसी विषय का एमआईआई स्कैन करेंगे कि ट्रंप ने ऐसा क्यों किया है, क्या है ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी, टैरिफ होता क्या है और इससे अमेरिका पर क्या असर पड़ेगा। जिन देशों पर टैरिफ लगाया गया है उन पर क्या असर पड़ेगा। सरल भाषा में कहे तो टैरिफ मतलब टैक्स जो दूसरे देशों से आने वाले सामान पर लगाया जाता है। जैसे मान लीजिए की आपने चीन से कोई मोबाइल मंगवाया तो अब उसकी वास्तविक कीमत पर एक्ट्रा 10 प्रतिशत का टैक्स देना पड़ेगा। इसका मतलब की अमेरिकी कंपनियां चीन से कुछ मंगवाएंगी तो उनको ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे। इसमें आपको साफ कर दें कि ट्रंप ने टैरिफ लगाया तो कनाडा, मैक्सिको या जिनपिंग के चीन को अपनी जेब से पैसा भरना होगा। असल में ये टैक्स अमेरिकी कंपनियों को देना पड़ता है जो इन देशों से सामान मंगवाती हैं। मतलब इंपोर्टर जो ये सामान खरीदते हैं ये टैक्स सरकार को देते हैं। ये पैसा वो जाहिर है अपनी जेब से तो भरेंगे नहीं और इसका असर ग्राहकों पर पड़ेगा। नतीजतन महंगाई बढ़ेगी। आम अमेरिकी जनता को ज्यादा दाम चुकाने पड़ेंगे। ट्रंप का कहना है कि अमेरिका में फैक्ट्री बंद हो रही है। जॉब बाहर जा रहे हैं। ट्रेड डेफेसिट बढ़ रहा है। उनकी कोशिश है कि अमेरिकी कंपनी को बाहर से सामान मंगवाने की बजाए खुद अमेरिका में प्रोडक्शन करने के लिए मजबूर किया जाए। अमेरिकी कंपनी को टैक्स में छूट मिले जिससे वो अमेरिका में ही फैक्ट्री लगाएं। इसके साथ ही गैर कानूनी अप्रवासी और ड्रग्स की सप्लाई रोकने के लिए भी टैरिफ को हथियार की तरह इस्तेमाल किया जाए। अतीत में अगर अमेरिका किसी देश से व्यापार करता था तो इसके ऐवज में उस देश की वैश्विक मुद्दों पर अलिखित सहमति रहती थी। यूएन और उसकी तमाम संस्थाएं अमेरिका के फंड से चलती रही हैं। विश्व बैंक और आईएमएफ में आज भी अमेरिकी और यूरोपियन प्रमुख ही होते हैं। यह सच है कि अमेरिकी व्यापार में असंतुलन है और भारत के अलावा चीन को भी उसका लाभ मिलता है। चीन 120 से अधिक देशों के लिए प्रमुख व्यापार भागीदार है और अमेरिका उनमें से एक है। पिछले दो दशकों में चीन ने अपनी अर्थव्यवस्था में व्यापार के महत्व को लगातार कम किया है और घरेलू उत्पादन में बढ़ोतरी की है। आज आयात और निर्यात का चीन के सकल घरेलू उत्पाद में केवल 37% हिस्सा है, जबकि 2000 के दशक की शुरुआत में यह 60% से अधिक था। 10% टैरिफ चभेगा, लेकिन पेइचिंग इस झटके को बर्दाश्त कर सकता है। अमेरिका पर इसका प्रभाव सीमित हो सकता है। अमेरिका दुनिया में तरल प्राकृतिक गैस का सबसे बड़ा निर्यातक है, लेकिन उस निर्यात में चीन की हिस्सेदारी केवल 2.3% के आसपास है। चीन का सबसे बड़ा कार आयात यूरोप और जापान से होता है। एक्सपर्ट इसे चीन की सौदेबाजी की शक्ति हासिल करने के तरीके के तौर पर देख रहे हैं। अमेरिका अगर भारतीय व्यापार पर टैक्स लगाता है, तो भारत को अपने माल को स्तरीय और सस्ता बनाना होगा यानी इसे एक अवसर के रूप में लेना होगा। एक्सपर्ट का मानना है कि अमेरिका और चीन के बीच व्यापार युद्ध भारतीय निर्यातकों के लिए फायदेमंद हो सकता है। इस कदम से अमेरिकी बाजार में भारतीय निर्यात बढ़ने की उम्मीद है।

संतुलित बजट कहा जाना अतिश्योक्ति नहीं

मोहनदास

केंद्रीय बजट-2025 लंबे समय से चली आ रही एक महत्वपूर्ण चिंता को संबोधित करता है: भारत के मध्यम वर्ग की वित्तीय भलाई। पिछले कई वर्षों में, मुद्रास्फीति, उच्च कर और स्थिर आय वृद्धि ने घरेलू बचत और खर्च को बाधित किया है। यह बजट कर कटौती और कल्याणकारी उपायों में मध्यम वर्ग को व्यापक रूप से शामिल करके उसे बहुत जरूरी राहत प्रदान करता है। साथ ही, यह बजट राजकोषीय विवेक, आर्थिक सुधारों और उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है, जो भारत के सतत विकास के मार्ग में प्रमुख तत्व हैं। आय स्लैब और संशोधित कर संरचना के आधार पर व्यक्तियों को 50,000 रुपये से लेकर अधिक राशि तक की कर बचत देखने को मिल सकती है, जिससे प्रयोज्य आय में वृद्धि होगी। संशोधित कर संरचना में सालाना 12.75 लाख रुपये तक की आय वाले वेतनभोगी कर्मचारियों को कोई कर नहीं चुकाना है, जिससे मध्यम वर्ग के परिवारों पर वित्तीय बोझ काफी हद तक कम हो गया है। हालांकि इसमें आगे और सरलीकरण की आवश्यकता है, विशेष रूप से, वर्तमान बहु-स्लैब संरचना के बजाय तीन-स्लैब प्रणाली को अपनाना, लेकिन समग्र रूप से कर राहत एक सकारात्मक कदम है।

वित्तीय अनुशासन : बजट में व्यय और राजकोषीय विवेक के बीच सावधानीपूर्वक संतुलन बनाए रखा गया है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए राजकोषीय घाटे को 4.8 फीसदी से घटाकर 4.4 फीसदी कर दिया गया है, जो जिम्मेदार वित्तीय प्रबंधन का संकेत है। इसके अतिरिक्त, उधारी को समान स्तर पर रखा गया है, जिससे ऋण बाजार पर अतिरिक्त दबाव को रोका जा सके। नियंत्रित घाटे और

अनुशासित उधारी से निजी क्षेत्र की तरलता में सुधार होगा, जिससे ब्याज दरें कम होंगी और निवेश के माहौल में सुधार होगा। सरकार ने पूंजीगत व्यय के लिए 11.21 लाख करोड़ रुपये से अधिक का आवंटन किया है, जिसमें उन बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को प्राथमिकता दी गई है, जिनसे दीर्घकालिक आर्थिक लाभ होगा।

एमएसएमई एवं स्टार्टअप को समर्थन : भारतीय?अर्थव्यवस्था की रीढ़ सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र को नीतिगत उपायों के माध्यम से महत्वपूर्ण समर्थन मिला है। ऋण गारंटी योजना को बढ़ाने और मुद्रा योजना के तहत ऋण सीमा बढ़ाने से पूंजी तक आसान पहुंच होगी, उद्यमशीलता और छोटे व्यवसाय के विस्तार को बढ़ावा मिलेगा। सबसे उल्लेखनीय घोषणाओं में से एक है स्टार्टअप के लिए समर्पित 10,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त आवंटन, जो मौजूदा 10,000 करोड़ रुपये के योगदान का पूरक है। यह सही दिशा में उठाया गया कदम है। करीब 50,000 करोड़ रुपये का एक बड़ा कोष भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम की बढ़ती पूंजी जरूरतों को बेहतर ढंग से पूरा करेगा। डीप-टेक इनोवेशन पर सरकार का नए सिरे से ध्यान केंद्रित करना एक सकारात्मक कदम है, जो प्रौद्योगिकी-संचालित उद्योगों में अत्याधुनिक प्रगति को बढ़ावा देता है।

सरल होंगी प्रक्रियाएं : भारत का विनियामक वातावरण जटिल बना हुआ है। यह बजट उसे सरलीकृत करने की दिशा में कदम उठाता है। एक नई प्रस्तावित विनियामक समिति गैर-वित्तीय विनियमनों की देखरेख करेगी, जबकि मौजूदा वित्तीय विनियामक निकाय वित्तीय क्षेत्र के नियमों को सुव्यवस्थित करेंगे। इन परिवर्तनों का उद्देश्य लालफीताशाही को कम करना और यह सुनिश्चित करना है कि व्यवसाय अधिक आत्मविश्वास और दक्षता के साथ काम कर सकें। विशेष रूप से भारतीय रिजर्व बैंक जैसी संस्थाओं का अधिक लचीला दृष्टिकोण व्यापार सुगमता को बढ़ाएगा और वैश्विक वित्तीय केंद्र बनने की भारत की महत्वाकांक्षा का समर्थन करेगा।

कृषि को मजबूती और ग्रामीण विकास: कृषि क्षेत्र में उत्पादकता और लचीलेपन को बढ़ाने के उद्देश्य से ऋण प्रवाह में वृद्धि की गई है। कम उत्पादकता से जूझने वाले 100 जिलों पर विशेष ध्यान दिया गया है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि लक्षित हस्तक्षेप ग्रामीण अर्थव्यवस्थाओं को ऊपर उठा सकें। सरकार ने उच्च उपज वाली फसलों के लिए एक राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम भी शुरू किया है, जिससे 170 लाख किसानों को लाभ होगा और सब्सिडी वाले ऋण की सीमा में वृद्धि होगी। राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन की शुरुआत कृषि उत्पादकता और स्थिरता को और बढ़ावा देगी, जिससे औद्योगिक विकास ग्रामीण विकास के साथ जुड़ता है।

समावेशी विकास और सामाजिक कल्याण : इस बजट का मुख्य विषय समावेशी विकास है, जिसमें किसानों, युवाओं, महिलाओं और वंचित क्षेत्रों के लिए बढ़ा हुआ समर्थन घोषित किया गया है, जिसका उद्देश्य समान विकास और आर्थिक सुरक्षा को बढ़ावा देना है। स्वास्थ्य सेवा में एक बड़ी राहत के रूप में 36 जीवन रक्षक दवाओं और औषधियों को मूल सीमा शुल्क से पूरी तरह छूट दी गई है, जिससे लाखों लोगों के लिए महत्वपूर्ण उपचार अधिक सुलभ और किफायती हो गए हैं।

आर्थिक लचीलापन : कुल प्राप्तियों के साथ सरकार का सकल कर संग्रह बेहतर बना हुआ है, जो मजबूत वृद्धि का भी प्रमाण है। 2025-26 के लिए अनुमानित राजस्व में मामूली समायोजन के, खासकर व्यक्तिगत कर संग्रह में, जो रिफंड से पहले ही सकल आधार पर काफी बढ़ गया है, कर अनुपालन के उच्च बने रहने के संकेत मिलते हैं। यह उपरिगामी रुझान एक लचीली अर्थव्यवस्था को रेखांकित करता है, जिसमें निरंतर राजस्व का प्रवाह दिखता है, जो वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद मजबूत आर्थिक गतिविधि को दर्शाता है।

आगे की राह : यह बजट राजकोषीय अनुशासन को रणनीतिक निवेशों के साथ संतुलित करते हुए सतत विकास का एक ठोस आधार निर्मित करता है। मध्य वर्ग को कर राहत व एमएसएमई व स्टार्टअप को वित्तीय सहायता मुहैया कराने वाला यह बजट दीर्घकालीन आर्थिक लचीलेपन को लेकर प्रतिबद्धता का संकेत देता है। विनियामक सरलीकरण, पूंजी में वृद्धि व्यय, और क्षेत्र-विशिष्ट सुधार एक दूरदर्शी दृष्टिकोण का संकेत देते हैं। कुछ क्षेत्र, जैसे स्टार्टअप में गहरे निवेश, करों का उत्तरोत्तर सरलीकरण और विनियामक छूट में आगे भी सुधार के अवसर बने हुए हैं। कुल मिलाकर, बजट एक व्यावहारिक दृष्टिकोण को दर्शाता है, जो भारत के अधिक समृद्ध और नवाचारी अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में विकास पथ को मजबूत करता है।

एकात्मता के स्वर — प्रयागराज

तीर्थराज प्रयाग उत्तरप्रदेश राज्य में स्थित है। यहाँ पर सभी देवता, दिशा, दिक्पाल, लोकपाल, सांध्य, लोकसम्मानित, पितर, सनत्कुमार, महर्षि अंगिरा आदि निर्मल महर्षि, नाग, सुपर्ण, सिद्ध, सूर्य, नदी, समुद्र, गन्धर्व, अप्सरा तथा ब्रह्मा जी सहित भगवान् विष्णु स्वयं निवास करते हैं। यहाँ पर तत्र त्रीण्यग्निकुण्डानि येषां मध्येन जाह्नवी।

तीन अग्नि कुण्ड हैं जिनके बीच से सब तीर्थों से सम्पन्न विष्णुजा भगवती भागीरथी गंगा वेगपूर्वक बहती हैं। त्रिभुवनविख्यात सूर्यपुत्री लोकपावनी यमुनादेवी वहाँ गंगाजी के साथ मिलती हैं। गंगा और यमुना का मध्यभाग पृथ्वी का जघन माना गया है। प्रयाग में दश तीर्थसहस्त्राणि षष्टि: कोट्यस्तथापरा। साठ करोड दस हजार तीर्थों का वास बताया गया है। प्रयाग में ही भोगवती नाम से प्रसिद्ध वासुकिनाग का उत्तम तीर्थ है। यहीं पर हंसप्रपतन तथा दशाश्वमेधिक तीर्थ हैं।

गंगा में कहीं भी स्नान किया जाये वह कुरुक्षेत्र के समान पुण्यदायी है पर प्रयागे परमं महत प्रयाग में गंगा स्नान का माहात्म्य सबकी अपेक्षा बहुत अधिक है। सत्ययुग में सभी तीर्थ पुण्यदायक होते हैं। त्रेता में पुष्कर का महत्त्व है। द्वापर में कुरुक्षेत्र विशेष पुण्यदायक है। सर्व कृतयुगे पुण्यं त्रेताया पुष्करं स्मृतम्। द्वापरेऽपि कुरुक्षेत्रं गंगा कलियुगे स्मृता।। और कलियुग में गंगा की अधिक महिमा बतायी गयी है। यहाँ पर साठ हजार धनुर्धर वीर गंगा की रक्षा करते हैं सात घोडों से जुते हुए रथ पर चलने वाले सूर्य सदा यमुना की देखभाल करते रहते हैं। इन्द्र विशेष रूप से प्रयाग की सदा रक्षा में तत्पर रहते हैं। षष्टिर्धनु: सहस्त्राणि यानि रक्षति जाह्नवीम्। यमुनां रक्षन्ति सदा सविता सप्तवाहन:।।

प्रयागं तु विशेषेण सदा रक्षति वासव:। भगवत्पार्षद महामना शिवशर्मा से कहते हैं कि मैंने पूर्वकाल में सब यज्ञों को एक ओर तराजू पर रखा और दूसरी ओर तीर्थराज प्रयाग को रखा, किंतु उसी (प्रयाग) का पलड़ा भारी रहा। अक्षय वट के मूल के समीप और संगम आदि में मृत्यु को प्राप्त मनुष्य विष्णु के धाम में जाता है। काशी से भी सौ गुना पुण्य पश्चिमाभिमुखी गंगा जहाँ यमुना के साथ मिलती है वहाँ स्नान करने से प्राप्त होता है।

गंगा-यमुना का संगम वेणी (त्रिवेणी) के नाम से प्रसिद्ध है। माघ मकरगति रवि जब होई। तीरधपति आवे सब कोई।। रा. मानस। माघ के माह में जब सूर्य मकर राशि पर होता है तब एक मास तक प्रयाग का वास जिसे %कल्पवास% कहा जाता है, के करने से उत्तम फल की प्राप्ति होती है। गया में जो फल पिण्डदान से मिलता है वही पुण्य प्रयाग में मुण्डन कराने से प्राप्त होता है।

पुराण दिग्दर्शन .... तीसरा अध्याय

वेदों में अष्टादश पुराणों के नाम

(गतांक से आगे...)

उसने (नारद के कहने से) भय नामक अपने सहोदर भाई को ही वर लिया था । वह भी अपने पति सहित बलात् पुरंजन के नगर में घुस गई और उसकी यवन फौज ने दरवाजों के रास्तों से नगर में प्रवेश करके समस्त पुर को कुचल डाला। इतने में भय का बड़ा भाई प्रज्वर भी आ पहुँचा और उसने अपने भ्राता की सहायता के लिये पुरंजन के नगर में सब जगह आग लगा दी और बलवान् यवन ने जबर्दस्ती पुरंजन को गिरफ्तार कर लिया। उस समय पुरंजन ऐसा अन्धकार में पड़ा कि अपने बचाने वाले अज्ञात मित्र को भी न बुला सका।

उपर्युक्त कथा में लौकिक शब्दों द्वारा किसी विलासी राजा के जीवन का और उसके अन्तिम परिणाम का चित्रण किया है। लोक में प्राय: जैसी घटनाएं नित्य घटती हैं वैसी वैसी घटनाओं के उल्लेख से उक्त सन्दर्भ में पाठकों के हृदयों को कर्तव्य पालन की ओर आकृष्ट करने का प्रयत्न किया है। साक्षात्पशु: पुच्छ-विषाणहीन: के अतिरिक्त शायद ही कोई सहृदय पुरंजन के इस दु:खान्त नाटक को पढ़कर समवेदना अनुभव किये बिना रहे। रह रहकर यह भाव हृदयं में प्रवृद्ध होते हैं कि ऐसा प्रभुत्वशाली और सर्वसाधन-सम्पन्न राजा यदि विलासिता के चक्कर में पड़कर, अपने स्वरूप को भूल, कर्तव्यपराङ्मुख न होता तो कदाचित् अन्त में उसका इस प्रकार अपमानपूर्वक सर्वनाश न होता। इन सब भावों की, जागृति का मूलकारण उपर्युक्त घटनाओं से मिलती जुलती हुई आये दिन घटने वाली वे लोक घटनाएं हैं जो कि सतत अनुभूत होने के कारण हमारे हृदयों में समा सी रही हैं। परन्तु वेदव्यास जी ने उक्त कथा के परिणाम को समवेदना तक ही सीमित नहीं रखा है। जब इस लोकभाषा के गांभीर्यगर्भ में कुछ और नीचे डुबकी लगाई जाती है, तो यही समवेदना आत्मग्लानि के रूप में परिवर्तित हो जाती है। **क्रमश: ...**

हंसी से दिल जीतने का वरदान मनुष्य के ही पास

रामवृक्ष बेनीपुरी

मानव-वंश की विशेषताओं में हंसी की भी गिनती होती है। सभी प्राणियों में मनुष्य ही हंसता है, ऐसा लोगों का विश्वास रहा है। यद्यपि इस धारणा का खंडन जगदीशचंद्र बसु के प्रयोगों ने कर दिया है और अब माना जाने लगा है कि जीव-जंतु की क्या बात, पेड़-पौधे भी हंसते हैं। किंतु तो भी मनुष्य की हंसी, उसकी अन्य कई विशेष खूबियों की तरह, कुछ और ही है। उच्च अट्टहास से लेकर मधुर-मुस्कान तक, हास्य की एक ऐसी सरणी उसके जीवन से जुड़ी है कि जब-जब उसकी कल्पना कीजिए, विस्मय विमुग्ध हो जाना पड़ता है! जीव-जंतु के जीवन में भी हास्य की धारा प्रवाहित होती होगी, पेड़-पौधों के रेशों में भी गुदगुदी दौड़ती होगी, मानता हूं। किंतु भी जोरों का ठहाका लगाकर छतों को हिला देना, कभी खिलखिलाहट से सारे कमरे को फूलों की सुवास से भर देना और कभी हल्की मुस्कराहट से किसी के दिल को जीत लेना, यह वरदान तो मनुष्य को ही मिला है।

और, यह वरदान है तो हम मानवों में, जिनमें से कुछ लोगों पर इसकी अजस्र वर्षा की गई, उनमें स्वर्गीय पंडित जगन्नाथप्रसाद चतुर्वेदी का नाम पहली पंक्ति में लिखा जाएगा। जैसी उन्मुक्त हंसी मैंने चतुर्वेदीजी में पाई थी, वैसी हंसी अन्यत्र नहीं मिली। चतुर्वेदीजी को उनके जीवन में 'हास्यरसावतार' की उपाधि हिंदी-संसार ने सर्वसम्मति से दे रखी थी। वह जहां भी रहते, हंसी की फुलझड़ियां छूटती रहतीं। जिस साहित्य-गोष्ठी में वह पहुंच जाते, वहां का सारा वातावरण ही हास्य-रस से ओतप्रोत हो जाता। जहां चतुर्वेदीजी हों, वहां मनहूसियत रह नहीं सकती थी। प्रकृति ने उन्हें ऐसा रूप दिया था, जिस पर हंसी वैसी ही खिलती थी, जैसी कुमुद-वन में शरद की शुभ्र चांदनी खिलती है। गोरा-चिट्टा चेहरा, सजे-संवरे बाल, सिर पर कलंगीदार मुरेठा, पतली भवों के नीचे हंसती हुई आंखें, उन पर सुनहले फ्रेम का चश्मा, काली मूंछें, चमकीले दांत, छोटी ठुड्डी, मैंने 1918 में, जबकि वह बिहार-प्रादेशिक हिंदी साहित्य सम्मेलन के प्रथम अधिवेशन का सभापतित्व कर रहे थे, उन्हें इस रूप में देखा था। सभापति को गंभीर होना चाहिए, यह धारणा तो आज तक बनी हुई है, किंतु जब चतुर्वेदीजी अगणित मालाओं से लदे अपना सभापति का भाषण सुनाने के लिए उठे, और, एक मंद मुस्कराहट से, सोनपुर मेले में ठसाठस भरे विशाल हॉल में दर्शकों की ओर देखा, तो ऐसा लगा कि सबके हृदय को वह तार छू गया, जो आनंद की लहर दौड़ा देता है और जब उन्होंने भाषण शुरू किया, तो भाव-विमुग्ध ही न रहे, बल्कि बीच-बीच में सभा-भवन अट्टहास से गुंजित होता रहा। एक दिन उनकी धर्मपत्नी अपने दोनों बेटों को बड़े प्रेम से खिला रही थीं और वह तालियां बजाकर गा रहे थे-'कल्लू मल्लू दोनों भाई, बैठे प्रेम से खाते हैं। बैठी माता खिला रही है, खड़े पिताजी गाते हैं।।' चतुर्वेदीजी और लोगों को प्रफुल्लित करने के उनके अनेक किस्से हैं। कहने का मतलब यह है, हमारे पूर्वजों की वह उन्मुक्त हंसी और जिंदादिली हमारे जीवन में उतरे और हमारे अनुवर्ती उनका अनुसरण करें, यही हमारी कामना है। मौजूदा दौर में इन्सान के जीवन में इतनी भागदौड़ है कि वह अपनी अलग ही धुन में भागा चला जा रहा है।

क्या चुनाव म्यांमार में शांति ला सकेंगे?

आनंद कुमार

म्यांमार 2021 से भीषण गृहयुद्ध की चपेट में है, जब सैन्य सरकार ने आंग सान सू की को सत्ता से हटा दिया और चुनावों में धांधली का आरोप लगाया था। इसके बाद से देश लगातार संघर्ष का गवाह बना हुआ है, जिसमें सेना, अपदस्थ नागरिक सरकार और विभिन्न जातीय सशस्त्र समूह शामिल हैं। सत्ता को मजबूत करने के सैन्य प्रयासों का कड़ा विरोध हुआ, जिसके परिणामस्वरूप युद्धक्षेत्र में भारी नुकसान और गंभीर मानवाधिकार उल्लंघन के आरोप लगे हैं। अब, सत्ता पर अपनी पकड़ बनाए रखने के अंतिम प्रयास में, जुंटा इस वर्ष जुलाई के बाद किसी समय चुनाव कराने की योजना बना रही है। लेकिन मूल प्रश्न यह है- क्या ये चुनाव म्यांमार में शांति ला पाएंगे?

अंतरराष्ट्रीय दबाव के बावजूद, म्यांमार अब भी गृहयुद्ध में फंसा हुआ है। सत्ता पर कब्जा करने के चार साल बाद भी जुंटा सेना और प्रमुख विपक्षी समूहों के बीच बातचीत की कोई संभावना नहीं दिख रही है। सेना को पीपुल्स डिफेंस फोर्स (पीडीएफ) और जातीय सशस्त्र संगठनों से जबर्दस्त प्रतिरोध का सामना करना पड़ रहा है, जो देश के बड़े हिस्सों पर नियंत्रण रखते हैं। इसके जवाब में, जुंटा ने हवाई हमलों, तोपखाने से बमबारी, जबरन भर्ती और सामूहिक गिरफ्तारियों जैसी दमनकारी रणनीतियों को अपनाया है, जिससे मानवीय संकट और गहरा गया है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) की रिपोर्ट के मुताबिक, अब लगभग आधी आबादी गरीबी में जी रही है और देश की अर्थव्यवस्था चरमरा गई है।

संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोपीय संघ,

ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, दक्षिण कोरिया, न्यूजीलैंड, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड सहित कई देशों ने जुंटा के सत्ता पर कब्जे की निंदा की और आंग सान सू की सहित सभी राजनीतिक कैदियों की रिहाई की मांग की। इन देशों ने म्यांमार में बढ़ते सीमा पार अपराधों, जिनमें नशीली दवाओं की तस्करी, मानव तस्करी और साइबर धोखाधड़ी शामिल हैं, पर भी चिंता व्यक्त की, जो क्षेत्रीय स्थिरता के लिए खतरा हैं। इन देशों के संयुक्त बयान में कहा गया कि म्यांमार की वर्तमान स्थिति अस्थिर है और यह पूरे क्षेत्र को और अस्थिर कर सकती है।

जिस म्यांमार सेना ने तख्तापलट के बाद प्रतिरोध को जल्द खत्म करने की उम्मीद की थी, वह अब मुश्किल स्थिति में फंस गई है। 2021 के तख्तापलट ने राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिए, जो सुरक्षाबलों द्वारा प्रदर्शनकारियों पर हिंसक कार्रवाई के बाद पूर्ण सशस्त्र संघर्ष में बदल गए। आज, सेना म्यांमार के केंद्रीय क्षेत्र और राजधानी नेप्यीडॉ पर नियंत्रण रखती है, जबकि विपक्षी समूह ग्रामीण इलाकों में मजबूत पकड़ बनाए हुए हैं। इस बढ़ते विद्रोह ने सेना को भारी नुकसान पहुंचाया है और उसकी शक्ति को कमजोर कर दिया है।

राजनीतिक बंदियों के लिए सहायता संघ (एएपीपी) के अनुसार, तख्तापलट के बाद से कम से कम 6,239 लोग मारे गए और 28,444 लोगों को गिरफ्तार किया गया। लेकिन माना जाता है कि वास्तविक संख्या इससे कहीं अधिक है। चीन की सीमा से लगे उत्तर-पूर्वी इलाकों और पश्चिमी रखाइन राज्य में जातीय सशस्त्र समूहों ने सैन्य ठिकानों, शहरों और प्रमुख क्षेत्रीय कमानों पर कब्जा कर लिया है। इन सफल अभियानों ने सेना की पकड़ को और कमजोर कर दिया है और विपक्षी ताकतों को और मजबूत किया है। दशकों से जातीय अल्पसंख्यक म्यांमार की केंद्र सरकार से अधिक स्वायत्तता की मांग कर रहे हैं। तख्तापलट के बाद से उन्होंने पीपुल्स डिफेंस फोर्स (पीडीएफ) के साथ गठबंधन कर लिया है और सैन्य शासन के खिलाफ एक मजबूत प्रतिरोध खड़ा कर दिया है।

तेजी से बढ़ते नुकसान को देखते हुए, सैन्य शासन चुनाव कराने की योजना बना रहा है और इस साल कभी भी मतदान कराने का वादा कर रहा है। हालांकि, आलोचकों का कहना है कि मौजूदा दमनकारी माहौल में ये चुनाव न तो स्वतंत्र होंगे और न ही निष्पक्ष। कई प्रमुख विपक्षी नेता, जिनमें आंग सान सू की भी शामिल हैं, अभी भी जेल में हैं, और नागरिक स्वतंत्रता गंभीर रूप से सीमित है। ऐसे में, जुंटा का चुनाव कराने का निर्णय लोकतंत्र बहाल करने का प्रयास नहीं, बल्कि अपनी वैधता स्थापित करने की एक कोशिश प्रतीत होता है। हाल ही में?सैन्य सरकार ने देश में आपातकाल की स्थिति को छह महीने के लिए बढ़ा दिया, यह कहते हुए कि चुनाव से पहले स्थिरता जरूरी है। हालांकि, चुनाव की कोई निश्चित तारीख घोषित नहीं की गई है।

यदि चुनावों से शांति और स्थिरता लानी है, तो इसके लिए कुछ शर्तों का पूरा होना जरूरी है, जैसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, निष्पक्ष राजनीतिक प्रतिस्पर्धा और एक स्वतंत्र चुनाव आयोग। लेकिन म्यांमार में फिलहाल इनमें से कोई भी तत्व मौजूद नहीं है। लाखों विस्थापित नागरिकों और बड़े पैमाने पर विपक्षी नियंत्रण वाले क्षेत्रों को देखते हुए, चुनाव कराने के लिए कई लॉजिस्टिक चुनौतियां भी हैं। यदि प्रमुख विपक्षी दलों और जातीय समूहों को चुनाव प्रक्रिया में शामिल नहीं किया गया, तो सेना द्वारा आयोजित किसी भी चुनाव को न तो अंतरराष्ट्रीय समुदाय मान्यता देगा और न ही म्यांमार की जनता।

बिगड़ते मानवीय संकट और सैन्य शासन की घटती पकड़ के बीच, म्यांमार का भविष्य अत्यधिक अनिश्चित बना हुआ है। माना जा रहा है कि जुंटा द्वारा प्रस्तावित चुनाव शांति स्थापित करने में विफल रहेंगे और देश के गहरे राजनीतिक और जातीय संघर्षों को हल नहीं कर पाएंगे। इसके बजाय, वे विभाजन को और गहरा कर सकते हैं और गृहयुद्ध को लंबा खींच सकते हैं। यदि स्थायी समाधान चाहिए, तो सेना को विपक्षी समूहों और जातीय अल्पसंख्यकों के साथ ईमानदारी से संवाद करना होगा। आसियान, चीन और भारत जैसे क्षेत्रीय खिलाड़ियों को मध्यस्थता में सक्रिय भूमिका निभानी होगी और जुंटा पर हिंसा रोकने का दबाव बनाना होगा। अंतरराष्ट्रीय समुदाय को म्यांमार की जनता के लिए मानवीय सहायता सुनिश्चित करनी होगी। जब तक सेना राजनीतिक सुधार, शक्ति-साझाकरण और लोकतांत्रिक स्वतंत्रता बहाल करने के लिए तैयार नहीं होती, तब तक किसी भी चुनाव से संकट और गहराने की संभावना ही अधिक होगी।

आज का इतिहास

1940 ब्रिटेन में रेलवे का राष्ट्रीयकरण हुआ।
1940 वॉल्ट डिज़्नी एनिमेटेड फिल्म पिनोचियो का प्रीमियर न्यूयॉर्क शहर के एक थियेटर में हुआ।
1943 द्वितीय विश्व युद्ध-जापान ने अपने सैनिकों को सफलतापूर्वक गादुदलकेन से हटा लिया।
1943 अमेरिका में जूतों की राशनिंग प्रणाली लागू की गई।
1959 फिदेल कास्त्रो ने क्यूबा के नये संविधान की घोषणा की।
1974 केंद्रीय अमरीका महाद्वीप में स्थित छोटे देश ग्रेनाडा को स्वतंत्रता मिली।
1986 हैती जीन-क्लाउड ड्यूवेलियर के राष्ट्रपति एक लोकप्रिय विद्रोह के बाद देश से भाग गए, देश में एक परिवार के शासन के 28 साल पूरे हो गए।
1990 सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी ने बहुपक्षीय चुनावों के लिए रास्ता साफ कर, सत्ता के एकाधिकार को समाप्त करने के लिए वोट किया।
1992 यूरोपीय देशों ने नीदरलैंड्स में मैत्री संधि पर हस्ताक्षर किए। इसके बाद ही यूरो मुद्रा का जन्म हुआ।
1995 1993 वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के बम विस्फोट और फिलीपीन एयरलाइंस की उड़ान 434 के मुख्य अपराधियों में से एक, रामजी यूसेफ को पाकिस्तान के इस्लामाबाद में गिरफ्तार किया गया था।
1995 1993 के वर्ल्डट्रेड सेंटर बम विस्फोट और फिलीपीन एयरलाइंस फ्लाइट 434 के मुख्य अपराधियों में से एक, रामजी यूसेफ को इस्लामाबाद, पाकिस्तान में गिरफ्तार किया गया था।
1997 यूएस और रूस ने हेलसिंकी के लिए 20 से 21 मार्च को शिखर सम्मेलन की घोषणा की।
1998 नागानो जापान में 18 वें शीतकालीन ओलंपिक खेल खोले गए।
1999 अब्दुल्ला द्वितीय अपने पिता राजा हुसैन की मृत्यु के बाद जॉर्डन के हाशमाइट राज्य का राजा बन गया।
1999 जॉर्डन के युवराज अब्दुल्ला ने गद्दी सम्भाली।
2001 इस्त्रायल के प्रधानमंत्री एहुद बराक चुनाव में पराजित, एरियल शेरोन नए प्रधानमंत्री बने।

भारत में आर्थिक विकास दर को 8 प्रतिशत से ऊपर ले जाने के प्रयास

प्रह्लाद सबनानी

विश्व के कुछ देशों में सत्ता परिवर्तन के बाद आर्थिक क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण परिवर्तन होते हुए दिखाई दे रहे हैं। विशेष रूप से अमेरिका में राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रम्प विभिन्न देशों को लगातार धमकी दे रहे हैं कि वे इन देशों से अमेरिका में होने वाले आयात पर कर की दर में वृद्धि कर देंगे। दिनांक 4 फरवरी 2025 से कनाडा एवं मेक्सिको से अमेरिका में होने वाले उत्पादों के आयात पर 20 प्रतिशत एवं चीन से होने वाले आयात पर 10 प्रतिशत का आयात कर लगा दिया है। वैश्विक स्तर पर उक्त प्रकार की उथल पुथल के अतिरिक्त रूस यूक्रेन युद्ध जारी ही है एवं कुछ समय पूर्व तक हमास इजराईल युद्ध भी चलता ही रहा था। वैश्विक स्तर पर उक्त विपरीत परिस्थितियों के बीच भी भारत, अपनी आर्थिक विकास दर को कायम रखते हुए, विश्व की सबसे तेज गति से आगे बढ़ती अर्थव्यवस्था बना हुआ है। हां, वित्तीय वर्ष 2024-25 की प्रथम दो तिमाहियों में सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि दर गिरकर 5.2 प्रतिशत एवं 5.3 प्रतिशत क्रमशः के आसपास रही है। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भारत को वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया है। यदि भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है तो आगे आने वाले दो दशकों तक आर्थिक विकास दर को 8 प्रतिशत से ऊपर रखना आवश्यक होगा। अतः केंद्र सरकार द्वारा भारत की आर्थिक विकास दर को इस वित्तीय वर्ष की दो तिमाहियों में दर्ज की गई लगभग 5.3 प्रतिशत की आर्थिक विकास दर को 8 प्रतिशत से ऊपर ले जाने के प्रयास किए जा रहे हैं।

अभी हाल ही में केंद्र सरकार की वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारामन ने लोक सभा में वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए केंद्रीय बजट पेश किया है। इस बजट के माध्यम से ऐसे कई निर्णय लिए गए हैं जिससे देश की आर्थिक विकास दर पुनः एक बार 8 प्रतिशत से ऊपर निकल जाए। दरअसल, आज देश में उत्पादों की मांग को बढ़ाना अति आवश्यक है जो पिछले कुछ समय से लगातार कम होती दिखाई दे रही है। इसके लिए आम नागरिकों के हाथों में अधिक धनराशि उपलब्ध रहे, ऐसे प्रयास किए जा रहे हैं। जैसे, आयकर की सीमा को वर्तमान में लागू सीमा 7 लाख रुपए प्रतिवर्ष से बढ़ाकर वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 12 लाख रुपए प्रतिवर्ष कर दिया गया है। साथ ही, आय पर लगने वाले कर की दर को भी बहुत कम कर दिया गया है। इस प्रकार लगभग 1 करोड़ मध्यमवर्गीय करदाताओं को लगभग 1.10 लाख रुपए तक प्रतिवर्ष का अधिकतम लाभ होने जा रहा है। इस राशि से विभिन्न उत्पादों का उपभोग बढ़ेगा एवं देश की आर्थिक विकास दर में तेजी दिखाई देगी। हालांकि इससे केंद्र सरकार के बजट पर एक लाख करोड़ रुपए का भार पड़ेगा। परंतु, फिर भी बजटीय घाटा वित्तीय वर्ष 2024-25 में 5.8 प्रतिशत से घटकर वित्तीय वर्ष 2025-26 में 5.4 प्रतिशत रहने की सम्भावना व्यक्त की गई है। अतः देश की वित्तीय स्थिति को सही दिशा दिए जाने के सफल प्रयास हो रहे हैं।

विनिर्माण के क्षेत्र को गति देना भी आज की आवश्यकता है। राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन भी चलाए जाने का प्रस्ताव है। आज देश में एक करोड़ से अधिक सूक्ष्म, मध्यम एवं लघु उद्योग हैं जो 7.5 करोड़ नागरिकों को रोजगार उपलब्ध कर रहे हैं एवं भारत के कुल उत्पादन में 36 प्रतिशत का योगदान दे रहे हैं तथा देश से होने वाले विभिन्न उत्पादों के निर्यात में भी 45 प्रतिशत की भागीदारी इन उद्योगों की रहती हैं। कुल मिलाकर भारत आज अपनी इन कम्पनियों को वैश्विक स्तर पर ले जाना चाहता है। भारत में आज निर्यात प्रोत्साहन मिशन को चालू किया जा रहा है ताकि भारत की कम्पनियों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिले। इसी प्रकार भारत को वैश्विक स्तर पर खिलौना उत्पादन के केंद्र के रूप में

विकसित किये जाने के प्रयास भी किये जा रहे हैं। केवल एक दशक पूर्व भारत में खिलौनों का शुद्ध आयात होता था आज भारत खिलौनों का शुद्ध निर्यातक देश बन गया है। पिछले 10 वर्षों में भारत में खिलौनों के निर्यात में 200 प्रतिशत की वृद्धि एवं खिलौनों के आयात में 52 प्रतिशत की कमी दर्ज हुई है। भारत ने 15 करोड़ अमेरिकी डॉलर की राशि के खिलौनों का निर्यात किया है।

भारत के सकल घरेलू उत्पाद में पर्यटन क्षेत्र का योगदान लगभग 5 प्रतिशत है। विशेष रूप से वाराणसी, श्री अयोध्या धाम, उज्जैन एवं महाकुम्भ, प्रयागराज में पर्यटकों के लिए विकसित की गई आधारभूत सुविधाओं के बाद इन सभी शहरों की पहचान धार्मिक पर्यटन के केंद्र के रूप में पूरे विश्व में कायम हुई है। आज आध्यात्म की ओर पूरा विश्व ही आकर्षित हो रहा है अतः भारत में अन्य धार्मिक केंद्रों को भी इसी तर्ज पर विकसित किया जाना चाहिए जिससे विभिन्न देशों के नागरिक भी इन धार्मिक स्थलों पर आ सकें एवं जिससे देश के धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिल सके। वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट में पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए 2,541 करोड़ रुपए की राशि का आबंटन किया गया है जबकि वित्तीय वर्ष 2024-25 में 850 करोड़ रुपए की राशि आबंटित की गई थी। भारतीय पर्यटन उद्योग का आकार 25,600 करोड़ अमेरिकी डॉलर का है, जो कि बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। उत्तर पूर्व के राज्यों से लेकर जम्मू एवं कश्मीर तक 50 नए पर्यटन केंद्र विकसित किए जा रहे हैं। यह ऐसे पुराने पर्यटन केंद्र हैं जिनकी पहचान कहीं खो गई है। अब इन पर्यटन केंद्रों पर आधारभूत सुविधाओं को विकसित किये जाने की योजना बनाई जा रही है। इन केंद्रो पर पहुंच को आसान बनाने के उद्देश्य से यातायात के साधनों का विकास किया जाएगा, सर्वसुविधा सम्पन्न होटलों का निर्माण किया जाएगा, एवं इन स्थलों पर अन्य प्रकार की समस्त सुविधाएं पर्यटकों को उपलब्ध कराई जाएंगी। साथ ही, भारत में मेडिकल पर्यटन को भी बढ़ावा दिया जा सकता है क्योंकि विकसित देशों की तुलना में भारत में विभिन्न बीमारियों का उच्चस्तरीय इलाज बहुत ही सस्ते दामों पर उपलब्ध है। और फिर, भारतीय नागरिकों के डीएनए में ही सेवा भावना भरी हुई है, अतः इन देशों के नागरिकों को भारत में इलाज कराने के लिए प्रेरित किया जा सकता है। वैश्विक स्तर पर मेडिकल पर्यटन का आकार 13,700 करोड़ अमेरिकी डॉलर का है। अतः भारत में मेडिकल पर्यटन को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। इससे पर्यटन के क्षेत्र में रोजगार के करोड़ों नए अवसर निर्मित किए जा सकते हैं।

इसी प्रकार भारत में सुरक्षा के क्षेत्र में भी अपार सम्भावनाएं मौजूद हैं। भारत अभी तक अपनी सुरक्षा सम्बंधी आवश्यकताओं के लिए सुरक्षा उपकरणों का बड़ी मात्रा में आयात करता रहा है। परंतु, पिछले कुछ वर्षों में सुरक्षा के क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए चलाए जा रहे अभियान का स्पष्ट असर अब दिखाई देने लगा है और भारत आज मिसाईल सहित कई सुरक्षा उपकरणों का निर्यात करने लगा है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए केंद्र सरकार के बजट में सुरक्षा क्षेत्र के लिए 4.92 लाख करोड़ रुपए की भारी भरकम राशि का आबंटन किया गया है, साथ ही, पूंजीगत खर्चों में भी सुरक्षा क्षेत्र के लिए 2 लाख करोड़ रुपए के बजट का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है। इसी प्रकार, देश में अधोसंरचना को और अधिक मजबूत बनाने के उद्देश्य से पूंजीगत खर्चों को भी 11.20 लाख करोड़ रुपए के स्तर पर रखा गया है। साथ ही, सरकारी उपक्रमों एवं निजी क्षेत्र की कम्पनियां भी अपने पूंजी निवेश को बढ़ाने का प्रयास यदि करती हैं एवं विदेशी कम्पनियों द्वारा किए जाने वाले विदेशी निवेश को मिलाकर पूंजीगत मदों पर खर्चे को 15 लाख करोड़ रुपए की राशि तक ले जाया जा सकता है। इसके लिए देश में ईज आफ डूइंग बिजनेस को अधिक आसान बनाना होगा एवं पुराने कानूनों को हटाकर उद्योग मित्र कानून बनाए जाने की आवश्यकता है।

चूंकि विश्व के कई देशों, विशेष रूप से विकसित देशों, में प्रौढ़ नागरिकों की संख्या लगातार बढ़ रही है अतः इन देशों में युवाओं की संख्या में कमी के चलते विभिन्न संस्थानों में कार्य करने वाले नागरिकों की कमी हो रही है। अतः भारत को पूरे विश्व में कौशल से परिपूर्ण युवाओं के केंद्र के रूप में विकसित किया जा सकता है। जापान, ताईवान, इजराईल, वियतनाम सहित कई विकसित देशों ने तो भारत से कौशल से परिपूर्ण इंजनीयर्स, डॉक्टर एवं नर्सों की मांग भी की है। आज भारत पूरे विश्व को ही कौशल से परिपूर्ण युवाओं को उपलब्ध कराने की क्षमता रखता है। साथ ही, देश में रोजगार के अधिकतम अवसर निर्मित हों, इसके प्रयास भी किए जा रहे हैं। विशेष रूप से रोजगार उन्मुख क्षेत्रों, यथा, कृषि, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों (टेक्स्टायल उद्योग, फूटवेयर उद्योग, खिलोना उद्योग, पर्यटन उद्योग, आदि सहित) एवं सेवा क्षेत्र पर अधिक ध्यान दिया जा रहा है।

अमेरिका में अवैध प्रवास, अब भारत में गंभीर आत्मनिरीक्षण जरूरी

दीपक कुमार शर्मा

प्रधानमंत्री मोदी की संभावित अमेरिकी यात्रा से महज एक हफ्ते पहले डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन द्वारा भारतीय अवैध प्रवासियों के वापसी की प्रक्रिया शुरू करना और कोलंबिया व मेक्सिको के विपरीत भारत द्वारा अमेरिका को पूरा सहयोग देना आप्रवासन नीतियों व अंतरराष्ट्रीय संबंधों में संतुलन का एक आदर्श उदाहरण है, लेकिन यह भारत के लिए?आत्मनिरीक्षण का भी विषय है। अमेरिकी आंकड़े बताते हैं कि 2024 में अवैध ढंग से अमेरिका पहुंचने वाले लोगों में मेक्सिको, वेनेजुएला और ग्वाटेमाला जैसे लैटिन अमेरिकी देशों की तुलना में भारतीयों की तादाद तीन फीसदी ही रही थी, लेकिन इस संख्या का लगातार बढ़ना भी एक तथ्य है। चूंकि भारत अवैध प्रवासन का समर्थन कतई नहीं करता और जैसा विदेश मंत्री पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं, बात सिर्फ अमेरिका की नहीं है, अगर कोई भारतीय नागरिक दुनिया के किसी भी देश में अवैध रूप से रहता हुआ पाया जाता है, तो भारत उसे वापस लाने की प्रक्रिया का समर्थन करता है। ध्यान रखा जाना चाहिए कि यह कोई पहली बार नहीं है, जब अमेरिका से अवैध प्रवासियों को भारत वापस भेजा गया हो। पिछले वर्ष अक्तूबर में करीब सौ लोगों को और 2023-24 में अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे एक हजार से ज्यादा लोगों को भारत भेजा गया था। लेकिन इसके लिए महंगे सैन्य विमान का उपयोग बेशक चौंकाने वाला है। अवैध आप्रवासियों का मुद्दा ट्रंप के चुनावी अभियान में केंद्रीय रहा था, और मुमकिन है कि सैन्य विमानों के इस्तेमाल से वह अपने समर्थकों को खुश करने के साथ यह संदेश भी देना चाह रहे हों कि अमेरिका अवैध प्रवासियों को कितना बड़ा खतरा मानता है। पिछले महीने डोनाल्ड ट्रंप द्वारा अमेरिकी राष्ट्रपति के रूप में पदभार संभालने के बाद, अमेरिका की एजेंसियों ने अवैध प्रवासियों के खिलाफ जो अभियान छेड़ा हुआ है, उसे कठोर कहने वाले भी हैं, लेकिन शायद यही ट्रंप की शैली है। अलबत्ता भारत के नजरिये से यह जरूर एक गंभीर विषय है। अवैध रूप से विदेश जाने के लिए लोग अक्सर लाखों रुपये खर्च कर डंकी रूट या दूसरे खतरनाक रास्तों का उपयोग करते हैं, जो न केवल उनके जीवन के लिए जोखिमपूर्ण है, बल्कि मानव तस्करी जैसे अपराधों को भी बढ़ावा देता है। सवाल उन परिस्थितियों पर भी उठने चाहिए, जिनसे बचने के लिए देश के युवा इतना जोखिम उठाने को तैयार हो जाते हैं। जो वापस आ रहे हैं, उनके सहारे उन माफियाओं तक तो पकड़ बनाई जा सकती है, जो लोगों को अवैध ढंग से दूसरे देशों में भेजने के काम में लिप्त हैं, ताकि देश के युवाओं की ऊर्जा यों बर्बाद होने से रोकी जा सके।

इनोवेशन के लिए अवसर है जेनरेटिव एआइ युद्ध

अशोक गौतम

नब्बे के दशक में, ओएस बाजार में प्रभुत्व के लिए माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल और कुछ अन्य कंपनियों के बीच कड़ा मुकाबला था। अंततः, माइक्रोसॉफ्ट इस दौड़ में आगे निकला, और विंडोज अधिकांश पीसी के लिए डिफॉल्ट ओएस बन गया। एप्पल ने एक खास जगह बनायी, वहीं लिनक्स एंटरप्राइज अन्य उत्साही उपयोगकर्ताओं के बीच लोकप्रिय हुआ। लेकिन यहां महत्वपूर्ण बात यह है कि माइक्रोसॉफ्ट और एप्पल ने केवल ओएस में प्रभुत्व स्थापित नहीं किया, बल्कि उन्होंने एक इकोसिस्टम तैयार किया जिसमें अन्य कंपनियां फल-फूल सकीं।

स्मार्टफोन के आगमन ने एक नये युद्ध क्षेत्र को जन्म दिया, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। माइक्रोसॉफ्ट, गूगल और एप्पल इस नयी दुनिया पर कब्जा करने के लिए संघर्ष कर रहे थे। हालांकि माइक्रोसॉफ्ट ने पीसी में दबदबा बनाये रखा, लेकिन उसका मोबाइल ओएस प्रयास विफल रहा। एप्पल का आइओएस और गूगल का एंड्रॉयड इस स्पेस में विजेता बनकर उभरे। एंड्रॉयड के ओपन-सोर्स नेचर ने कई निर्माताओं और डेवलपर्स को इस प्लेटफॉर्म पर काम करने और नवाचार करने की अनुमति दी, जिससे एक मजबूत इकोसिस्टम बना। जबकि एप्पल ने आइओएस के साथ नियंत्रित इकोसिस्टम बनाया और उपयोगकर्ताओं के बीच वफादारी सुनिश्चित की। यह वही परिदृश्य है, जिसे हम अब जेनरेटिव एआइ के क्षेत्र में देख रहे हैं।

वर्ष 2020 के दशक में, जेनरेटिव एआइ के क्षेत्र में एक समान युद्ध छिड़ा हुआ है। ओपनएआइ (माइक्रोसॉफ्ट के साथ साझेदारी में), गूगल, मेटा और अमेजन सबसे शक्तिशाली एआइ मॉडल और प्लेटफॉर्म विकसित करने की दौड़ में हैं। ये फाउंडेशनल मॉडल- जैसे जीपीटी, जेमिनी, और अन्य- उन ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह हैं जो पिछली तकनीकी क्रांतियों में आधार बने। हालांकि इस बार ओपन-सोर्स खिलाड़ी भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। एस्टेबिलिटी एआइ और हगिंग फेस जैसी संस्थाएं जेनरेटिव एआइ को लोकतांत्रिक बना रही हैं, जिससे छोटी कंपनियां और स्वतंत्र डेवलपर बिना बड़ी टेक कंपनियों पर निर्भर रहे नवाचार कर सकें। यह भूमिका लिनक्स की तरह है, जिसने ओएस युद्ध में एक स्वतंत्र और शक्तिशाली विकल्प प्रदान किया था।

जेनरेटिव एआइ युद्ध की असली कहानी यह नहीं है कि कौन जीतता है, बल्कि यह है कि इसके बाद क्या होगा। जिस तरह ओएस और मोबाइल ओएस युगों में हुआ, उसी तरह यहां भी असली मूल्य इकोसिस्टम में है। जेनरेटिव एआइ सिर्फ एक तकनीक नहीं, एक प्लेटफॉर्म है, और प्लेटफॉर्म हमेशा नवाचार के अवसर बनाते हैं। हम पहले से ही देख रहे हैं कि कैसे स्टार्टअप और स्थापित कंपनियां जेनरेटिव एआइ का उपयोग करके विशिष्ट समस्याओं को हल कर रही हैं। निजीकरण शिक्षा से लेकर एआइ-ड्राइवेन कंटेंट क्रिएशन प्लेटफार्मों तक, संभावनाएं अनंत हैं।

ओएस और मोबाइल ओएस युद्धों ने हमें कुछ महत्वपूर्ण सबक सिखाये, जो आज भी प्रासंगिक हैं। एक, फाउंडेशनल लेयर में कुछ ही विजेता होते हैं- किसी भी तकनीकी बदलाव में आधारभूत स्तर आमतौर पर कुछ बड़े खिलाड़ियों के हाथ में रहता है, क्योंकि इन प्रणालियों को विकसित और बनाये रखना अत्यधिक महंगा और जटिल होता है। दो, इकोसिस्टम नवाचार को बढ़ावा देता है, जबकि फाउंडेशनल खिलाड़ी बड़े लाभ कमाते हैं, वास्तविक नवाचार इकोसिस्टम में होता है। हजारों कंपनियां इस बुनियादी ढांचे पर निर्माण कर सफलता पा सकती हैं। तीन, विशेषज्ञता एप्लिकेशन स्तर पर जीतती है- कंपनियां, जो विशिष्ट समस्याओं का समाधान करने पर ध्यान केंद्रित करती हैं, वे अक्सर सफल होती हैं। ओएस युग में, एडोब और इंट्यूट जैसी सॉफ्टवेयर कंपनियां सफल रहीं। मोबाइल ओएस युग में स्पॉटिफाइ और टिकटॉक जैसी एप्लिकेशन कंपनियां उभर कर आयीं। जेनरेटिव एआइ युग में स्वास्थ्य सेवा, वित्त, और क्रिएटिव इंडस्ट्री के लिए एआइ उपकरण विकसित करने वाले स्टार्टअप महत्वपूर्ण भूमिका निभायेंगे।

जेनरेटिव एआइ युद्ध के अंत में हमें एक ऐसी दुनिया देखने को मिलेगी जहां कुछ कंपनियां फाउंडेशनल एआइ इन्फ्रास्ट्रक्चर को नियंत्रित करेंगी। माइक्रोसॉफ्ट (ओपेन एआइ के माध्यम से), गूगल, और संभवतः एक या दो अन्य कंपनियां इस क्षेत्र में प्रमुख खिलाड़ी बनेंगी, ठीक वैसे ही जैसे माइक्रोसॉफ्ट और एप्पल ने ओएस युग में, और गूगल तथा एप्पल ने मोबाइल ओएस युग में किया था। परंतु यह 'विजेता-ही-सब-कुछ' परिदृश्य नहीं होगा। फाउंडेशनल खिलाड़ी एक समृद्ध इकोसिस्टम को सक्षम करेंगे, जहां एप्लिकेशन, टूल्स और सेवाओं की भरमार होगी। ओपन-सोर्स कंपनियां, जैसे स्टेबिलिटी एआइ और हगिंग फेस, इस नवाचार को और आगे बढ़ायेंगी। जो कंपनियां बिना किसी डर के अवसरों को पहचान, जेनरेटिव एआइ की शक्ति का लाभ उठा और विशिष्ट बाजारों में मूल्य प्रदान करके काम करेंगी, वे बड़ी सफलताएं हासिल करेंगी। अंततः, जेनरेटिव एआइ युद्धों को उन कंपनियों से नहीं आंका जायेगा जिन्होंने सबसे बेहतरीन मॉडल बनाये, बल्कि उनसे आंका जायेगा जिन्होंने इस तकनीक से नवाचार की नयी लहर को जन्म दिया।

शिक्षा पर ट्रम्प की उपेक्षा और पीएम नरेंद्र मोदी से अपेक्षा

आलोक मेहता

अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के सत्ता में आने पर महाशक्ति के प्रभाव से दुनिया में युद्ध रोकने, आर्थिक बदलाव, व्यापार, रोजगार के लिए वीसा आदि पर भारत या अन्य मित्र देशों से संबंधों की बहुत चर्चा हो रही है। लेकिन ट्रम्प शासन द्वारा अमेरिकी शिक्षा मंत्रालय को ही बंद कर देने की तैयारी जैसे क्रांतिकारी बदलाव की बात पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विकसित भारत का सपना साकार करने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने और शैक्षणिक सुविधाओं के विस्तार और कौशल विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता देने का प्रयास कर रहे हैं।

शायद बहुत कम लोगों ने ध्यान दिया कि अपने पूरे चुनाव अभियान के दौरान ट्रम्प संघीय शिक्षा विभाग की निंदा करते नजर आए। अमेरिकी शिक्षा व्यवस्था को बदलने के लिए ट्रम्प ने प्लान पेश किया है। वे कॉलेज की बढ़ती फीस और वामपंथी विचारधारा के प्रचार को रोकने की बात भी कह रहे हैं। ट्रम्प का कहना है कि एक्रिडिटेशन सिस्टम की वजह से कॉलेजों में 'मार्क्सवादी' विचारधारा का बोलबाला है।

एक्रिडिटेशन सिस्टम का काम कॉलेज की गुणवत्ता को मापना है। ट्रम्प मौजूदा एक्रिडिटर्स को हटाकर नए लोगों की भर्ती करना चाहते हैं। नए एक्रिडिटर्स अमेरिकी मूल्यों, अभिव्यक्ति की आजादी और करियर पर ध्यान देंगे। ट्रम्प का मानना है कि इससे कॉलेजों में जवाबदेही बढ़ेगी, खर्चे कम होंगे और सस्ती डिग्री मिल सकेगी।

नई सरकार के गठन पर उन्होंने पूर्व वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट कंपनी की सीईओ और पेशेवर रेसलर लिंडा मैकमोहन को शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी सौंपी है। इसमें कोई

शक नहीं कि शिक्षा क्षेत्र का मैदान जीतना किसी बड़े रेसलिंग के वर्ल्ड चैंपियन से अधिक कठिन चुनौती है।

दूसरी तरफ अमेरिकी शिक्षा संस्थानों में भारत के करीब साढ़े तीन लाख भारतीय छात्रों सहित लगभग 12 लाख विदेशी छात्रों पर होने वाले दूरगामी प्रभाव भी कम महत्वपूर्ण नहीं हैं। अमेरिका में शिक्षा मुख्य रूप से राज्यों के अधीन है- जिसमें प्रत्येक राज्य अपनी स्कूल प्रणाली का प्रभारी होता है-संघीय सरकार नहीं।

लेकिन डोनाल्ड ट्रम्प की चुनावी जीत माता-पिता, शिक्षकों और शिक्षा विशेषज्ञों के बीच हलचल पैदा कर रही है। डोनाल्ड ट्रम्प ऐसी शिक्षा व्यवस्था लाना चाहते हैं, जहां छात्रों को जल्द से जल्द और कम पैसे में डिग्री हासिल हो सके। ऐसा होने पर कॉलेज की पढ़ाई करना सबके लिए आसान हो जाएगा।

चुनाव अभियान के वादों के बावजूद, संवैधानिक कारणों से अमेरिकी राष्ट्रपति भी किसी मंत्रालय को आसानी से समाप्त नहीं कर सकते। ट्रम्प को कांग्रेस के समर्थन की आवश्यकता होगी। सीनेट में कम से कम 60 सीनेटरों के 'सुपर बहुमत' को उन्मूलन के पक्ष में मतदान करना होगा। रिपब्लिकन के पास वर्तमान में 53 सीटों का बहुमत है, इसलिए उन्हें डेमोक्रेट्स के वोटों की भी आवश्यकता होगी, जो उन्हें मिलने की संभावना कम है। उनका मानना है कि स्टूडेंट्स को देशभक्ति के मूल्यों की शिक्षा भी उपलब्ध कराई जानी चाहिए। ट्रम्प का आरोप रहा है कि अभी स्टूडेंट्स को मार्क्सवादी विचारधारा के तहत शिक्षित किया जा रहा है। ट्रम्प ऐसे कॉलेजों के खिलाफ कार्रवाई भी चाहते हैं, जो समानता के नाम पर नस्लीय भेदभाव करते हैं। वह ऐसे कॉलेजों पर जुर्माना और टैक्स लगाना चाहते हैं।

शिक्षा व्यवस्था में बदलाव के पीछे डोनाल्ड ट्रम्प चाहते हैं कि कॉलेज स्टूडेंट्स को नौकरियां दिलाने में भी मददगार हों। मतलब शिक्षा के बाद रोजगार सुनिश्चित हो। अमेरिकी शिक्षा मंत्रालय शिक्षा से जुड़े अहम फैसले लेता है। ऐसे में इसके बंद होने का सबसे पहला असर यह होगा कि शिक्षा संबंधी सभी निर्णय राज्य व स्थानीय स्तर पर लिए जाने लगेंगे।

हालांकि कुछ हद तक अब भी ऐसा ही होता है, लेकिन इसमें सबसे अहम काम लोन से जुड़ा है। यह काम संघीय शिक्षा मंत्रालय ही करता है। अमेरिकी शिक्षा विभाग 1.6 ट्रिलियन डॉलर के फेडरल स्टूडेंट लोन प्रोग्राम का काम भी देखता है। यही नहीं, वह समय-समय पर कॉलेज व यूनिवर्सिटीज के लिए नियम-कायदे भी बनाता रहता है।

शिक्षा विभाग से मिलने वाले फंड का इस्तेमाल शिक्षण कर्मचारियों को आगे की ट्रेनिंग देने और विशेष जरूरतों वाले छात्रों की मदद करने के लिए भी किया जाता है। ऐसे में इसके बंद होने का असर इन सभी कामों पर भी पड़ेगा। डोनाल्ड ट्रम्प ने एक बार यह भी चिंता जताई थी कि अमेरिकी लोग किसी भी देश की तुलना में एक बच?चे पर तीन गुना अधिक पैसा खर्च करते हैं।

लेकिन फिर भी उनके बच्चों का प्रदर्शन उतना अच्छा नहीं होता। इसी में सुधार लाने के लिए वह ऐसा करना चाहते हैं। इधर भारत में 2014 और 2024 के बीच उच्च शिक्षा के बजट में 78 फीसदी की बढ़ोत्तरी हुई, तो स्कूली शिक्षा का 40 फीसदी बढ़ा है। 2025-26 में बजट में और अधिक खर्च का प्रावधान है।

स्कूलों को अपग्रेड करने के लिए 2022 में प्रधानमंत्री के हाथों लॉन्च पीएम स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया (पीएम एसएचआरआई या पीएम श्री योजना का उद्देश्य 14,500 मौजूदा स्कूलों को नई शिक्षा नीति की मूल कल्पना को साकार करने वाले 'मॉडल स्कूलों' में नए सिरे से विकसित करना है। नई शिक्षा प्रणाली डिग्री-केंद्रित प्रणाली से अब योग्यता पर जोर देने वाली प्रणाली की तरफ बढ़ रही है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है कि 'भारत नवोन्मेष की कुदरती प्रतिभा से संपन्न लोगों का देश है, पर प्रतिभा के पूल को केवल डिग्रियों के आधार पर नहीं आंकना चाहिए। कौशल-आधारित शिक्षा, अनुसंधान और उद्यमिता को बढ़ावा देने की जरूरत है। हमें डिग्री से योग्यता की तरफ ले जाने वाली संस्कृति का निर्माण करना होगा।'

नई शिक्षा नीति का जोर बहुआयामी सीख पर है और रिसर्च की बिना पर हमारे छात्रों और फैकल्टी में तीन गुना इजाफा हुआ है। नीतियों और हमारे संस्थानों के लक्ष्य की दिशा एक है। नई शिक्षा नीति में सरकार और इंडस्ट्री के बीच प्रैक्टिकल एंगेजमेंट पर फोकस से शोधवृत्ति को बढ़ावा मिलेगा और छात्रों को असल जिंदगी की चुनौतियों के लिए तैयार करेगा।

अमेरिका का टैरिफ वॉर भारत के लिए मौका

डॉ. जयंती लाल भण्डारी

हाल ही में जहां एक फरवरी को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने कनाडा और मैक्सिको पर 25 फीसदी और चीन पर 10 फीसदी टैरिफ का ऐलान किया, वहीं 4 फरवरी को चीन ने पलटवार करते हुए अमेरिका पर 15 फीसदी टैरिफ लगा दिया। इसके साथ ही अमेरिका-चीन के बीच ट्रेड वॉर का नया दौर शुरू हो गया है। वस्तुतः चीन, मैक्सिको और कनाडा से अमेरिका को सबसे ज्यादा व्यापार घाटे का सामना करना पड़ता है। ये तीनों

देश अमेरिका के लगभग 670 अरब डॉलर व्यापार घाटे के लिए जिम्मेदार हैं। वर्ष 2023 में अमेरिका को चीन से 317 अरब डॉलर, मैक्सिको से 200 अरब डॉलर और कनाडा से 153 अरब डॉलर का व्यापार घाटा हुआ था जबकि अमेरिका के व्यापार घाटे में भारत की हिस्सेदारी सिर्फ 36 अरब डॉलर रही है। अमेरिका को जिन देशों से सबसे ज्यादा व्यापार घाटा होता है, उस लिस्ट में भारत नौवें क्रम पर है। गौरतलब है कि ट्रम्प भारत की ओर से अमेरिकी प्रोडक्ट पर बहुत ज्यादा टैरिफ लगाने की शिकायत करते हुए भारत पर भी टैरिफ लगाने की धमकी दे चुके हैं। ऐसे में भारत ने भी इस बात को समझा है कि ट्रम्प एक हाथ से लेने व दूसरे हाथ से देने में विश्वास करते हैं अतएव भारत ने ट्रम्प के टैरिफ से बचने के लिए देखते ही देखते अपने यहां कुछ अमेरिकी सामान पर टैरिफ कम करना शुरू कर दिया है। एक फरवरी को पेश वर्ष 2025-26 के बजट में भारत ने अमेरिका से आने वाली वस्तुओं जैसे 1600 सीसी से कम इंजन की मोटरसाइकिल, सैटेलाइट के लिए ग्राउंड इंस्टॉलेशन और सिंथेटिक फ्लेवरिंग एसेंस जैसे कुछ सामानों पर शुल्क घटा दिए हैं। भारत ने स्पष्ट संकेत दिया है कि वह ट्रम्प प्रशासन से शुल्कों के रूप में मिलने वाली किसी चुनौती को टालने के लिए सीमा शुल्कों में एकतरफा कमी के लिए तैयार है। निश्चित रूप से भारत के द्वारा अमेरिका के व्यापक हित में कुछ उत्पादों से शुल्क घटाए जाने से भारत को अमेरिका में निर्यात के अधिक मौके प्राप्त होंगे। भारत में अमेरिकी राजदूत एरिक गारसेटी ने कहा है कि ट्रम्प के आगमन से भारत और अमेरिका के आर्थिक रिश्ते और अधिक मजबूत होंगे। ऐसे में ट्रम्प की आर्थिक चुनौतियों के बीच भी भारत के लिए आर्थिक मौके उभर कर दिखाई दे रहे हैं। खासतौर पर ट्रम्प ने भारतीयों को बड़ी राहत का ऐलान करते हुए कहा कि एच-1 बी वीजा बंद नहीं होगा, क्योंकि इस समय अमेरिका को अच्छे प्रोफेशनल्स की जरूरत है। निस्संदेह ट्रम्प का रुख और ट्रम्प की नीति से भारत के लिए अमेरिका के साथ द्विपक्षीय व्यापार बढ़ाने और अमेरिका के सहयोग से भारत को चीन प्लस वन के रूप में वैश्विक व्यापार में तेजी से उभरने का मौका भी मिल सकता है। चीन में मैन्युफैक्चरिंग करने वाली कई विदेशी कंपनियां भी भारत का रुख कर सकती हैं।

देहरादून, देहरादून जिले का मुख्यालय है जो भारत की राजधानी दिल्ली से 230 किलोमीटर दूर दून घाटी में बसा हुआ है। 9 नवंबर, 2000 को उत्तर प्रदेश राज्य को विभाजित कर जब उत्तराखण्ड राज्य का गठन किया गया था, उस समय इसे उत्तराखण्ड (तब उत्तरांचल) की अंतरिम राजधानी बनाया गया। देहरादून नगर पर्यटन, शिक्षा, स्थापत्य, संस्कृति और प्राकृतिक सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध है। इसका विस्तृत पौराणिक इतिहास है।

प्राकृतिक सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध

देहरादून

दर्शनीय स्थल

तपकेश्वर मंदिर -यह मंदिर सिटी बस स्टैंड से 5.5 कि.मी. की दूरी पर गढ़ी कैंट क्षेत्र में एक छोटी नदी के किनारे बना है। सड़क मार्ग द्वारा यहां आसानी से पहुंचा जा सकता है। यहां एक गुफा में स्थित शिवलिंग पर एक चट्टान से पानी की बूंदें टपकती रहती हैं। शिवरात्रि के पर्व पर आयोजित मेले में लोग बड़ी संख्या में यहां एकत्र होते हैं और यहां स्थित शिव मूर्ति पर श्रद्धा-सुमन अर्पित करते हैं।

मालसी डियर पार्क-देहरादून से 10 कि.मी. की दूरी पर मसूरी के रास्ते में यह एक सुंदर पर्यटन स्थल है जो शिवालिक श्रंखला की तलहटी में स्थित है। मालसी डियर पार्क एक छोटा सा चिड़ियाघर है जहां बच्चों के लिए प्राकृतिक सौंदर्य से घिरा एक पार्क भी विकसित किया गया है। सुंदर वातावरण के कारण यहां ताज़गी का अहसास होता है जिससे यह एक आदर्श दर्शनीय-स्थल और पिकनिक-स्पॉट बन चुका है। सहस्त्रधारा सल्फर मिश्रित पानी का झरना है, जिसका औषधिय महत्व भी है। बाल्दी नदी और यहां की गुफाएं एक रोमांचक दृश्य उत्पन्न करती हैं। बस स्टैंड से 14 कि.मी. की दूर, यहां नियमित बस सेवा और टैक्सियों द्वारा पहुंचा जा सकता है। यह पिकनिक के लिए एक अच्छा स्थान है।

कलंगा स्मारक-देहरादून-सहस्त्रधारा मार्ग पर स्थित यह स्मारक ब्रिटिशों और गोरखाओं के बीच 180 वर्ष पहले हुए युद्ध में बहादुरी की गाथाएं याद दिलाता है। रिसपाना नदी के किनारे पहाड़ी पर 1000 फुट की ऊंचाई पर बना यह स्मारक गढ़वाली शासकों के इतिहास को दर्शाता है।

लक्ष्मण सिद्ध-ऋषिकेश की ओर देहरादून से 12 कि.मी. दूर यह एक प्रसिद्ध मंदिर है। किवदंती है कि एक साधु ने यहां समाधि ली थी। मंदिर तक सुलभता से पहुंच होने के कारण विशेषकर रविवार को यहां बड़ी संख्या में दर्शनार्थी आते हैं।

चन्द्रबदनी- देहरादून-दिल्ली मार्ग पर देहरादून से 7 कि.मी. दूर यह मंदिर चन्द्रबदनी(गौतम कुंड) के लिए प्रसिद्ध है। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस स्थान पर महर्षि गौतम अपनी पत्नी और पुत्री अंजनी के साथ निवास करते थे. इस कारण मंदिर में इनकी पूजा की जाती है। ऐसा कहा जाता है कि स्वर्ग-पुत्री गंगा इसी स्थान पर अवतरित हुई, जो अब गौतम कुंड के नाम से प्रसिद्ध है। प्रत्येक वर्ष श्रद्धालु इस पवित्र कुंड में डुबकी लगाते हैं। मुख्य सड़क से 2 कि.मी. दूर, चारों ओर से शिवालिक पहाड़ियों के मध्य में यह एक सुंदर पर्यटन स्थल है।

साई दरबार-राजपुर रोड पर शहर से 8 कि.मी. की दूरी पर घंटाघर के समीप साई दरबार मंदिर है। इसका बहुत अधिक सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व है तथा देश-विदेश से दर्शनार्थी यहं आते हैं। साईं दरबार के समीप राजपुर रोड पर ही भगवान बुद्ध का बहुत विशाल और भव्य तिब्बती मंदिर है।

रॉबर्स केव (गुच्छुपानी)- पिकनिक के लिए एक आदर्श स्थान रॉबर्स केव सिटी बस स्टैंड से केवल 8 कि.मी. दूर है। हरिद्वार-ऋषिकेश मार्ग पर लच्छीवाला-डोईवाला से 3 कि.मी. और देहरादून से 22 कि.मी. दूर है। सुंदर टूरयावली वाला यह स्थान पिकनिक-स्पॉट है। यहां हरे-भरे स्थान पर फॉरेस्ट रेस्ट हाउस में पर्यटकों के लिए ठहरने की व्यवस्था है।

वन अनुसंधान संस्थान- घंटा से 7 कि.मी. दूर देहरादून-चकराता मोटर-योग्य मार्ग पर स्थित यह संस्थान भारत में सबसे बड़ा फॉरेस्ट-बेस प्रशिक्षण संस्थान है। जो तथा इसमें एक बॉटनिकल म्यूजियम भी है। एफआरआई (देहरादून) से 3 कि.मी. आगे देहरादून-चकराता मार्ग पर 8 कि.मी. की दूरी पर स्थित इंडियन मिलिटरी एकेडमी सेना अधिकारियों के प्रशिक्षण का एक प्रमुख संस्थान है।

तपोवन- देहरादून-राजपुर रोड पर सिटी बस स्टैंड से लगभग 5 कि.मी. दूर स्थित यह स्थान सुंदर दृश्यों से घिरा है। कहावत है कि गुरु द्रोणाचार्य ने इस क्षेत्र में तपस्या की थी।

संतोला देवी मंदिर- देहरादून से लगभग 15 कि.मी. दूर स्थित प्रसिद्ध संतौला देवी मंदिर पहुंचने के लिए बस द्वारा जैतांवाला तक जाकर वहां से पंजाबीवाला तक 2 कि.मी. जीप या किसी हल्के वाहन द्वारा तथा पंजाबीवाला के बाद 2 कि.मी. तक पैदल रास्ते से मंदिर पहुंचा जा सकता है।

इतिहास

देहरादून का इतिहास कई सौ वर्ष पुराना है। देहरादून से 56 किलोमीटर दूर कालसी के पास स्थित शिलालेख से इस पर तीसरी सदी ईसा पूर्व में सम्राट अशोक का अधिकार होने की सूचना मिलती है। देहरादून ने सदा से ही आक्रमणकारियों को आकर्षित किया है। खलीलुल्लाह खान के नेतृत्व में 1654 में इस पर मुगल सेना ने आक्रमण किया था। सिरमोर के राजा सुभाक प्रकाश की सहायता से खान गढ़वा के राजा पृथ्वी शाह को हराने में सफल रहे। गद्दी से अपदस्थ किए गए राजा को इस शर्त पर गद्दी पर आसीन किया गया कि वे नियमित रूप से मुगल बादशाह शाहजहाँ को कर चुकाया करेंगे। इसे 1772 में गुज्जरों ने लूटा था। तत्कालीन राजा ललत शाह जो पृथ्वी शाह के वंशज थे, की पुत्री की शादी गुलाब सिंह नामक गुज्जर से की गई थी। गुलाब सिंह के पुत्र का नियंत्रण देहरादून पर था और उनके वंशज इस समय भी नगर में मिल सकते हैं। गढ़वाल के राजा ललत शाह के पुत्र प्रदुमन शाह के शासन काल में रोहिल्ला नजीब के पोते गुलाम कादिर के नेतृत्व में अफगानों का आक्रमण हुआ। जिसमें उसने गुरू राम राय के अनुयायियों और शिष्यों को मौत के घाट उतार दिया। जिन लोगों ने हिन्दू धर्म त्यागने का निर्णय लिया, उन्हें छोड़ दिया गया। लेकिन अन्य लोगों के साथ बहुत निमर्मतापूर्वक व्यवहार किया गया। सहारनपुर के राज्यपाल और अफगान प्रमुख नजीबुदौल्ला भी देहरादून को अपने अधिकार में करने के उद्देश्य में सफल रहा उसके बाद देहरादून पर गुज्जरों, सिक्खों, राजपूतों और गोरखाओं के लगातार आक्रमण हुए और यह उपजाऊ और सुंदर भूमि शीघ्र ही बंजर स्थल में बदल गई। 1783 में एक सिक्ख प्रमुख बुघेल सिंह ने देहरादून पर आक्रमण किया और बिना किसी बड़े प्रतिरोध के सहजता से इस क्षेत्र को जीत लिया। 1786 में देहरादून पर गुलाम कादिर का आक्रमण हुआ। उसने पहले हरिद्वार को लूटा और फिर देहरादून पर कहर बरपाया। उसने नगर पर आक्रमण किया और उसे जमकर लूटा तथा बाद में देहरादून को बर्बाद कर दिया। 1801 तक अमर सिंह थापा के नेत्वृत्व में गोरखा ने दून घाटी पर आक्रमण किया और उस पर अधिकार कर लिया। 1814 में नालापानी के लिए अमर सिंह थापा के पोते बालभद्र सिंह थापा के नेत्वृत्व में गोरखा और जनरल जिलेस्पी के नेत्वृत्व में ब्रिटिश के बीच युद्ध हुआ। गोरखाओं ने इस लड़ाई में जमकर बराबरी कि और जनरल समेत कई ब्रिटिश सेनाओं को अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ा। इस बीच गोरखाओं को एक असामान्य स्थिति का सामना करना पड़ा और उन्हें नालापानी के किले को छोड़ कर जाना पड़ा। 1815 तक गोरखाओं को हरा कर ब्रिटिश शासन ने इस पूरे क्षेत्र पर अपना अधिकार कर लिया। देहरादून के दो स्मारक प्रसिद्ध हैं। इनमें से एक कलंगा स्मारक का निर्माण ब्रिटिश जनरल गिलेस्पी और उसके अधिकारियों की स्मृति में कराया गया है। दूसरा स्मारक गिलेस्पी से लोहा लेनेवाले कैप्टन बलभद्र सिंह थापा और उनके गोरखा सिपाहियों की स्मृति में बनवाया गया है। कालंगा गढ़ी सहस्त्रधारा सड़क पर स्थित है। घंटा घर से इसकी दूरी 4.5 किलोमीटर है। इसी वर्ष देहरादून तहसील के वर्तमान क्षेत्र को सहारनपुर जिले से जोड़ दिया गया। इसके बाद 1825 में इसे कुमाऊँ मण्डल को हस्तांतरित कर दिया गया। 1828 में अलग-अलग उपायुक्त के प्रभार के अंतर्गत देहरादून और जॉनसार बवार हस्तांतरित कर दिया गया और 1829 में देहरादून जिले को मेरठ खण्ड को हस्तांतरित कर दिया गया। 1842 में देहरादून को सहारनपुर जिले से जोड़ दिया गया और इसे जिलाधीश के अधिनस्थ एक अधिकारी के अधिकार क्षेत्र में रखा गया। 1871 से यह एक अलग जिला है। 1968 में इस जिले को मेरठ खण्ड से अलग करके गढ़वा खण्ड से जोड़ दिया गया।

देहरादून और कुछ महत्वपूर्ण स्थानों के बीच की दूरी

दिल्ली - 240 किमी
यमुनोत्री - 279 किमी
मसूरी - 35 किमी
नैनीताल - 297 किमी
हरिद्वार - 54 किमी
शिमला - 221 किमी
ऋषिकेश - 67 किमी
आगरा - 382 किमी
रुड़की - 43 किमी

रेल: देहरादून उत्तरी रेलवे का एक प्रमुख रेलवे स्टेशन है। यह भारत के लगभग सभी बड़े शहरों से सीधी ट्रेनों से जुड़ा हुआ है। ऐसी कुछ प्रमुख ट्रेनें हैं- हावड़ा-देहरादून एक्सप्रेस, चेन्नई- देहरादून एक्सप्रेस, दिल्ली- देहरादून एक्सप्रेस, बांद्रा-देहरादून एक्सप्रेस, इंदौर- देहरादून एक्सप्रेस आदि।

वायु मार्ग: जॉली ग्रांट एयरपोर्ट देहरादून से 25 से किलोमीटर है। यह दिल्ली एयरपोर्ट से अच्छी तरह से जुड़े हुए हैं। एयर डेक्कन दोनों एयरपोर्टों के बीच प्रतिदिन वायु सेवा संचालित करती है।

जलवायु : देहरादून की जलवायु समशीतोष्ण है। यहां का तापमान 16 से 36 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है जहां शीत का तापमान 2 से 24 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है। देहरादून में औसतन 2073.3 मिलिमीटर वर्षा होती है। अधिकांश वर्षा जून और सितंबर के बीच होती है। अगस्त में सबसे अधिक वर्षा होती है।

नगर के विषय में: राजपुर मार्ग पर या डालनवाला के पुराने आवासीय क्षेत्र में पूर्वी यमुना नहर सड़क से देहरादून शुरु हो जाता है। सड़क के दोनों किनारे स्थित चौड़े बरामदे और सुन्दर ढालदार छतों वाले छोटे बंगले इस शहर की पहचान हैं। इन बंगलों के फलों से लदे हुए पेड़ों वाले बगीचे बरबस ध्यान आकर्षित करते हैं। घण्टाघर से आगे तक फैलाहुआ रंगीन पलटन बाजार यहाँ का सर्वाधिक पुराना और व्यस्त बाजार है। यह बाजार तब अस्तित्व में आया जब 1820 में ब्रिटिश सेना की टुकड़ी को आने की आवश्यकता पड़ी। आज इस बाजार में फल, सब्जियां, सभी प्रकार के कपड़े, तैयार वस्त्र (रेडीमेड गारमेंट्स) जूते और घर में प्रतिदिन काम आने वाली वस्तुयें मिलती हैं। इसके स्टोर माल, राजपुर सड़क तक है जिसके दोनों ओर विश्व के लोकप्रिय उत्पादों के शो रूम हैं। अनेक प्रसिद्ध रेस्तरां भी राजपुर सड़क पर है। कुछ छोटी आवासीय बस्तियाँ जैसे राजपुर, क्लेमेंट टाउन, प्रेमनगर और रायपुर इस शहर के पारंपरिक गौरव हैं।

सड़क मार्ग

देहरादून देश के विभिन्न हिस्सों से सड़क मार्ग से जुड़ा हुआ है और यहां पर किसी भी जगह से बस या टेक्सी से आसानी से पहुंचा जा सकता है। सभी तरह की बसें, (साधारण और लक्जरी) गांधी बस स्टैंड जो दिल्ली बस स्टैंड के नाम से जाना जाता है, यहां से खुलती हैं। यहां पर दो बस स्टैंड हैं। देहरादून और दिल्ली, शिमला और मसूरी के बीच डिलक्स/ सेमी डिलक्स बस सेवा उपलब्ध है। ये बसें क्लेमेंट टाउन के नजदीक स्थित अंतरराज्यीय बस टर्मिनस से चलती हैं। दिल्ली के गांधी रोड बस स्टैंड से एसी डिलक्स बसें (वोल्वो) भी चलती हैं। यह सेवा हाल में ही यूएएसआरटीसी द्वारा शुरू की गई है। आईएसबीटी, देहरादून से मसूरी के लिए हर 15 से 70 मिनट के अंतराल पर बसें चलती हैं। इस सेवा का संचालन यूएएसआरटीसी द्वारा किया जाता है। देहरादून और उसके पड़ोसी केंद्रों के बीच भी नियमित रूप से बस सेवा उपलब्ध है।

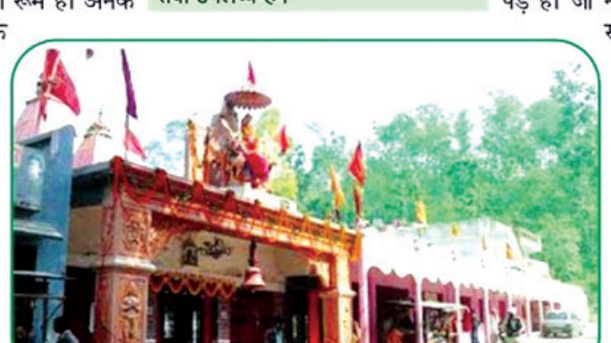

देहरादून के राजपुर मार्ग पर भारत सरकार की दृष्टिबाधितों के लिए स्थापित पहली और एकमात्र राष्ट्रीय स्तर की संस्था राष्ट्रीय दृष्टिबाधित संस्थान (एन.आई.वी.एच.) स्थित है। इसकी स्थापनी 19वीं सदी के नब्बे के दशक में विकलांगों के लिए स्थापित चार संस्थाओं की श्रंखला में हुआ जिसमें राष्ट्रीय दृष्टिबाधित संस्था के लिए देहरादून का चयन किया गया। यहाँ दृष्टिबाधित बच्चों के लिए स्कूल, कॉलेज, छात्रावास, ब्रेल पुस्तास्तलय एवं ध्वन्यांकित पुस्तकों का पुस्तकालय भी स्थापित किया गया है। इसके कर्मचारी इसके अन्दर रहते हैं इसके अतिरिक्त (तेज यादगार) शार्प मेमोरियल नामक निजी संस्था राजपुर में हैं यें दृष्टि अपंगता तथा कानों सम्बन्धि बजाज संस्थान तथा राजपुर सड़क पर दूसरी अन्य संस्थाये बहुत अच्छा कार्य कर रही है। उत्तराखण्ड सरकार का एक और नया केन्द्र है। करूणा विहार, बसन्त विहार में कुछ कार्य शुरू किये है। तथा गहनता से बच्चों के लिये कार्य कर रहें है तथा कुछ नगर के चारों ओर केन्द्र है। देहरादून राफील रेडरचेशायर अंतरराष्ट्रीय केन्द्र है। रिस्पना ब्रिज शायर गृह डालनवाला में हैं। जो मानसिक चुनौतियों के लिए कार्य करते है। मानसिक चुनौतियों के लिए काम करने के अतिरिक्त राफील रेडरचेशायर अंतरराष्ट्रीय केन्द्र ने टी.बी व अधरंग के इलाज के लिये भी अस्पताल बनाया। अधिकाँश संस्थायें भारत और विदेश से स्वेच्छा से आने वालो को आकर्षित तथा प्रोत्साहित करती है। आवश्यकता विहीन का कहना है कि स्वेच्छा से काम करने वाले इन संस्थाओं को ठीक प्रकार से चलाते है। तथा अयोग्य, मानसिक चुनौतियो और कम योग्य वाले लोगो को व्यक्तिगत रूप से चेतना देते है।

देहरादून अपनी पहाड़ियों और ढलानों के साथ-साथ साईकिलिंग का भी एक महत्वपूर्ण स्थान है। चारों ओर पर्वतों और हरियाली से घिरा होने के कारण यहाँ साईकिलिंग करना बहुत सुखद है। लीची देहरादून का पर्यायवाची है क्योंकि यह स्वादिष्ट फल चुनिंदा जलवायु में ही उगता है। देहरादून देश की उन जगहों में से एक है जहाँ लीची उगती है। लीची के अतिरिक्त देहरादून के चारों ओर बेर, नाशपत्ती, अमरूद और आम के पेड़ है। जो नगर की बनावट को घेरे हुये है। ये सारी चीजें घाटी के आकर्षण में वृद्धि करती है। यदि मई माह या जून के शुरू की गर्मियों में भ्रमण के लिये जाएं तो तुम इन फलों को केवल देखेंगे ही नहीं बल्कि खरीदेंगे भी। बासमती चावल की लोकप्रियता देहरादून या भारत में ही नही बल्कि विदेशों में भी है। एक समय अंग्रेज भी देहरादून में रहते थे और वे नगर पर अपना प्रभाव छोड़ गये। उदाहरण के रूप में देहरादून की बैकरीज (बिस्कुट आदि) आज भी यहाँ प्रसिद्ध है। उस समय के अंग्रेजों ने यहाँ के स्थानीय स्टाफ को सेंकना सिखाया। यह निपुणता बहुत अच्छी सिद्ध हुई तथा यह निपुणता अगली संतति सन्तान में भी आयी। फिर भी देहरादून के रहने वालो के लिये यहाँ के स्थानीय रस्क, केक, होट क्रोस बन्स, पेस्टिज और कुकीज मित्रों के लिये सामान्य उपहार है, कोई भी ऐसी नही बनाता जैसे देहरादून में बनती है। दूसरा उपहार जो पर्यटक यहाँ से ले जाते है विख्यात क्वालिटी की टॉफी जोकि क्वालिटी रेस्टोरेन्ट (गुणवत्ता वाली दुकानों) से मिलती हैं। यद्यपि आज बडी संख्या में दूसरी दुकानों (स्टोर) से भी ये टॉफी मिलती है परन्तु असली टॉफी आज भी सर्वोतम है। देहरादून में आनंद के और बहुत से पर्याप्त विकल्प है।

राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय
प्रमुख समाचार

राष्ट्रपति अगले सप्ताह झारखंड की दो दिवसीय यात्रा करेंगी

नईदिल्ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अगले सप्ताह झारखंड की दो दिवसीय यात्रा करेंगी और यहां एक कार्यक्रम में भाग लेंगी। एक अधिकारी ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि राष्ट्रपति 14 फरवरी को रांची पहुंचेंगी और अगले दिन बीआईटी मेसरा के हीरक जयंती समारोह में भाग लेंगी। अधिकारी ने बताया कि संस्थान में शैक्षणिक उत्कृष्टता, शोध और तकनीकी नवाचार के 70 साल पूरे होने का जश्न मनाया जाएगा। रांची के उपायुक्त (डीसी) मंजूनाथ भजंत्री ने बुधवार को राष्ट्रपति के दौरे की तैयारियों की समीक्षा के लिए अधिकारियों के साथ बैठक की। आधिकारिक बयान के अनुसार, उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए। भजंत्री ने अधिकारियों से प्रोटोकॉल के मुताबिक समय पर तैयारियां पूरी करने को कहा। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को हवाई अड्डा, राजभवन और कार्यक्रम स्थल समेत प्रमुख स्थानों पर नोडल अधिकारी एवं सहायक नोडल अधिकारी तैनात करने का भी निर्देश दिया।

रोजाना प्रश्नकाल बाधित करना मतदाताओं का अपमान है: बिरला

नईदिल्ली। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बृहस्पतिवार को सदन में विपक्षी सदस्यों के हंगामे के बाद कहा कि रोजाना प्रश्नकाल में गतिरोध पैदा करना भारत के मतदाताओं का अपमान हैं। विपक्षी सदस्यों ने अमेरिका से ''अवैध'' भारतीय प्रवासियों को वापस भेजे जाने के मुद्दे पर सदन में हंगामा किया। लोकसभा अध्यक्ष ने विपक्षी सदस्यों से नारेबाजी बंद करने और सदन चलने देने की अपील की। उन्होंने कहा, ''नियोजित तरीके से सदन में व्यवधान पैदा करना संसदीय परंपराओं के अनुरूप नहीं है।'' बिरला ने यह भी कहा, ''आपके सारे विषय सरकार ने संज्ञान में लिए हैं। यह विदेश नीति का मामला है। उनकी अपनी नीतियां होती हैं। इस पर सरकार गंभीर है। आपसे आग्रह है कि सदन चलने दें। आप लोग हर रोज प्रश्नकाल में गतिरोध पैदा करके भारतीय मतदाताओं का अपमान कर रहे हैं।''

जयराम ने उठाया यूसीसी से लेकर जनगणना में देरी का मुद्दा

नई दिल्ली। कांग्रेस ने गुरुवार को समान नागरिक संहिता को लागू करने, जनगणना नहीं कराने पर केंद्र सरकार पर हमला बोला। वहीं गाजा के भविष्य को लेकर ट्रंप के फैसले को अस्वीकार्य बताया। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि समान नागरिक संहिता स्थायी ध्रुवीकरण बनाए रखने के लिए राजनीतिक साधन नहीं बन सकता। जनगणना में देरी को लेकर उन्होंने कहा कि इसके शुरू न होने से कई सामाजिक नीतियों और कार्यक्रमों को नुकसान पहुंच रहा है। हाल ही में भाजपा ने उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता को लागू किया गया है। जबकि गुजरात में समान नागरिक संहिता को लागू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त जज की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है। इस पर कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि उत्तराखंड सरकार द्वारा लागू समान नागरिक संहिता (यूसीसी) खराब तरीके से तैयार किया गया कानून है। जो अत्यधिक दखलंदाजी करने वाला है।

चुनाव आयोग मर गया है सफेद कपड़ा भेंट करना होगा

लखनऊ। समाजवादी पार्टी द्वारा भारतीय जनता पार्टी पर उत्तर प्रदेश के मिल्कीपुर उपचुनाव में मतदान को अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करने का आरोप लगाने के एक दिन बाद पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने गुरुवार को कहा कि भाजपा इसी तरह से चुनाव लड़ती है और चुनाव आयोग मृत है। बुधवार को यूपी के पूर्व सीएम ने दावा किया कि पुलिस मतदाताओं के पहचान पत्र की जांच कर रही है। एक्स पर एक पोस्ट में यादव ने चुनाव आयोग से इसमें शामिल लोगों को हटाने के लिए कार्रवाई की मांग की। अखिलेश यादव ने आज कहा कि चुनाव आयोग को इस खबर से जुड़ी तस्वीरों पर तुरंत संज्ञान लेना चाहिए कि अयोध्या पुलिस मिल्कीपुर में मतदाताओं के पहचान पत्र की जांच कर रही है, जिसमें वरिष्ठ पुलिस अधिकारी भी शामिल हैं। यह मतदाताओं में भय पैदा कर मतदान को अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करने का लोकतांत्रिक अपराध है। ऐसे लोगों को तत्काल हटाया जाना चाहिए और दंडात्मक कार्रवाई की जानी चाहिए।

दिल्ली की एग्जिट पोल को संजय राउत ने किया खारिज

मुंबई। शिवसेना (यूबीटी) नेता संजय राउत ने एग्जिट पोल पर कहा कि ये एग्जिट पोल है, असल पोल के नतीजे 8 तारीख को तय होगा। एग्जिट पोल में कहा गया था कि महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी और हरियाणा में कांग्रेस जीत रही है। ये 8 तारीख को पता चलेगा लेकिन हमें पूरा भरोसा है कि भाजपा दिल्ली नहीं जीतेगी। दिल्ली में आम आदमी पार्टी ही रहेगी...भाजपा वाले यहां पैसे बांट रहे थे लेकिन न प्रशासन ने और न ही पुलिस ने कोई कार्रवाई की। भाजपा को भरोसा हो सकता है कि हमने ये सब किया है इसलिए हम जीतेंगे लेकिन जनता ताकतवर है। शिवसेना (यूबीटी) नेता संजय राउत ने एग्जिट पोल पर कहा कि एग्जिट पोल आते-जाते रहते हैं। हमने महाराष्ट्र और हरियाणा के एग्जिट पोल भी देखे, ऐसा लग रहा था कि हम सरकार बनाने जा रहे हैं। 8 फरवरी को सुबह 10 बजे चीजें सब पता चल जाएगा। शिवसेना (यूबीटी) सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि एग्जिट पोल गलत साबित होते हैं।

जो लोग भारत को विश्वगुरु बनाने का सपना दिखा रहे थे, वे चुप क्यों?

अमेरिका से भारतीयों के डिपोर्टेशन पर भड़का विपक्ष

नईदिल्ली। लोकसभा नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव सहित विपक्षी दलों के सांसदों ने अमेरिका से कथित अवैध भारतीय प्रवासियों के निर्वासन के मुद्दे पर संसद के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल, एसपी सांसद धर्मेंद्र यादव, कांग्रेस सांसद गुरजीत सिंह औजला और कुछ अन्य नेताओं को उनके विरोध को चिह्नित करने के लिए हथकड़ी लगाए देखा जा सकता है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि भारतीय नागरिकों को अमेरिका से निर्वासित करते समय अमानवीय व्यवहार किया गया था।

कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि बहुत सी बातें कही गईं कि राष्ट्रपति ट्रंप और पीएम मोदी बहुत अच्छे दोस्त हैं। पीएम मोदी ने ऐसा क्यों होने दिया? क्या हम उन्हें वापस लाने के लिए अपना विमान नहीं भेज सकते थे? क्या इंसानों के साथ ऐसा ही व्यवहार किया जाता है? क्या उन्हें हथकड़ी और बेड़ियां पहनाकर वापस भेजा जाता है? विदेश मंत्री और प्रधानमंत्री को जवाब देना चाहिए। अखिलेश यादव ने कहा कि जो लोग भारत को विश्वगुरु बनाने का सपना दिखा रहे थे, वे अब चुप क्यों हैं?

सपा नेता ने कहा कि भारतीय नागरिकों को गुलामों की तरह हथकड़ी लगाकर और अमानवीय परिस्थितियों में भारत निर्वासित किया जाता है। विदेश मंत्रालय क्या कर रहा है? बच्चों और महिलाओं को इस अपमान से बचाने के लिए सरकार ने क्या किया? हम चाहते हैं कि सरकार इसका जवाब दे और विपक्ष को संसद में इस मुद्दे पर चर्चा करने की अनुमति दे। सीपीआई सांसद पी संदोष कुमार ने कहा कि मेरे सहित राज्य सभा के हम 13 सदस्यों ने नियम 267 के तहत दिन के कामकाज को निलंबित करने और इस मानवीय मुद्दे पर चर्चा करने के लिए एक नोटिस दिया था।

उन्होंने कहा कि यह ट्रंप प्रशासन के अमानवीय रवैये को दर्शाता है। लेकिन हमें सबसे ज्यादा चिंता इस बात की है कि इन लोगों को भारत कैसे पहुंचाया गया। उन सभी को हथकड़ी लगायी गयी और सभी वास्तविक मानवीय अधिकारों से वंचित कर दिया गया। भारत और अमेरिका के बीच राजनयिक संबंध हैं। हमारे लोगों को इस तरह भारत वापस क्यों लाया जाना चाहिए? मानदंड और प्रथाएं हैं, नहीं?

कई विपक्षी सांसदों ने भी सरकार की आलोचना की और उनके साथ किए जा रहे व्यवहार पर सवाल उठाए। कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने कहा कि जिस तरह से भारतीयों को वापस लाया गया, वह सरकार की कमजोरी का प्रमाण है। उन्होंने संसद परिसर में संवाददाताओं से कहा, जिस तरह से महिलाओं के साथ व्यवहार किया गया और उन्हें अपराधियों की तरह हथकड़ी लगाकर वापस लाया गया। हम देश का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री मोदी के लिए देश की प्रतिष्ठा से ज्यादा उनकी व्यक्तिगत छवि महत्वपूर्ण है। यह एक काला दिन है। प्रधानमंत्री चुप हैं।

कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने आश्चर्य जताया कि भारत और अमेरिका के बीच राजनयिक संबंध ऐसी स्थितियों को टालने में क्यों कारगर नहीं हो रहे हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के नेता शशि थरूर ने कहा कि अमेरिका को वहां अवैध रूप से रह रहे लोगों को वापस भेजने का कानूनी अधिकार है, लेकिन जिस तरह से उन्हें वापस भेजा गया, हम उसका विरोध कर रहे हैं। उन्होंने सुझाव दिया कि इस उद्देश्य के लिए नागरिक विमान का इस्तेमाल किया जा सकता था।

संसद में जयशंकर ने प्रवासियों पर दिया जवाब

अवैध रूप से विदेश में रहने वाले नागरिकों को वापस लेना सभी देशों का दायित्व

नईदिल्ली। विरोध के बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर ने राज्यसभा में भारतीयों के निर्वासन मुद्दे पर अपना जवाब दिया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि यह सभी देशों का दायित्व है कि यदि उनके नागरिक विदेश में अवैध रूप से रहते हुए पाए जाते हैं तो उन्हें वापस बुला लें। उन्होंने कहा कि अमेरिका द्वारा निर्वासन का आयोजन और कार्यान्वयन आव्रजन और सीमा शुल्क प्रवर्तन (आईसीई) प्राधिकरण द्वारा किया जाता है। आईसीई द्वारा उपयोग किए जाने वाले विमान द्वारा निर्वासन का एसओपी जो 2012 से प्रभावी है, संयम के उपयोग का प्रावधान करता है। हमें आईसीई द्वारा सूचित किया गया है कि महिलाओं और बच्चों को रोका नहीं जा सकता है।

एस जयशंकर ने कहा कि हम अमेरिकी सरकार से यह सुनिश्चित करने के लिए बातचीत कर रहे हैं कि लौटने वाले निर्वासित लोगों के साथ किसी भी तरह का दुर्व्यवहार न हो। विपक्षी दलों के कई सांसदों ने अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे भारतीयों को वापस भेजने के तरीके को लेकर बृहस्पतिवार को सरकार की आलोचना की तथा प्रवासियों के साथ किए जा रहे व्यवहार पर सवाल उठाए। बुधवार को एक अमेरिकी सैन्य विमान 104 अवैध भारतीय प्रवासियों को लेकर अमृतसर पहुंचा। अवैध प्रवासियों के खिलाफ कार्रवाई के तहत डोनाल्ड ट्रंप सरकार द्वारा निर्वासित भारतीयों का यह पहला जत्था है। निर्वासित लोगों ने दावा किया कि पूरी यात्रा के दौरान उनके हाथ-पैरों में हथकड़ी लगी रही और अमृतसर हवाई अड्डे पर उतरने के बाद ही उन्हें खोला गया।

विदेश मंत्री ने कहा कि हम यह सुनिश्चित करने के लिए अमेरिकी सरकार से संपर्क कर रहे हैं कि निर्वासित लोगों के साथ किसी भी तरह का दुर्व्यवहार न हो। साथ ही, सदन इस बात की सराहना करेगा कि हमारा ध्यान अवैध आप्रवासन उद्योग के खिलाफ कड़ी कार्रवाई पर होना चाहिए। निर्वासित लोगों द्वारा प्रदान की गई जानकारी के आधार पर, कानून प्रवर्तन एजेंसियां एजेंटों और ऐसी एजेंसियों के खिलाफ आवश्यक, निवारक और अनुकरणीय कार्रवाई करेंगी। एस जयशंकर ने कहा कि अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे प्रत्येक लौटने वाले (अमेरिका से निर्वासित भारतीयों) के साथ बैठें और पता लगाएं कि वे अमेरिका कैसे गए, एजेंट कौन था, और हम कैसे सावधानी बरतें ताकि यह जारी न रहे।

उन्होंने कहा कि कानूनी गतिशीलता को प्रोत्साहित करना और अवैध आवाजाही को हतोत्साहित करना हमारे सामूहिक हित में है। यह सभी देशों का दायित्व है कि यदि उनके नागरिक विदेश में अवैध रूप से रहते हुए पाए जाते हैं तो उन्हें वापस बुला लें। निर्वासन की प्रक्रिया कोई नई नहीं है। उन्होंने कहा कि हम जानते हैं कि कल 104 लोग वापस आये। हम ही हैं जिन्होंने उनकी राष्ट्रीयता का सत्यापन किया है। हमें यह नहीं समझना चाहिए कि यह कोई नया मुद्दा है। यह एक ऐसा मुद्दा है जो पहले भी होता रहा है।

जयशंकर ने अमेरिका से अब तक भारत निर्वासित किए गए लोगों के आंकड़े भी सदन के सामने रखे। उन्होंने कहा कि साल 2009 में 734, साल 2010 में 799, साल 2011 में 597, साल 2012 में 530 भारतीयों को निर्वासित किया गया। उन्होंने इस संबंध में 2024 तक के आंकड़े साझा किए।

प्रवासन को लेकर नया कानून लाने की तैयारी में सरकार

अमेरिका से 104 अवैध अप्रवासी भारतीयों को वापस भेजने को लेकर इस समय विपक्ष सरकार के खिलाफ हमलावर है। इस बीच, सरकार ने बताया है कि वह सुरक्षित और व्यवस्थित प्रवासन के लिए नए कानून पर काम कर रही है। प्रवासन पर प्रस्तावित कानून विदेशी गतिशीलता सुविधा और कल्याण विधेयक, 2024 के बारे में सरकार ने यह जानकारी दी है।

यह विधेयक विदेश में रोजगार के लिए सुरक्षित, व्यवस्थित और नियमित प्रवासन को बढ़ावा देगा। इस नए विधेयक के जरिए 1983 के प्रवासन अधिनियम को बदला जाएगा। बता दें कि यह बात कांग्रेस सांसद शशि थरूर की अध्यक्षता वाली विदेश मामलों की संसदीय समिति की रिपोर्ट से सामने आई है। इस रिपोर्ट को सोमवार को संसद में पेश किया गया।

अपनी रिपोर्ट में संसदीय पैनल ने यह भी कहा कि इस विधेयक में उन राज्यों में क्षआश्व (प्रवासियों के संरक्षक) कार्यालयों की स्थापना करने का भी प्रावधान किया गया है, जहां ऐसे कार्यालय वर्तमान में मौजूद नहीं हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि अब तक मुंबई, चेन्नई, दिल्ली, कोलकाता, चंडीगढ़, हैदराबाद, कोचीन, तिरुवनंतपुरम, जयपुर, रायबरेली, पटना, बेंगलुरु, गुवाहाटी और रांची में स्थित प्रोटेक्टर ऑफ इमिग्रेंट्स (पीओई) के 14 कार्यालय हैं। पीओई की पहुंच का विस्तार करने के लिए, मंत्रालय ने पटना, बेंगलुरु और गुवाहाटी में अतिरिक्त पीओई कार्यालय स्थापित किए हैं, जो पूरी तरह कार्यात्मक हैं।रिपोर्ट में कहा गया है कि त्रिपुरा, भुवनेश्वर और अहमदाबाद में अतिरिक्त कार्यालयों की योजना बनाई जा रही है। इसके अलावा, समिति ने आग्रह किया है कि भारत से प्रस्थान करने वाले सभी नागरिकों को आव्रजन काउंटरों पर बुनियादी जानकारी दी जानी चाहिए।

खेल
प्रमुख समाचार

ऑस्ट्रेलिया के मार्कस स्टोयनिस ने लिया वनडे क्रिकेट से संन्यास

सिडनी। ऑस्ट्रेलिया के स्टार ऑलराउंडर मार्कस स्टोइनिस ने अचानक वनडे क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर सबको चौंका दिया है। स्टोइनिस का नाम आगामी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए ऑस्ट्रेलिया के स्क्वॉड में था, लेकिन अब उनके रिटायरमेंट के फैसले के बाद ऑस्ट्रेलिया को स्क्वॉड में बदलाव करना होगा। स्टोइनिस के संन्यास से ये अटकलें लगाई जा रही हैं कि ऑस्ट्रेलियाई खेमे में कुछ ठीक नहीं चल रहा है। स्टोइनिस ने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए स्क्वॉड में नाम होने के बावजूद अचानक संन्यास की घोषणा की है। उनका कहना है कि वह टी20 क्रिकेट पर अपना ध्यान केंद्रीत करना चाहते हैं।

ऑस्ट्रेलिया के इस हरफनमौला ने 2015 में डेब्यू किया था जिसके बाद उन्होंने 71 वनडे मैच खेले। जिसमें उन्होंने 1495 रन बनाने के साथ-साथ 48 विकेट भी चटकाए हैं।

इस दौरान स्टोइनिस ने कहा कि, ऑस्ट्रेलिया के लिए वनडे क्रिकेट खेलना एक अविश्वसनीय यात्रा रही है। और मैं हरे और सुनहरे रंग के मैदान में बिताए हर पल के लिए आभारी हूं। उच्चतम स्तर पर अपने देश का प्रतिनिधित्व करना कुछ ऐसा है जिसे मैं हमेशा संजो कर रखूंगा। ये एक आसान निर्णय नहीं था, लेकन मेरा मानना है कि मेरे लिए वनडे से दूर रहने और अपने करियर के अगले अध्याय पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करने का यही सही समय है। रॉन यानी एंड्रयू मैकडॉनल्ड के साथ मेरा बेहतरीन रिश्ता है और मैं उनके समर्थन की बहुत सराहना करता हूं। बता दें कि, स्टोइनिस ने अपने करियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 2017 में ऑकलैंड में न्यूजीलैंड के खिलाफ 146 रनों की नाबाद पारी खेलकर किया। उन्होंने आखिरी बार पिछले नंवबर में पाकिस्तान के दौरे पर हिस्सा लिया था। स्टोइनिस 2023 में ऑस्ट्रेलिया की वर्ल्ड कप विजेता टीम का भी हिस्सा थे और 2018-19 में टीम के लिए वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर थे।

आर्थिक/वाणिज्य/विज्ञान/
प्रमुख समाचार

सेंसेक्स 213 अंक टूटा निफ्टी 23,650 के नीचे बंद

नईदिल्ली। वैश्विक बाजारों से मिलेजुले रुख के बीच घरेलू शेयर बाजार गुरुवार (6 फरवरी) को लगातार दूसरे ट्रेडिंग सेशन में गिरावट में बंद हुए। देसी कंपनियों के दिसंबर तिमाही के नतीजे उम्मीद से कमजोर रहने से बाजार के सेंटीमेंट पर नेगेटिव असर पड़ा। साथ ही आरबीआई के ब्याज दरों पर फैसले से पहले निवेशक सतर्क रुख अपना रहे हैं। तीस शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स गुरुवार (6 फरवरी) को 200 से ज्यादा अंक चढ़कर 78,513 अंक पर खुला। कारोबार के दौरान यह 77,843 अंक तक फिसल गया था। अंत में सेंसेक्स 213 अंक या 0.27% की गिरावट लेकर 78,058 पर बंद हुआ। इसी तरह नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी50 भी गिरावट में रहा। यह 92.95 अंक या -0.39% गिरावट के साथ 23,603 पर क्लोज हुआ। अदाणी पोर्ट्स, इंफोसिस, एक्सिस बैंक, एचसीएल टेक्नोलॉजीज, टेक महिंद्रा और इंडसइंड बैंक लाभ में रहे।

आरबीआई कर सकता है रेपो रेट में 25 बीपीएस की कटौती

नई दिल्ली। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) 7 फरवरी को मौद्रिक नीति घोषणा के दौरान पांच साल के अंतराल के बाद पहली बार रेपो दर में 25 आधार अंकों (बीपीएस) की कटौती का एलान कर सकता है। बैंक ऑफ बड़ौदा की एक रिपोर्ट में यह बात कही गई है। मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की तीन दिवसीय बैठक फिलहाल जारी है। आरबीआई के नए गवर्नर संजय मल्होत्रा शुक्रवार को पहली बार एमपीसी के फैसले का एलान करेंगे। रिपोर्ट के अनुसार मुद्रास्फीति, जिसपर फोकस मौद्रिक नीति के केंद्र में है, में नरमी के संकेत दिख हैं, इसलिए केंद्रीय बैंक के पास दर कटौती का मौका है। रिपोर्ट में कहा गया है, सभी मैक्रो और भू-राजनीतिक कारकों को देखते हुए आरबीआई की ओर से नीतिगत ब्याज दरों खासकर रेपो रेट में 25 आधार अंकों की कटौती की गुंजाइश बनी हुई है।

जनवरी में वेडिंग सीजन ने ऑटो इंडस्ट्री की बढ़ाई रौनक

नईदिल्ली। देश में गाड़ियों की रिटेल सेल्स जनवरी 2025 में सालाना 7% बढ़कर 22,91,621 यूनिट्स पर पहुंच गई। फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन (फाडा) ने गुरुवार को ये जानकारी दी। जनवरी 2024 में ये सेल्स 21,49,117 यूनिट्स रही थी। फाडा के अध्यक्ष सी. एस. विग्नेश्वर ने कहा, हमारे ऑब्जर्वेशन के मुताबिक हर वाहन सेगमेंट जैसे 2-व्हीलर, 3-व्हीलर, पैसेंजर व्हीकल, ट्रैक्टर और कमर्शियल व्हीकल्स में पॉजिटिव ग्रोथ देखने को मिली है। इससे उपभोक्ताओं के बढ़ते कॉन्फिडेंस और स्थिर मार्केट रिकवरी का संकेत मिलता है। पैसेंजर व्हीकल्स की खुदरा बिक्री जनवरी में सालाना आधार पर 16% बढ़कर 4,65,920 यूनिट्स पर पहुंच गई। विग्नेश्वर ने बताया कि कई डीलरों ने मांग बढ़ने और पिछले साल की भारी छूट का जिक्र किया है, जिससे पुराने मॉडल्स को बेचने और पंजीकरण ट्रांसफर करने में मदद मिली।

तीसरी तिमाही के बाद टाइटन पर ब्रोकरेज बुलिश

नईदिल्ली। टाटा ग्रुप की 'जेम्स' कही जाने वाली टाइटन कंपनी के स्टॉक में आगे अच्छा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। दिसंबर तिमाही (Q3FY25) के नतीजों के बाद ज्यादातर ब्रोकरेज फर्म स्टॉक पर बुलिश हैं। उनका कहना है कि ज्वेलरी सेगमेंट से अच्छी ग्रोथ रही। हालांकि मार्जिन स्टेबल रहा है। दिसंबर तिमाही में कंपनी का नेट प्रॉफिट स्थिर रहा। जबकि, रेवेन्यू में 25.2 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज की गई। गुरुवार (6 फरवरी) के कारोबार में टाइटन के शेयर में शुरुआती कारोबार में 1 फीसदी से ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई। ब्रोकरेज फर्म एंटिक स्टॉक ब्रोकिंग ने टाइटन पर BUY रेटिंग बरकरार रखी है। हालांकि टारगेट प्राइस 4,598 रुपये से घटाकर 4,184 रुपये कर दिया है। 5 फरवरी 2025 को शेयर 3490 पर बंद हुआ था।

ट्रंप के व्यापार युद्ध का असर पूरी दुनिया पर

अनिल त्रिगुणायत

जैसी कि आशंका थी, दूसरी बार सत्ता में आते ही डोनाल्ड ट्रंप ने चीन, कनाडा और मेक्सिको के खिलाफ शुल्क युद्ध छेड़ दिया है। ट्रंप का कहना है कि यह कदम अवैध प्रवासन और ड्रग्स तस्करी से उपजी चिंताओं को लेकर उठाया गया है। ट्रंप ने अपने चुनाव अभियान में भी मुख्य रूप से इन दोनों मुद्दों को उठाया था। यही नहीं, चुनाव में जीत दर्ज करने के बाद से ही इन वादों को पूरा करने की दिशा में कदम उठाने का संकेत ट्रंप दे रहे थे।

गौरतलब है कि अपने पहले राष्ट्रपति काल में भी ट्रंप ने चीन के साथ दो साल का व्यापार युद्ध शुरू किया था। तब दोनों देशों ने एक दूसरे के अरबों डॉलरों के सामान पर शुल्क लगाये थे, जिससे वैश्विक आपूर्ति प्रभावित हुई थी और विश्व अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा था। ट्रंप प्रशासन ने चीनी उत्पादों पर 10 प्रतिशत शुल्क लगाया है। उसने मेक्सिको और कनाडा से आयातित उत्पादों पर 25 प्रतिशत व्यापार शुल्क लगाने की घोषणा की थी, हालांकि कनाडा के ऊर्जा संसाधनों पर उसने 10 प्रतिशत शुल्क लगाने का ही एलान किया था। मेक्सिको और कनाडा ने भी अमेरिकी व्यापार शुल्क के बदले में जवाबी शुल्क लगाने की घोषणा की थी।

अमेरिका द्वारा चीनी उत्पादों पर शुल्क लगाने के जवाब में चीन ने भी कई अमेरिकी उत्पादों पर 15 फीसदी जवाबी शुल्क लगाने की घोषणा की, जो 10 फरवरी से प्रभावी होगा। साथ ही, उसने अमेरिकी सर्च इंजन गूगल की जांच की भी बात कही। चीन की ओर से कहा गया है कि अमेरिका का एकतरफा शुल्क बढ़ाना विश्व व्यापार संगठन के नियमों का उल्लंघन है। उसने यह भी कहा है कि ट्रंप प्रशासन का यह कदम समस्याओं का हल करने में कोई मदद नहीं करेगा। इसके बजाय यह चीन और अमेरिका के बीच सामान्य आर्थिक और व्यापार सहयोग को नुकसान पहुंचायेगा।

हालांकि कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन त्रुदो और मेक्सिको की राष्ट्रपति क्लाउडिया शिनबाम के साथ अलग-अलग बातचीत में ट्रंप ने इन दोनों देशों पर शुल्क लगाये जाने के फैसले को लागू करने पर कम से कम एक महीने की रोक लगाने पर सहमति जतायी है। जबकि चीन पर लगाया गया व्यापार शुल्क मंगलवार से लागू हो गया है। हालांकि ट्रंप ने अगले कुछ दिनों में चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग के साथ बातचीत करने की योजना बनायी है। ट्रंप की इस पहल से विश्व स्तर पर आर्थिक अस्थिरता का एक नया दौर शुरू हो गया है।

'अमेरिका प्रथम' की नीति के साथ शुरू हुआ यह युद्ध विश्व व्यापार को नया रूप देने जा रहा है और उद्योगों तथा सरकारों को अपनी व्यापार रणनीतियों के बारे में फिर से सोचने पर मजबूर कर दे रहा है। इसका परिणाम चाहे जो भी हो, लेकिन तात्कालिक तौर पर इससे आयात लागत में वृद्धि होगी, आपूर्ति श्रृंखला में रुकावट आयेगी और बहुराष्ट्रीय कारोबार में अनिश्चय की स्थिति उत्पन्न होगी। वैश्विक शेयर बाजार तो ट्रंप के इस कदम से वैसे भी हिल गये हैं। मजबूत घरेलू बाजार होने के कारण अमेरिका पर भले ही इस व्यापार युद्ध का असर न पड़े, लेकिन कनाडा और मेक्सिको जैसे देशों को, जहां जीडीपी में कारोबार की हिस्सेदारी लगभग 70 प्रतिशत तक है, इससे काफी नुकसान उठाना पड़ सकता है। यही नहीं, मेक्सिको पर थोपे जाने वाले शुल्क का असर कमोबेश पूरे लैटिन अमेरिका में फैल सकता है। और शुरुआती स्तर पर भले ही अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर इसका असर न पड़े, लेकिन दीर्घावधि में ट्रंप की इस आक्रामकता का असर अमेरिकी बाजारों पर निश्चित रूप से पड़ेगा और उसे नुकसान होगा।

जहां तक चीन की बात है, तो वह 120 से भी अधिक देशों के लिए प्रमुख व्यापार भागीदार है और अमेरिका उनमें से सिर्फ एक है। इसके अलावा बार-बार व्यापार युद्ध का सामना करते रहने के कारण अब चीन ने जीडीपी में आयात-निर्यात की हिस्सेदारी बहुत कम कर दी है।

भाजपा
म हे मोर विश्वास
हर नगर म हो ही विकास

स्वास्थ्य

- हर निगम क्षेत्र में सिकल सेल एनीमिया **स्क्रीनिंग केंद्र और सभी मरीज़ों को पहचान पत्र जारी।**

आवास

- **PMAY-U के 3 लाख घर** तेजी से पूरे होंगे, बिजली बिल और समेकित कर पटाने वालों को **आवास बनाने की पात्रता।**

राजस्व

- नजूल भूमि के लिए नया कानून, सभी पट्टा धारकों को **भू-स्वामी बनाएंगे।**
- महिलाओं को प्रॉपर्टी टैक्स पर **25% छूट,** समय पर भुगतान पर **10% अतिरिक्त छूट।**
- हर नगर निकाय के व्यावसायिक केंद्रों में **बिजली-पानी-सड़क जैसी मूलभूत** सुविधाओं की गारंटी।
- समाधान योजना से बिना जुर्माना या ब्याज लगाए **पुराने संपत्ति कर के लिए एकमुश्त निपटान।**

शहरी विकास

- **स्ट्रीट वेंडर्स सशक्तिकरण** के लिए पीएम स्वनिधि के माध्यम से **₹30,000** तक की सहायता। स्मार्ट वेंडिंग जोन, फूड स्ट्रीट्स की स्थापना ।
- शासकीय जगहों पर **सुव्यवस्थित पार्किंग** का निर्माण।

अटल
विश्वास पत्र
नगरीय निकाय चुनाव 2025

हमने बनाया है
हम ही संवारेंगे

महिला

- विद्यालयों और महाविद्यालयों में छात्राओं को **फ्री सैनिटरी नैपकिन।**
- महतारी वंदन योजना के SHG लाभार्थियों को **₹2.5 लाख तक का ऋण एवं बर्तन बैंक** की स्थापना।

युवा एवं शिक्षा

- महापौर सम्मान निधि से यू.पी.एस.सी. मुख्य परीक्षा (MAINS) **उत्तीर्ण छात्रों को ₹1 लाख।**
- विद्यालयों और महाविद्यालयों में **फ्री वाई-फाई।**
- नालंदा परिसर पर आधारित **सार्वजनिक अध्ययन केंद्र** खुलेंगे और पुस्तकालयों में सीटें बढ़ेंगी।

स्वच्छता

- बाजार क्षेत्रों में महिलाओं के लिए **पिंक टॉयलेट की व्यवस्था।**
- हर घर को मिलेगा **कचरा बाल्टी, रात्रिकालीन सफाई और स्मार्ट वेस्ट मॉनिटरिंग सिस्टम** का निर्माण।
- तालाब के लिए **प्रभावी प्रणाली स्थापना, एस.टी.पी.** से जोड़ना ।

सेवा क्षेत्र

- **'माई सिटी ऐप'** से सभी सेवाएं एक क्लिक पर।

संस्कृति

- गोवंश संरक्षण और देखभाल के लिए **गोकुल नगर का विस्तार।**

जल

- हर घर को **स्वच्छ पानी** और नए जल टैंक निर्माण व कुओं का संरक्षण।

पूरा मेनिफेस्टो पढ़ने के लिए स्कैन करें

कमल का बटन दबाएं • **भाजपा को विजयी बनाएं**

भारतीय जनता पार्टी, छत्तीसगढ

आर.एन.आई.रजि. क्र. CHHHIN/2021/80529, स्वत्वाधिकारी, मुद्रक एवं प्रकाशक- शशांक शर्मा द्वारा मिशन मीडिया प्रा. लि., प्रेस कॉम्प्लेक्स, रजबंधा मैदान, रायपुर (छ.ग.) 492001 से मुद्रित एवं 29/1110, सेवती स्मृति, आजाद चौक, रायपुर (छ.ग.) 492001 से प्रकाशित। संपादक-शशांक शर्मा, मो. 94255-20531.